12.07 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
THIRTEENTH REPORT

The Minister of Parliamentary affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I beg to move the following:

"That this House agrees with the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 22nd February, 1963."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 22nd February, 1963."

The motion was adopted.

12.07½ hrs

MOTION ON ADDRESS BY THE PRESIDENT—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri R. S. Pandey and seconded by Dr. K. L. Rao on the 20th February, 1963, namely:—

"That an Address be presented to the President in the following terms:—

"That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 18th February, 1963.'"

and also further consideration of amendments moved on the 20th February, 1963. Shri Braj Raj Singh is to continue his speech.

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि चीन को हमने भाई बनाया और भाई-भाई का नारा लगाया। चीन ने भी पंचशील के सिद्धान्तों को माना और उसके बाद भी हमला किया और एक बड़ा धोखा हमारी सरकार को हुआ। उस धोखे से सरकार को सबक लेना चाहिये था। कई बार कहा भी गया है कि हमें सोते हुए पकड़ा गया किन्तु अब हमारी आंखें खुल गई हैं। परन्तु देखने को यह मिला है कि हम एक नया भ्रम अपने मन में उत्पन्न कर रहे हैं यह भ्रम कि शायद कम्युनिज्म में कोई दो गुट बन गये हैं। एक गुट चाहे भले ही हमारा विरोध करे और हम पर हमला करे परन्तु दूसरा गुट अभी हमसे भाई चारा निभाने के लिए तैयार है। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए कम्युनिस्ट भाई हमारे देश और उस नये गुट के बीच में एक दलाली कर रहे हैं। एक भाईचारा और एक रिश्ता पैदा करने की बात कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि जब हमने चीन को भाई बनाया और वहां से हमें धोखा मिला उधर रूस बराबर कह रहा है कि हिन्दुस्तान हमारा दोस्त जरूर है परन्तु चीन हमारा भाई है, मौका आने पर हम भाई की मदद करेंगे। परन्तु फिर भी ऐसा नशा सा हमारे ऊपर तारी हो चुका है कि हम उसके मना करने के बावजूद भी इस बात की जिद में लगे हुए हैं कि हम उसको भाई बना कर ही छोड़ेंगे और हमारे इस देश के उन्हीं के पैदा किये हुए कम्युनिस्ट उस बीच में दलाली कर रहे हैं। हमारी सरकार उन्हें दलाली के पैसे भी देती है कीमत भी दलाली की अच्छी देती है। उनको वह बतलाती है कि यह सेंट परसेंट नेशनलिस्ट्स हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार पहले एक गुट को भाई बना कर धोखा खाया, अब इस आशा पर कि उन दोनों गुटों में आपस में मतभेद हो गया है, दूसर गुट की तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाया जा रहा है। ईश्वर जाने क्या होने

[श्री बृजराज सिंह]

वाला है हमारे इस देश का यदि उस दूसरे भाई ने भी हमें वही चपत लगाई जो कि पहले भाई ने लगायी थी। इतना बड़ा इलाका तो एक भाई ले गया। ईश्वर जाने कि यह दूसरा भाई कितना बड़ा इलाका लेकर हमको चपत लगाने वाला है।

यह चाल चली जा रही है कम्यूनिस्टों के उन दलालों की तरफ से, जो कि आज भारतवर्ष में मौजूद हैं और हमारी रूलिंग पार्टी के अन्दर भी जिनका प्रवेश हो चुका है।

श्री त्यागी (देहरादून) : नहीं।

श्री बृजराज सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी दुनिया उनके बर्बरतापूर्ण ढंग को जान गई है, उनके अमानुषिक तरीकों को जान गई है, परन्तु यह दावा करते हुए भी कि हमारी आंखें खुल गई हैं, हमारी सरकार को उनकी बर्बरता का ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हज जाने वाले हर एक यात्री के प्रति कुछ श्रद्धा पैदा होती है, परन्तु जब नौ सौ चूहे खाने के बाद कोई बिल्ली हज करने के लिए चले, तो एक सन्देह अवश्य उत्पन्न होता है। किन्तु हम देखते हैं कि हमारी सरकार के मन में कोई सन्देह उस बिल्ली के प्रति भी नहीं है, जो कि नौ सौ चूहे खाकर हज करने जा रही है। हमारी सरकार अभी भी यह आशा लगाये बैठी है कि जो भाई-चारा चीन से टूट गया है, वह रूस से स्थापित हो जायेगा।

अभी पिछले दिन कांग्रेस के हमारे एक साथी, श्री ब्रह्म प्रकाश जी ने, एक आरोप लगाया। उनकी जानकारी के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस सा है। उन्होंने कहा कि कम्यूनिस्टों से टक्कर लेने, कम्यूनिस्टों का मुकाबला करने या वर्ल्ड कम्यूनिज्मका मुकाबला करने का नारा अब पुराना हो चुका है और अब इस नारे में कोई तथ्य नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि अब कम्यूनिज्म से हमें कोई खतरा बाकी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा खतरा तो हमें जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी से है। हम उनकी विद्वत्ता की कहां तक कद्र करें? हमें तो अफसोस होता है।

आज मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं और इस हाउस को याद दिला दूं कि हमारी पार्टी कहीं बाहर से प्रेरणा लेने वाली पार्टी नहीं है। यह उस महा पुरुष से प्रेरणा लेने वाली पार्टी है जिसने भारत की अखंडता के लिए हमारे बड़े से बड़े नेता से कन्धा मिला कर एक आदर्श स्थापित किया जिसने काश्मीर के मसले पर अपनी जान की बाजी लगाई और अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अखंडता के सिद्धान्त को कायम किया। हम सदा उसी से प्रेरणा लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। भारत की अखंडता हमारा मुख्य उद्देश्य है।

परन्तु हमारे कुछ मित्रों को इससे सब्र नहीं होता। कांग्रेस को तो आज चाहिए हीरो-वरशिप। आज तो उसको उन लोगों से प्रसन्नता होती है जो कि नेहरू जी के नाम पर दुआयें देते रहते हैं। वे कुछ भी करें उनके कारनामों को देखने वाला कोई नहीं है। उनके लिये एक पासवर्ड मौजूद है कि हम नेहरू सरकार के साथ हैं। उस पासवर्ड का इस्तेमाल कर चाहे वे मिनिस्टरों में फूट डालने की कोशिश करें और मिनिस्टरों पर कीचड़ उछालने और उनको बदनाम करने की कोशिश करें, देश में फूट डालने का प्रयत्न करें वह सब क्षम्य है।

श्री त्यागी : नेहरू का मतलब है कांग्रेस गवर्नमेंट।

श्री बृजराज सिंह : तो क्या यह समझा जाय कि जो बाकी के मिनिस्टर हैं, उनका मतलब कोई दूसरी सरकार है?

श्री ब्रह्मप्रकाश ने यदि कोई तर्कशुद्ध बात कही, तो केवल एक और वह यह कि नई दिल्ली में इमर्जेन्सी का कुछ असर नहीं हुआ। यह बात तो आपोज़ीशन ने भी चिल्ला चिल्ला कर कही है। माननीय सदस्य ने भी कही है, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। यह खुशी की बात है कि उन्होंने यह बात कहने की हिम्मत की। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस की ज़िम्मेदारी आपोज़ीशन पर है। क्या सरकार की अपनी कमियों के लिए आपोज़ीशन ज़िम्मेदार है? वास्तव में इस बात पर सरकार की गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिए और उसको अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखना चाहिए। अगर नई दिल्ली में इमर्जेन्सी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो यह ज़िम्मेदारी सरकार की है और उसको इस बारे में उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि कांग्रेस संगठन पर यह ज़िम्मेदारी है और उसने इस ज़िम्मेदारी को कई दफ़ा निभाया भी है। मैं समझता हूं कि पिछले सुरक्षा मन्त्री को अपने पद से हटाने का श्रेय कांग्रेस संगठन को है। उसने यह अनुभव करके कि उनकी जरूरत नहीं है हिम्मत करके उनको हटा दिया। अगर आज नई दिल्ली में इमर्जेन्सी का कोई असर नहीं है, तो यह उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी सरकार पर प्रेशर डाले और उसको मजबूर करे कि वह ऐसे कदम उठाए, जिससे दुनिया और देश को मालूम हो कि इमर्जेन्सी का कुछ असर नई दिल्ली पर पड़ा है। सम्भव है कि अन्दरूनीतौर पर वह असर हो, लेकिन जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ईमानदार है, यही काफी नहीं है। दुनिया को, भारतवर्ष को मालूम होना चाहिए कि वह ईमानदार है। दुनिया को और इस देश को मालूम होना चाहिए कि इमर्जेन्सी के कारण नई दिल्ली पर और इस देश की शासन-व्यवस्था पर कुछ असर पड़ा है। मैं बार-बार कहूंगा कि इसकी ज़िम्मेदारी कांग्रेस संगठन पर है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस संगठन अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेगा और अपने मिनिस्टरों को इस बात के लिए मजबूर करेगा कि वे अपनी असाइश को कम करें।

अब मैं गोल्ड कण्ट्रोल के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि सरकार के बीच में रिफ्ट डाली जाये, सरकार के नाम पर तो दुआयें दी जाय और एक मिनिस्टर की किसी बात पर उसे कोसा जाए। मैं समझता हूं कि गोल्ड नियन्त्रण एक आवश्यक कदम था। बाहर से तस्कर व्यापार चल रहा था और यहां की कीमतें बहुत ऊंची जा रही थीं और इसके लिए कोई नियन्त्रण लाना बहुत आवश्यक था। खेद तो केवल इस बात पर है कि यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया। स्वर्ण का तस्कर व्यापार केवल इमर्जेन्सी के टाइम में तो नहीं शुरू हुआ। जिस प्रकार गवर्नमेंट सुरक्षा के मामले में सोती रही, उसी प्रकार वह स्वर्ण के तस्कर व्यापार के मामले में भी सोती रही और वह जागी उस वक्त, जबकि मार मार कर जगाया गया। तब इमर्जेन्सी के टाइम पर स्वर्ण नियन्त्रण लाया गया। इसको बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। इमर्जेन्सी के टाइम पर स्वर्ण नियन्त्रण करने का परिणाम यह हुआ कि देश तो पहले ही बेकारी के चंगुल में फंसा हुआ था, अब और बीस लाख आदमियों को बेकारी के चंगुल में डाल दिया गया। इससे गवर्नमेंट को कोई आराम होगा, यह मैं नहीं समझ पाता। इस बीस लाख आदमियों के बेकार हो जाने से देश में कितना दुख और परेशानी होगी, मैं समझता हूं कि इसका अन्दाज़ा आज सरकार अच्छी तरह लगा रही है। यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि उन लोगों को सर्विसिज़ में जगह दी जायेगी। और सर्विसिज़ हैं कहां? सर्विस पाने के लिए लाखों करोड़ों आदमी पहले ही से बिलबिला रहे हैं। उनके साथ ही बीस लाख

[श्री बृजराज सिंह]

आदमियों की एक और लम्बी क्यू लगा दी गई है। अगर सरकार की तरफ से इन लोगों को सर्विस के सम्बन्ध में प्रायर्टी दी जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि आज तक जो लोग मर रहे हैं, उनका नम्बर इन बीस लाख लोगों के पीछे चला जाता है। सरकार को इस बारे में कोई तगड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे इस बेरोजगारी और भुखमरी से बचने का उपाय किया जा सके।

आज देश में एन० डी० एफ० नेशनल डिफैंस फ़ंड, के लिए कलेक्शन किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं। सब जगहों का तो मुझे पता नहीं, परन्तु उत्तर प्रदेश में नेशनल डिफस फण्ड कोई दान-वृत्ति वाली चीज़ नहीं रही। वहां पर अब रीयलाइज़ेशन किया जा रहा है। डेफ़िनटली रीयलाइज़ेशन किया जा रहा है। वसूलयाबी हो रही है। मैंने अपनी आंखों से बरेली के कलेक्टर का सर्कुलर लैटर देखा है, जिसमें लिखा गया था कि "फलां फलां तारीख को हमारे प्रदेश के मुख्यमन्त्री आ रहे हैं और उनको इतनी बड़ी थैली पेश करने का हम वादा कर चुके हैं। आप जाकर एक एक गांव को बेबाक कर लीजिए" लफ्ज़ "बेबाक" इस्तैमाल किया गया है। अगर ज़रूरत हो, तो आप दफ्तर के, सरकार के काम छोड़ कर और बाहर रह कर वसूलयाबी करते रहें। ताकि हमारे मुख्य मन्त्री जो आ रहे हैं, उनको थैली भेट करने में कोई कमी न हो जाए। यह कलैक्टर साहब की चिट्ठी है जो सर्क्युलेट की गई है, सारे तह-सीलदारों में, सारे एस० डी० ओज़० में, सारे ए० एस० डी० ओज़० में। इसको मैंने स्वयं देखा है। यदि सदन चाहेगा तो मैं इसे लाकर यहां टेबल पर भी रख दूंगा। इस वक्त मैं इसको ला नहीं सका हूं। हमारे प्रेज़ीडेंट साहब ने कहा कि लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, दी एक्चुअल वार खत्म हो चुकी है परन्तु खतरा बाकी है। लड़ाई खत्म हो चुकी है, नई दिल्ली पर कोई असर नहीं है, कांग्रेस के सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि काहे पर असर है? क्या एन० डी० एफ० रीयलाइज़ेशन पर इसका असर नहीं बाकी रह जाएगा? क्या एन० डी० एफ० की कोलैक्शन्ज़ के ऊपर कोई चादर डालनी है। इस तरह का नाजायज़ इस्तैमाल नहीं होना चाहिये। जब सरकार को जरूरत हो तो जनता सीना तान कर आगे आ सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो त्याग की भावना जनता में जाग्रत हुई थी, इस एन० डी० एफ० की रीयलाइज़ेशन से जो कि आज सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, उसको बड़ी ठेस ही नहीं लगी बल्कि वह सम्पूर्णतः समाप्त हो गई है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि मैं किस प्रकार इस भाषण के लिए जो कि प्रेज़ीडेंट साहब ने दिया है, धन्यवाद दे सकता हूं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों के साथ मैं भी आज राष्ट्रपति जी के भाषण का अनुमोदन करने के लिए खड़ी हुई हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चन्द एक बातें राष्ट्रपति जी के भाषण में नहीं हैं। मैं समझती हूं कि सभी चीज़ों का ज़िक्र डिटेल में इस भाषण में नहीं हो सकता था और न ही सभी बातों का ज़िक्र करके कोई ज्यादा फोयदा ही हो सकता था।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज चीनी हमले की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और उसी को सामने रख कर हम को बाकी बातों पर विचार करना है। मैं राष्ट्रपति जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि हमारी सरकार तमाम चीज़ों का फैसला जहां तक हो सके, शान्ति से करना चाहती है।

बहुत सी बात यहां पर कही गई हैं। यह भी कहा गया है कि हमारी सरकार डरती है और इन्तज़ाम ठीक से नहीं करती है या जाग्रत नहीं है, या बार बार धोखा खाकर सम्भलती नहीं है। जहां तक मेरी राय है,

हमारी सरकार और हमारे देश के लोगों ने बता दिया है कि हम जिस तरह से शान्ति के वक्त काम कर सकते हैं, उसी तरह अगर हमारे देश की आजादी को खतरा पैदा हो तो हम अपने देश को बचाने के लिए भी काम कर सकते हैं, पूरी तरह से काम कर सकते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने उनको भाई कहा और उन्होंने हम को धोखा दिया। क्या इसका यह मतलब है कि हम दुनिया में लोगों को भाई समझना बन्द कर दें ? अगर कोई आज भला आदमी है, अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, अच्छे उसूलों पर चलना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है, तो दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो एंटी-सोशल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, धोखा भी देते हैं, खराब बातें भी करते हैं लेकिन उनका भी मुकाबला किया जा सकता है। पर यह नहीं हो सकता है कि हम भी खराब हो जायें, हम लोग भी बिगड़ जाएं और हम सभी को शक और शुबह की निगाह से देखना शुरू कर दें और अपने चरित्र से, अपने उसूलों से गिर जाय। इस तरह की बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अगर हमने धोखा खाया है तो सम्भलना हम लोगों का फर्ज है। हम सम्भले हैं, हमारी जनता सम्भली हैं। हमारी सरकार भी सम्भली है और जो जो जरूरी चीज करनी हैं, उनको कर रही है।

यहां डिफेंस में बहुत सा सामान बनने लगा है, बहुत सी चीज बनने लगी हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती। मैं समझती हूं सरकार उनका जिक्र करेगी। इस सम्बन्ध में मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं कि आज जब शान्ति और अमन है तो हम लोगों को जो बोर्डर के एरियाज हैं, उनकी तरक्की पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। बोर्डर एरियाज में मैं उस एरिया का खास तौर पर जिक्र करना चाहती हूं जो कि नेपाल तक है। यह हमारा सौभाग्य है और यह अच्छी बात भी हैं कि नेपाल से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। व सम्बन्ध बने रहें और कभी लड़ाई और झगड़ा उधर न हो। पर जरूरी नहीं है कि उन सड़कों पर, उन इलाक़ों की तरक्की पर ध्यान उसी वक्त दिया जाए जब किसी तरह दोनों के ताल्लुक़ात ख़राब हों जायें। जब ताल्लुक़ात अच्छे हों, तब भी उन इलाक़ों की तरफ़ ध्यान दिया जाना चाहिये। और उन को विकसित किया जाना चाहिये। जो इलाके नेपाल बोर्डर में लगे हुए हैं, वहां पर अभी तक सड़कों की हालत ख़राब है, कोई मीज आफ़ कम्युनिकेशन नहीं हैं, ट्रांस्पोर्ट नहीं है कोई भी चीज नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूं कि उन चीज़ों का वह अच्छी तरह से ख्याल रखे।

हमारे राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि आर्थिक और औद्योगिक विकास भी हमारी डिफ़ेंस के लिए बहुत आवश्यक है। मैं समझती हूं कि एमरजेंसी आने के बाद भी सरकार के उन महकमों ने जोकि हमारे कारखाने बनवाते हैं, जो उन को लोन देते हैं, जो उनकी तरक्की करते हैं, कोई तेजी नहीं दिखाई है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि १९६२ के पहले जो नौ महीनों में साढ़े सात परसेंट इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ी है। लेकिन एमरजेंसी के बाद क्या नतीजे निकले हैं, कितनी तेजी आई इसका जिक्र नहीं किया है। मैं तो अभी भी देखती हूं कि जो उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं, छोट छोटे उद्योग धंधा चलाना चाहते हैं, उनको क़र्ज़ मिलने में, उनको पैसा मिलने में, उनको मदद मिलने में उतनी ही देरी होती है, जितन पहले हुआ करती थी। यही बात बिजली पर लागू होती है। बहुत सी स्टेटों में अभी भी बिजली और पावर देने का है, वह प्राइवेट कम्पनियों के हाथ है। यह काम प्राइवेट हाथ में होने से न कारखान के लिये बिजली मिलती है और न कोई मदद होती है। मैं प्रार्थना

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

करती हूं कि इस तरह की चीजों को जल्दी से जल्दी आप अपने हाथों में ले लें, स्टेट अपने हाथों में ले लें ताकि जो आवश्यक चीजें हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीजें हैं, जिनकी हमें लड़ाई में आवश्यकता हैं, उनके उत्पादन में तेजी लाई जा सके, उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके, उनके उत्पादन में मदद पहुंचाई जा सके ।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि एमरजेंसी डिक्लैयर होने के बाद मालिकों और मजदूरों में मीटिंग हुई थी और वहां पर इस बात का फैसला हुआ कि श्रमिकगण जब तक एमरजेंसी है, तब तक अधिक से अधिक पैदा करने की कोशिश करें और डिसप्यूट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स जो हैं, वे कम खड़े हों मुझ इस बातका बहुत अफ़सोस है कि इसका लाभ मालिक उठा रहे हैं । यह एक बहुत अच्छा फ़ैसला था जो कि श्रम मंत्री नन्दा जी ने करवाया था । लेकिन इस का फ़ायदा मालिक ज्यादा से ज्यादा उठा रहे हैं, पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा उठा रहे हैं और कई जगहों पर जो यूनियंज में काम करने वाले हैं, उनको निकालने, उनको सताने, उनको हटाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं । वे समझते हैं कि अगर श्रमिकगण इसका मुकाबला करेंगे तो कहा जायगा कि श्रमिक उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं । इसलिए मैं श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वह इस तरफ़ तवज्जह दें । मैं चाहती हूं कि वह बतायें कि इस एमरजेंसी में कौन से कदम उठये गये हैं जिनसे मजदूर वर्ग अपनी शिकायतें दूर करवा सकते हैं, अपनी तकलीफ़ें दूर करवा सकते हैं, जो उनकी कठिनाईयां हैं, उनको दूर करवा सकते हैं ।

इसी सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि श्रमिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । पैदावार बढ़ा रहे हैं लेकिन मुझे अफ़सोस है कि जिस तरह से देश के दूसरे पूंजीपति और मलिक इस एमरजेंसी से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी तरह से हमारे यहां भी एक बिल लाने की कोशिश की जा रही है जिस में यह व्यवस्था है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो अपने आपको डिफ़ेंड करने का मौका दिया जाता रहा है, एक सैकशन का एमेंडमेंट करके, यह मौका उन से छीन लिया जाए, यह जो उनका अधिकार है, यह उनसे वापिस ले लिया जाए । मैं दरख्वास्त करूंगी अपने श्रम मंत्री से जी तथा दूसरों से भी कि सरकारी कर्मचारियों ने जितना अच्छा आचरण इरस वक्त दिया है, जितना अच्छा परिचय दिया है, उसको देखते हुए ऐसे वक्त पर इस तरह का एमेंडमेंट ला कर, उनकी चोट पहुंचाना बहुत नामुनासिब है । उन्होंने हमको बहुत ज्यादा पैसा ही नहीं दिया बल्कि यह भी कहा है कि हमें छुट्टी नहीं चाहिये, कुछ नहीं चाहिये, हम चोबीस घंटे काम करने के लिये तैयार हैं । जब वे इतना कोओपरेशन दे रहे हैं तब इस प्रकार का एमेंडमेंट ऐसे मौके पर नहीं लाया जाना चाहिये । मैं आशा करती हूं कि इस पर विचार किया जाएगा ।

यह हमारी समाजवादी सरकार है, इसको मैं मानती हूं । लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं । मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर पढ़ी है कि हमारे एल० आई० सी के लोग बर्मा में एक मुकदमा लड़ रहे हैं और इस आधार पर लड़ रहे हैं कि बर्मा के जो एम्प्लायीज़ हैं, उनको दूसरों के मुकाबले में वहां पर कम पैसा देते हैं, जितने पैसे एल० आई० सी० के हिन्दुस्तानी कर्मचारियों को देते हैं वर्मा के लोगों को उससे कम मिलते हैं । यहां पर हर रोज़ इस बात की चर्चा होती है कि दूसरे देशों की हमारे साथ हमदर्दी होनी चाहिये और खास तौर पर आज के वक्त पर तो होनी ही चाहिये । ऐसी सूरत में चाहे हमारे बैंक हों या दूसरे मुहकमे दूसरे देशों के लोगों को, दूसरे देशों के नागरिकों

को वे एक्सप्लाइट करने की कोशिश करें तो अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी पालिसी स्पष्ट करे।

हमारे राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा किया जो उन देशों को धन्यवाद दिया जिन्हों ने इस एमरजेंसी में हमारी मदद की है। जिन राष्ट्रों को इस भाषण में जिक्र नहीं है और जिन्हों ने हमारी मदद की है, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं।

हमारे देश पर आक्रमण हुआ। चीनी बढ़ते चले आ रहे थे, उस समय खास कर दो देशों को, जिन का उन्होंने धन्यवाद दिया, अर्थात् यू० एस० ए० और ग्रेट ब्रिटेन, हमारे देश का बच्चा बच्चा आभारी है। ऐसा कौन होगा जो अहसान नहीं मानेगा, जो कृतज्ञ नहीं होगा? हमारे देश के करोड़ों लोग कृतज्ञ हैं उन देशों के जिन्हों ने हमारे देश को मदद की थी। परन्तु एक चीज मैं कहना चाहती हूं। मैं इस सभा के माननीय सदस्य श्री रंगा से प्रार्थना करना चाहती हूं कि जिस तरह से वह बाहर की मदद की मांग करते है और साथ ही जो हमारे देश की समाजवादी प्लैन है, जो प्लैन समाजवाद पर बेस्ड है, उसका विरोध करते हैं, उस से हमारे देश में बड़ी चिन्ता हो जाती है। बाहर की सारी मदद चाहिये, हर एक को चाहिए पर क्यों मदद चाहिए? इस लिये कि देश के करोड़ों गरीब लोग इस बातके इन्तजार में हैं कि हमारे देश की आजादी बनी रहे तो किसी दिन हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर बाहर से मदद मांगने वाले लोग रंगा जी जैसे हों और साथ में वह कहें कि सरकार को अपनी समाजवादी प्लैन तोड़ देनी चाहिये, बदल देनी चाहिये और समाजवाद यहां नहीं लाना चाहिये, तो देश के गरीब आदमियों को और हमें जो मदद बाहर से मिलती है उस के बारे में दिल में सन्देह होने लगता है, शुबहा होने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि हमारी समाजवादी प्लैन हट जाये और अमरीका और इंगलैंड से मदद आये, कहीं इन में कोई सम्बन्ध तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रंगा साहब की जमात इस बात का फायदा उठाना चाहती हो

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : आप जो मदद ले रहे हैं उस का मतलब क्या होता है?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : हमारे दिल में शुबहा होने लगता है, हम सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रंगा साहब, स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ के लोग इमरजेंसी का फायदा उठा कर अपना काम सीधा करना चाहते हैं, और अपनी अपनी पार्टी का, जो कि समाज के खिलाफ है, उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं और इस के लिये अमरीका का नाम लेते हैं। या तो वह फायदा उठा रहे हैं या हो सकता है कि बाहर वालों के कहने से ऐसा वह कह रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी मदद की है उन से हमें रोज रोज मदद चाहिये, लेकिन उन के प्रति रंगा साहब हमारे दिल में संदेह पैदा करते हैं। मैं रंगा साहब से प्रार्थना करूंगी कि वह ऐसा न करें। मैं तो अपने अमरीका और ग्रेट ब्रिटन के लोगों से भी प्रार्थना करूंगी कि अगर रंगा साहब दोस्ती में ऐसा करते हैं तो वे नादान दोस्त हैं, और उन का साथ उन लोगों को छोड़ देना चाहिय। और अगर रंगा साहब कोई एजेंट हैं तो उस एजेंट को उन लोगों को डिसमिस कर देना चाहिये क्योंकि इस वक्त देश का बच्चा बच्चा अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन का आभारी है। लेकिन जब रंगा साहब उस के साथ यह जोड़ देते हैं कि समाजवादी प्लैन को तोड़ दिया जाय, उस समय देश के लोग उन देशों को कुछ शबहा की नजर से देखते हैं।

दूसरा जो एतराज मुझे है वह यह है कि रंगा साहब ने औरतों के काज को बहुत एडवोकेट किया और कहा कि उन के जेवर ले लिये गये जिस से कि देश की स्त्रियां बहुत दुखी हैं, परेशान है, डर गई हैं। हिन्दुस्तान की स्त्री क्या चाहती है? हिन्दुस्तान की स्त्री

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

चाहती है कि उस के बच्चे को अच्छा खाना मिले, अच्छा पढ़ने को मिले, उस के बच्चे की सेहत अच्छी हो और उस का बच्चा जब बड़ा हो जाये तो उस को रोजगार मिले । आज हिन्दुस्तान की स्त्री, हिन्दुस्तान की गरीब जनता की मा आजादी क्यों चाहती है ? इसलिये कि उन के बच्चों की तरक्की हो । आज समाजवाद चला जाय, हिन्दुस्तान की स्त्री इस को नहीं चाहती और रंगा साहब ऐसा समझते हैं कि हिन्दुस्तान की स्त्री को सोना चाहिये, तो हिन्दुस्तान की स्त्री ऐसी नहीं है । वह सोना ले कर क्या करेगी? हिन्दुस्तान की स्त्री सोना तो क्या सभी कुछ दे सकती है । अपने देश के और अपने बच्चों की तरक्की के लिये । हिन्दुस्तान की स्त्री, भारतीय नारी आज बच्चे दे रही है कुर्बानी के लिये, भाई दे रही है, पति दे रही कि सीमा पर जा कर लड़ने को तैयार हैं, तब स्त्री के केस को ऐडवोकेट करना कि हिन्दुस्तान की स्त्री को सोना चाहिये, यह स्त्री का बड़ा अपमान करना है, जो कि रंगा साहब ने किया । हिन्दुस्तान की स्त्री को समाजवादी प्लैन चाहिये, हिन्दुस्तान की स्त्री को देश की रक्षा चाहिये । मैं उन भाइयों से कहूंगी जिन का केस ऐडवोकेट करते हुए यहां कहा गया है कि सुनारों के पास आज काम नहीं है भारत में, रंगा साहब से कहूंगी कि हिन्दुस्तान की स्त्री नहीं चाहती कि वह सोने की बात कह कर हिन्दुस्तान की स्त्री को बेवकूफ बनायें । आज हिन्दुस्तान की स्त्री सोने के जेवर पहन कर बेवकूफ नहीं बनना चाहती । मैं कहूंगी कि सुनार भाई कारखाने बनायें, जिन में देश के बच्चों को काम मिले, सुनार भाई आज बम और गोले बनायें जिस से कि हमारे देश की रक्षा हो और आजादी बनी रहे । (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : आप तो यहीं कारखाने बनाने लगी ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इस तरह से भारतीय नारी का नाम ले कर अगर यहां रंगा साहब पूंजीपतियों, मुट्ठी भर लोगों के केस को जिनके हाथों में सोना है, राजाओं और महारानियों के केस को ऐडवोकेट करते हैं, तो उसको हम बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं । इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि बाहर से ऐड लेने के बहाने हमारी प्लेन को कटवाने की बात जो यहां होती है उस को हमें रोकना चाहिये ।

हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना, विचार इजहार, विश्वास, निष्ठा और पूजा की आजादी, दर्जे की बराबरी यह सब करना हमारी सरकार का काम रहा है । आज हमारे सामने सवाल उठा कि इमर्जेन्सी रहे या नहीं रहे । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि अगर इमर्जेन्सी का इस्तेमाल नहीं करना है तो वह क्यों रहें । इमरजेंसी रहनी चाहिये । पर उस का कहां इस्तेमाल हुआ है ? सरे-आम कहा जाता है कि सरकार को पैसा मत दो, उस पर हमारा विश्वास नहीं है, सोना मत दो, सरकार पर विश्वास नहीं है । सरे आम कहा जाता है कि इस सरकार में समझ नहीं, अक्ल नहीं, वह सम्भाल नहीं सकती है । इतना ही नहीं भाई भाई में, बिरादरी बिरादरी में, जाति जाति में आज भी जहर अथवा विष फैलाया जाता है । लेकिन सरकार अपनी इमर्जेन्सी की पावर को इस्तेमाल नहीं करती है । आज जो नई और सब से खराब बात हम ने देखी, और जिस की हमें सरकार से शिकायत करनी है वह यह है कि जब कि हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि हम यहां पर नागरिक नागरिक को बराबर समझते है, हमारे देश में जो राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो हमारी आजादी का दिन मनाया गया, उस में उस जमात को जगह दी गई जो कि देश के तमाम नागरिकों को नागरिक मानने के लिये तैयार नहीं हैं, जो जमात देश के झंडे को अपना झंडा मानने के लिये तैयार नहीं है, जो जमात अपने देश के तमाम लोगों को एक बराबर मानने के

लिये तैयार नहीं है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को हमारे यहां उस सड़क पर मार्च करवाया गया जिस सड़क पर गांधी जी की अर्थी को हम ने निकाला था ।

श्री बड़े : (खारगोन) : उस वक्त हमारे हाथ में नेशनल फ्लैग था । राष्ट्रीय झंडा उन लोगों के हाथ में था और आर० एस० एस० को कारपोरेशन ने बुलाया था । क्या हम को चलने का अधिकार भी नहीं है । २६ जनवरी को ? हम भी नागरिक हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके । अब वह बैठ जायें ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि आज इमर्जेन्सी के वक्त खास कर हमारे देश के लिये, तमाम नागरिकों को ....

श्री रामेश्वरानन्द : वह कह रही हैं कि कम्युनिस्टों से प्रेम करो, औरों से मत करो क्योंकि उन के पति देव कम्युनिस्ट हैं ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अगर हमारी सरकार इमर्जेंसी की पावर्स को इस्तेमाल नहीं करती हैं तो इमर्जेन्सी को हटा दिया जाय, और अगर वह इमर्जेन्सी की पावर्स को इस्तेमाल करती है तो हमारे यहां इमर्जेन्सी रहनी चाहिये और कारखानों के बाहर और भीतर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम कर के देश की रक्षा के लिये तैयार रहना चाहिये ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे अवसर दिया मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने विचा प्रकट करना चाहता हूं । कब्ल इस के कि मैं राष्ट्रपति महोदय के विचारों के ऊपर अपना मत प्रकट करूं, मैं उस दिन जो राष्ट्रपति के प्रति अशोभनीय घटना घटित हुई उस के सम्बन्ध में मैं अपनी क्षमा याचना करना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

आज लगभग बारह वर्षों से देश के राष्ट्रपति हिन्दी भाषा भाषी पूज्य राजेन्द्र बाबु थे । मेरा ऐसा इम्प्रेशन था कि बाह वर्षों तक राजेन्द्र बाब पहले हिन्दी में और उस के बाद अंग्रेजी में अपना अभिभाषण दिया करते थे । लेकिन एक हिन्दी भाषा भाषी और हिन्दी हिमायती ने, जिन्हें किसी से भी कम हिन्द से प्रेम नहीं है, बतलाया कि राजेन्द्र बाब भी जब पूर्ण स्वस्थ थे तो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ते थे । पहले वह अंग्रेजी में अपना अभि ाषण पढ़ते थे और बाद में हिन्दी में पढ़ते थे ।

इसके अलावा मैं उन भाइयों के प्रति भी क्षमा याचना करना चाहता हूं जो कि हिन्दी भाषा भाषी नहीं है । इस से उन भाइयों के मनमें यह आशंका उत्पन्न हो सकती कि हिन्दी भाषा भाषी जोर जबरदस्ती कर के हिन्दी को उन के ऊपर लादना चाहते हैं । इसलिये एक हिन्दी भाषा भाषी होने के नाते में यह बिलकुल स्पष्ठ कर देना चाहता हूं कि यह भावना जिसके वशीभूत होकर राष्ट्रपति के संसद के संमुख अभिभाषण के समय इस किस्म का प्रदर्शन किया गया, वह उन की अपनी व्यक्तिगत भावना हो सकती है या उनकी पार्टी की हो सकती है जिस जमात से कि वे आते हैं । पर उससे हिन्दी भाषा भाषियों का कोई संबंध नहीं है । हिन्दी भाषा भाषियों का उनके प्रति भी उतना ही आदर है जितना कि उनका जो इस देश में हिन्दी नहीं जानते है । इस देश में अभी भी एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहां कि लोगों को हिन्दी की जानकारी नहीं है और विशेष प्रयास करने पर भी हिन्दी को सीखने में उन को कठिनाई होती है । जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था और जब मैं अपने प्रदेश में था तो मेरा भी यह विचार था कि हिन्दी की उन लोगों के प्रति अश्रद्धा है और वे हिन्दी की जानकारी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन यहां आने पर मुझे यह चीज समझ में आगई कि वाकई हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने में उनको कठिनाई

[श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह]

का अनुभव होता है और प्रयास करने पर भी वे उसे जल्दी नहीं सीख सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी हिन्दी के प्रति अश्रद्धा है या वह हिन्दी सिखना नहीं चाहते हैं। इस लिये राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर जो अशोभनीय कांड यहां घटित हुआ उसके लिये में समस्त हिन्दी भाषा भाषियों की ओर से उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूं और राष्ट्रपति महोदय से भी क्षमा चाहता हूं जोकि उनके प्रति ऐसा अशोभनीय प्रदर्शन हुआ।

आज देश में संसदीय पद्धति के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और आदर का भाव है और सभी लोग संसद के सदस्यों को आदर की दृष्टि से देखा करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे जैसा कि अभाग्यवश उस दिन किया गया तो देशवासियों के दिलों में संसदीय पद्धति के प्रति अनादर पैदा होगा और ऐसी बात पैदा हो जायेगी जिससे कि देश का कल्याण नहीं होगा और कोई दूसरी ही व्यवस्था उत्पन्न करनी पड़ेगी।

गत सोमवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति महोदय ने जो भाषण दिया उसके तीन अंग हैं, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, आन्तरिक व्यवस्था एवम् भारत चीन सीमा विवाद। तीनों पर उन्होंने प्रकाश डाला अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में उन्होंने संतोष जाहिर किया है। इसमें हम लोग उन से सहमत है। हमारे निकटवर्ती राज्य नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपनी मौजूदा समस्याओं को सुलझाने और उनके साथ अपने संबंध मैत्रीपूर्ण बनाने के लिये हमारी सरकार सचेष्ट है और चिंतित भी है। अभी कुछ ही दिनों बाद हमारे आदरणीय नेता और गृह-मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री नेपाल जाने वाले हैं। और मेरा अपना विश्वास है कि नेपाल से हमारी मित्रता पुनः वैसी ही कायम होजायगी जैसी कि पहले थी।

एक दूसरे मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने पिछले दिनों पाकिस्तान से मौजूद समस्याओं को सुलझाने और उससे अच्छे संबंध स्थापित करने के लिये कई बार प्रयास किया है और कई मीटिंग इस संबंध में हो चुकी हैं। मेरी आशा और विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा मुख्य समस्याओं पर समझौता हो जायगा और अच्छे संबंध स्थापित हो जायेंगे और दोनों पड़ौसी देशों में मैत्री भाव कायम हो जायगा।

जहां तक दूसरे देशों का संबंध है, मैं मानता हूं कि हमारी विदेशी नीति अच्छी रही है। विदेशों में जो हमारे राजदूत नियुक्त हैं वे काबिल और सुयोग्य हैं लेकिन काबिलियत के साथ उनके चुनाव में कुछ देशभक्ति का भी ख्याल रहना चाहिये। प्राग के पास हमारे देश का नक्शा नहीं था और जिस नक्शे को डांगे साहब को देना पड़ा जिससे कि उनकी जानकारी हुई। इससे मालूम होता है कि जो हमारे राजदूत विदेशों में रहते हैं वे सुयोग्य रहते हुए भी कहीं कहीं उन में देश की चिन्ता की कमी और देशभक्ति की कमी रहती है। इसलिये मेरा सरकार को नम्र सुझाव है कि इनकी बहाली के वक्त देशभक्ति को प्रथम स्थान देना चाहिये और बाद में योग्यता और अन्य चीजों का ध्यान होना चाहिये। ऐसा करने से हमारे देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा ऊंची उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, आन्तरिक व्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने संतोष जाहिर किया है। कृषि और उद्योग के मामले में देश की काफी प्रगति हुई है। लेकिन कुछ दिन पहले कलकत्ता की एक सभा में हमारे माननीय योजना मंत्री ने कृषि या उद्योग के मामले में पूरा संतोष जाहिर नहीं किया। उसके इस विचार से हम भी सहमत हैं और इस दृष्टि से सरकार को ज्यादा चेष्टा दिखाने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को उन कामों के लिए जवाबदेह बनाने की जरूरत

है जिन को कि इन कामों की जानकारी के साथ साथ उन में श्रद्धा भी हो । अभी देखा जाता है कि योजनाएं बना दी जाती हैं और ऐसे लोगों को जिन की इन योजनाओं में श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है उन को उनके वास्ते जवाबदेह बना दिया जाता । फलस्वरूप योजना में सफलता नहीं होती और योजना में कमी होती है । इसलिए यह आवश्यक है कि जिस योजना के लिए जो व्यक्ति लगाया जाये और जवाबदेह बनाया जाय उसकी उसम श्रद्धा हो । जिस योजना में आदमी रखा जाय और जवाबदेह बनाया जाय उस में उस योजना के प्रति आस्था और विश्वास रहना जरूरी है और केवल उन्हीं लोगों को लिया जाय ।

राष्ट्रपति ने जिस वीरता और संकल्प के साथ इस संकटकालीन घड़ी में देशवासियों का आवाहन किया है उस का सारे देश में स्वागत हुआ है । वह हमारे देश में आदर के सूचक बन गये हैं । वह एक महान् दार्शनिक हैं । शब्दों का समुद्र उन के समक्ष मौजूद है और उन्हों ने यह साबित कर दिया है कि प्रशासन के काम में केवल राजनीतिक व्यक्ति ही दक्ष और कुशल नहीं हो सकता है बल्कि दार्शनिक और विद्वान् लोग भी इस काम को सुचारु रीति से कर सकते हैं । जिन का किसी पार्टी विशेष या दल से सम्बन्ध नहीं होता है वह देश की भावनाओं का विशेषवीरता और विशेष संकल्प के साथ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं बनिस्बत उन व्यक्तियों के जिन का कि किसी पार्टी या दल से सम्बन्ध रहता है । उन की भावनाओं का देश ने स्वागत किया है और आज राष्ट्रपति के रूप में सारे देश की भावनाओं के प्रतीक बन कर हमारे सामने मौजूद हैं ।

भारत चीन विवाद के सम्बन्ध में उन्हों ने विशेष ध्यान दिया है । उन्हों ने कहा है कि देश में शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हुए भी हम किसी भी तरीके से प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और देश की रक्षा में किसी बात की कमी नहीं करेंगे और इस काम को पूरा करने के लिए हमारी सरकार सचेष्ट है । इसी अभिप्राय: से यह संकटकालीन स्थिति जो हमारे देश में कायम है उस को जारी रक्खा जा रहा है ।इस दृष्टि से हमारे देश के नागरिकों ने जो सहयोग दिया है वह निश्चय ही प्रशंसा की बात है । एक स्वर से देहातसे ले कर शहरों तक के लोगों ने इस में एकता की भावना दिखलाई है और एक आवाज से जिस तरीके से चीनी आक्रमण का विरोध किया है और उस के विरुद्ध प्रदर्शन किया है वह सचमुच ही हमारे देश के लिए एक गौरव की वस्तु है ।

यह बात यहीं नहीं है जैसाकि कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि जोर जबरदस्ती से चंदा वसूल किया जाता है । लोगों ने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से चन्दा दिया है क्योंकि लोगों के हृदय में देशभक्ति की एक ज्वाला है जोकि इस के लिए उन को प्रेरित करती है । देशवासी हर प्रकार से देश की रक्षा के लिए तैयार है और वे उस के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं । लेकिन उन माननीय सदस्यों ने जिन्हों ने कि इस के विरुद्ध शिकायत की, उन की भावनाओं से इतना मैं जरूर सहमत हूं कि चंदा वसूली का काम जिस पवित्र भावना से होना चाहिए उस भावना से न हो कर एक प्रचार का दृष्टिकोण उस में रक्खा गया है क्योंकि अगर एक बार एक ब्लाक में चंदा ५००० के करीब वसूल हुआ तो फिर वही ५००० की रकम ५ मंत्री उस ब्लाक में गये तो ५ बार उस का प्रचार किया गया । जिस पवित्र भावना से लोगों ने सरकार का साथ दिया और पूरी सहायता की, जिन लोगों पर यह रुपया वसूल करने की जवाबदेही थी, उन लोगों ने उस पवित्र भावना से काम नहीं लिया । यह एक दुखद बात है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

[श्री रामशेखर प्रसाद सिंह]

इस में कोई सन्देह नहीं कि ख़र्च में कमी करने की बहुत आवश्यकता है । आज कांफ्रेंसिज होती हैं और इस के साथ ही हवाई जहाज, स्टाफ़ कार और टेलीफ़ोन आदि के इस्तेमाल का प्रश्न सामने आता है यह कहा जा सकता है कि चालीस पचास हज़ार या दो चार लाख रुपये की बचत से क्या हो सकता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के ख़र्च से लोगों की अन्तरात्मा और भावनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है । लोग महसूस करते हैं कि एक तरफ़ तो ये लोग दो दो पैसे के लिए भिखारी बने हुए हैं और दूसरी तरफ़ ये हवाई जहाजों का इतना इस्तेमाल करते हैं—जहां बड़ी आसानी से रेल के द्वारा जा सकते हैं, वहां पर ये हवाई जहाज से जाते हैं । लोगों पर इस का बहुत बुरा असर पड़ता है । इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यद्यपि पहले पटना से सरकारी काफ़िला बड़ी आसानी स प्लेन में दिल्ली पहुंच जाता था, लेकिन इमर्जेन्सी के इस ज़माने में इस काम के लिए दो दो हवाई जहाज इस्तेमाल किये जाते हैं । आज सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । जो आवश्यक ख़र्च है, वह ज़रूर किया जाये, लेकिन जो अनावश्यक ख़र्च है, जिस में किसी तरीके से कमी की जा सकती है, उस को कम करने का प्रयास किया ।

आज सारा देश वार मूड में है । आज देश के एक एक नागरिक के दिल में युद्ध-भावना जाग्रत है । सभी लोग इस बात को जानने के लिए चिन्तित हैं कि लड़ाई के लिए सरकार की तैयारी क्या है । अगर आज कोई भी आदमी चाइनीज के प्रति कोई रोष प्रदर्शन करता है और इस संकट-कालीन स्थिति के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता ज़ाहिर करता है, तो, क्या आप जानते हैं कि उस के लिए क्या कहा जाता है ? कहा जाता है कि यह व्यक्ति जवाहरलाल जी के ख़िलाफ़ है । मालूम होता है कि आज चाइना के सब से ज्यादा दोस्त जवाहरलाल जी हैं । कौन लोग ऐसा कहते हैं ? ऐसी बात वे लोग कहते हैं, जिन्हों ने कभी भी पंडित जी का साथ नहीं दिया । १९४२ की क्रान्ति के ज़माने में, जबकि हम लोग जेलों के सीखचों में बन्द थे, ये लोग कहा करते थे कि हम ट्रेटर्ज टु दि कंट्री हैं, उस वक्त लड़ा जाने वाला युद्ध पीपल्ज वार है और उस में सहायता के देने के कारण जवाहरलाल जी बुरे हैं । मैं आप को बताना चाहता हूं कि उस समय "भारत छोड़ो" का नारा लगा कर कितने ही नौजवान फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन इस प्रकार की बात कहने वाले लोग आज जवाहरलाल जी के सब से नज़दीक और हमारे माननीय नेता, श्री त्यागी, उन से दूर चले गए कहे जाते हैं ।

श्री त्यागी : मैं प्रोटेस्ट करता हूं । मैं उन से दूर नहीं हूं ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : उन के बारे में ऐसा कहा जाता है । मैं ने यह नहीं कहा कि वह दूर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो श्री त्यागी की मदद कर रहे हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : माननीय सदस्य का इशारा किस तरफ़

अध्यक्ष महोदय : उन का इशारा आप की तरफ़ भी हो सकता है । मेरा इशारा शर्मा जी की तरफ़ है ।

श्री दी० चं० शर्मा : शुक्रिया ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिला कर हर एक लड़ाई में पंडित जी का साथ दिया, वे कभी भी उन से दूर

नहीं हो सकते हैं, यह मेरा विश्वास है । मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में जवाहर लाल जी जितने मज़बूत हैं, उतने मज़बूत वह जिन्दगी में कभी भी नहीं थे । आज ४४ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जवाहरलाल जी हैं और हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा उन के साथ है । सिर्फ़ वही लोग उन के साथ नहीं हैं, जो कहते हैं कि उन के हाथ मज़बूत करने चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल जी कभी भी कमज़ोर नहीं रहे हैं और न हैं ।

देश में एक ऐसी एम्बीशस पार्टी है, जोकि इस सम्बन्ध में बात चलने पर कहती है कि आल्टरनेटिव लीडरशिप होनी चाहिए । अगर इस बारे में उन से बात करें, तो वे भी स्वीकार करेंगे कि पंडित जी इंडिस्पेन्सेबल हैं । पंडित जी केवल जवाहरलाल ही नहीं हैं, बल्कि वह हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की युद्ध करने वाली मनोवृत्ति के प्रतीक हैं । जिन लोगों ने कुछ दिन पहले कोलम्बो प्रस्तावों को बुरा बताया था, उन को भी स्वीकार करना पड़ा कि प्रधान मंत्री ने उन को मान कर अच्छा किया ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या स्वामी जी की तकरीर साथ साथ चलती रहेगी ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह : हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश की चीन का मुकाबला करने की भावनाओं के प्रतीक हैं । जो लोग चाहते हैं कि चाइनीज़ को किसी भी तरीके से इस देश से निकाला जाय, उन को मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करें, उस में किसी तरीके से बाधा डालना देश को कमजोर करना है । जो लोग उन की पापुलैरिटी से लाभ उठा कर खुद पापुलर बनना चाहते हैं, केवल वही कहा करते हैं कि पंडित जी कमज़ोर हैं, उन को मज़बून बनाना चाहिए । उन को कमज़ोर कहने की बात ग़लत है ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय को उन के भाषण के लिए धन्यवाद देता हूं ।

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Mr. Speaker, Sir, during the Question Hour itself, it was very evident that Members belonging to all sections of this House were very much agitated over the proposad between Pakistan and China to conclude an agreement on the border of Kashmir. The Pakistan Foreign Minister has already proceeded to Peking. As far as our position is concerned, it was made very clear long ago that neither Pakistan nor China has any right whatsoever to conclude an agreement on the border of Kashmir. We have declared from this forum that we continue to hold to that position that the people of this country will not be a party to any agreement or any action on the part of either Pakistan or China to repudiate through the backdoor the sovereignty of India over the entire Jammu and Kashmir State.

Shri Tyagi: I hope this will be the policy of the communist party of India.

Shri Vasudevan Nair: Yes; this is the declared policy of the communist party of India not now, but since long ago.

We were persuaded by our friends to sit round the table with representatives of Pakistan to settle the outstanding disputes between the two countries. As far as we are concerned, with all our differences with Pakistan and its leadership, we have always stood for friendship and peace between these two neighbourly countries. From the bottom of our heart, we wish to have everlasting friendship and peace with the brothers and sisters of Pakistan. But what is happening today? We regret to state that the unscrupulous policies of the

[Shri Vasudevan Nair]

leadership in Pakistan are standing in the way of establishing peaceful relations between these two countries. When the U.K. and USA came to help India, they persuaded our Government to make a trial and see whether the Kashmir question could be settled and marathon meetings are taking place. Our Minister, Shri Swaran Singh, is handling a very delicate question with patience. But reports have appeared that there are schemes hatched by various people and Governments, not only inside our two countries but even outside, for the partition of Jammu and Kashmir State. Our Deputy Leader, Shri Hiren Mukerjee, made it very clear, when he spoke here the other day, that we want the Parliament at least to be taken into confidence when such proposals are there before the Government. There are some disturbing statements also by responsible people. You might have also read a statement issued by the erstwhile Special Secretary of the External Affairs Ministry who happens to be a Vice Chancellor now. In that statement he has pleaded for the partition of Jammu and Kashmir State and even handing over some of the areas now under our jurisdiction.

13 hrs.

Shri Tyagi: Is it a Press statement?

Shri Vasudevan Nair: I think he made a speech and it was reported.

Shri Tyagi: In which paper?

Shri Vasudevan Nair: It was reported in many daily newspapers.

Sir, he being an ex-employee, an ex-official of the External Affairs Ministry, that statement has added importance.

Shri Tyagi: He made that statement in England.

13.01 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

Shri Vasudevan Nair: Unfortunately he has even used a language which is really objectionable. He has said "those areas under the present occupation of India". About Kashmir he has used a language which is thoroughly objectionable. The point is—not that I want to impeach him before this Parliament—when a person employed in the External Affairs Ministry makes a statement which is having some importance, I want that Government should make it very clear as to whether there is any deliberation or discussion going on.

Shri D. C. Sharma: Is that man now a Pakistani national or an Indian national?

Shri Vasudevan Nair: To my knowledge he is an Indian national.

Shri Tyagi: May I enquire from the hon. Deputy Minister as to whether he is still in the employ of the Ministry of External Affairs?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The Government will reply at the end.

Shri Vasudevan Nair: Now, Sir, the only point is that Parliament should be taken into confidence before the Government takes a final decision on this matter.

There are some people in our country who are all out for a settlement with Pakistan, I may say, at any cost, and it was mentioned by several Members in this House that one of the Opposition parties in this country represented by our hon. friend, Shri Ranga, was kind enough, gracious enough to entrust the entire responsibility of settling this problem to the Prime Minister with whom they have such fundamental differences in the handling of the China affair.

Shri Ranga (Chittoor): In regard to this matter we do not have any differences with him.

Shri Vasudevan Nair: One can understand the policy of such people who have even gone out of their way to plead for people—I do not say they are not our friends—who have taken up positions on various issues which were not in our favour. Is it a secret that such people have always pleaded on behalf of Pakistan as far as the Kashmir question is concerned? Is our memory so short as to forget that a little while ago in the United Nations when the issue was discussed they openly collaborated with Pakistan? So, Sir, we should be very careful in proceeding in such matters and I warn such parties and sections of people also to be a bit careful.

Dr. M. S. Aney: What party are you referring to?

Shri Vasudevan Nair: Sir, I have only very little time at my disposal and I am unable to enlighten the hon. Member by further explanation.

Shri D. C. Sharma: You should not make oblique references, you should make direct references.

Shri Vasudevan Nair: Questions were asked of the Prime Minister as to whether he had received any communication about the reactions of the United States and United Kingdom Governments about the proposed treaty between China and Pakistan. In the Press we read some mild statements beings issued by the Secretary States of America, Mr. Dean Rusk, where he has expressed some concern about the proposed treaty. But, Sir, we all know that, after all, Pakistan has got its western guardians who can intervene if they want in such matters, and who have made it a condition precedent before giving help to India that India should sit round a table and settle the problem of Kashmir thereby persuading India even to partition that State and give our territory to Pakistan.

Now, they are taking a very lukewarm attitude. From the past experience we should learn lessons and be prepared to meet the present difficult situation standing on our own legs. The problem posed before us is: what to do in the present situation? We have to strengthen our defence. We have to increase our armed might. But for all those things if people advise us to look towards other countries, it is a very wrong position to take which is detrimental to our basic interest. The Prime Minister, sometime ago, criticised the people who thought that building up of the defence of this country could mainly be entrusted to outsiders. He was ridiculing those people who thought on those lines by saying that some people think that we may write a post-card to London or Washington to send us arms and then we can fight with those arms. Essentially, we believe, we have to rely on ourselves to the maximum extent as far as strengthening of our defence is concerned. Simultaneously, we have to pursue peaceful methods to solve the disputes. As far as our country is concerned, we have always stuck to the position of peaceful solution of all controversial questions. That is why we have always supported the Government's position of strengthening the defensive potential of the country and simultaneously trying to solve all the problems peacefully.

There are critics inside as well as outside who are clamouring for all kinds of foreign bases, all kinds of "umbrellas"—all kinds of new words like "armada" and others are coined by newspapers—and who perhaps think that they can safely sleep on the arms of somebody else. Sir, in our language there is a proverb that one can never safely sleep on the arms of somebody else.

Shri D. C. Sharma: Why? On the mother's arms we sleep.

Shri Vasudevan Nair: That is a fundamental position and that has to be accepted by every self-respecting country. We have to go on strengthening our army, our navy and our

[Shri Vasndevan Nair.]

air force so that we will be in a position to meet any threat from any quarter. At the same time, we should try to settle all problems peacefully, with dignity and with honour, if such an opportunity is presented before us.

In that way, Sir, we have accepted the Colombo proposals. But it is painful to see even responsible Members of Parliament trying to run down the countries who have in their own humble way tried to put forward a solution to this dispute. Even my hon. friend Shri Hem Barua was stating here that four countries out of the six Colombo powers are with China—I do not know where he gets that information from.

Shri Priya Gupta (Katihar): Because they did not protest when China committed aggression against India.

Shri Vasudevan Nair: He was lamenting in this House that we are all alone, our country is alone, our Prime Minister is alone and our people are alone.

Shri Priya Gupta: Hs was not lamenting but giving expression to his feelings.

Mr. Deputy-Speaker: Order order. The hon. Member cannot sit and go on interrupting like that. It is very unparliamentary. No hon. Member should sit and talk like that.

Shri Priya Gupta: Interruptions are part of the proceedings.

Mr. Deputy-Speaker: Unless the hon. Member who is on his legs yields, no hon. Member can sit and talk or even stand and talk.

Shri Priya Gupta: But he also cannot say all these things.

Shri Vasudevan Nair: I do not know to what the hon. Member is objecting. I did not say anything that Shri Hem Barua did not mention.

Mr. Deputy-Speaker: It would be better if the hon Member addresses the Chair.

Shri Vasudevan Nair: I was only quoting word by word what the hon. Member said in this House the previous day. I did not distort his speech; neither did I say anything which he has not mentioned. Therefore, I do not know why we should furnish materials for propaganda by Peking by saying such things as our country is thoroughly isolated. Is it a correct thing to state that in this dispute with China the Government and people of India are isolated from other countries? As a matter of fact, it is a development which we should welcome that even Communist countries, many Communist governments, are siding India and hoping that this problem should be solved with dignity and honour to the Government and people of India

Shri Yogendra Jha (Madhubani): Has any Communist country supported our case with China on merits?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The hon. Member may kindly sit down. He should not interrupt like this unless the member in possession of the floor yields.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): May I draw your attention to the fact that interruptions like this are part of established parliamentary practice?

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry, I have to differ from him.

Shri Yogendra Jha: May I know from the hon Member....

Mr. Deputy-Speaker: Unless he yields, no member can go on talking.

श्री योगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक भी कम्यूनिस्ट देश ऐसा है जिस ने हमारे इस केस का समर्थन मेरिट्स पर किया हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

Shri Vasudevan Nair: The point is that our viewpoint is very much appreciated all over the world and India has received such moral support from all corners of the world that today China, because of her reluctonce in accepting the Colombo proposals, is standing isolated from the rest of the world. If people are not able to appreciate or understand that position, we can only sympathise with them. I would not like to say anything more on this matter.

Then I come to the Afro-Asian Solidarity Conference. My hon. friend was ridiculing the Indian delegation by saying that they were walking in and walking out like a circus horse. Of course, he can use any phrase he likes. Whether Shri Hem Barua likes it or not the Afro-Asian Solidarity Conference is a movement where the representatives of Afro-Asian people assemble.

Shri D. C. Sharma: They represent only themselves.

Shri Vasudevan Nair: Our representatives, including responsible Members of Parliament, going there and putting our case before those representatives is a good thing and it is to be welcomed.

Shri D. C. Sharma: They have done nothing of that kind.

Shri Vasudevan Nair: It is not to be ridiculed. The Chinese propaganda is there. We have to face that. We have to present our case to the other countries. Insted of facing the problem, if people go on maligning such people and running them down, that does not help the country. Incidentally, that may help the propaganda apparatus of Peking, because they can quote these things. So, on this problem, as the President has tried to say, though on very vague terms, we stand very firm and we are strengthening our armed forces. At the same time, we will avail of every apportunity for peaceful solution with dignity and honour.

Then I will pass on to another subject where I will have to criticise the Government to a certain extent. At the very outset, before I thouch upon the subject, I would like to point out to the representatives of Government in the treasury benches that we are not making these remarks with any intention to say something against the Government.

Mr. Deputy-Speaker: He has three more minutes.

Shri Vasudevan Nair: It is not as if we want to criticise government on some count or another. At the same time, we want government to realise the false steps that they have taken during the period of the emergency. As far as collections to the National Defence Fund are concerned, many instances were given by our leader in his speech about the partisan method adopted by many States in India. Though I have got many such instances with me, I will just quote one instance here, and I want the Congress members to listen to this. In my State of Kerala, the Congress Committee has sent out a circular to the district committees, asking for lists of name of people to be recruited to the Home guards. These lists were being seupplied to the Government officers for recruitment to the home guards. This has not been denied by the Congress or the Government. Actually, when the issue was raised in the Legislative Assembly last week we were surprised to see that the Government representatives were almost trying to justify it by asking what is wrong in that? Is there nothing wrong in the recruitment to the home guards being made on the basis of lists drawn up by the Congress Committee? I would like the Congress members to ponder over this question. I would also I like the Home Minister to inquire about it as to whether it is true. If it is found to be true, I hope suitable action will be taken to rectify the matter.

Shri D. C. Sharma: They would have given lists of people belonging to all parties.

Shri Vasudevan Nair: That is one interpretation which can be put on it by my esteemed friend, Shri Sharma.

Shri Tyagi: Since the hon. Member has named my party.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Tyagi: Sir, he has yielded. I would like to know what type of objection he find in the Congress organisation suggesting a list of names to some subordinate bodies.

Mr. Deputy-Speaker: That is a matter of opinion. You may differ from him.

Shri Tyagi: I would like to know his objection to this.

Mr. Deputy-Speaker: Let him have his own opinion.

Shri Vasudevan Nair: The motive is clear to every one. When a political party prepares a list of people to be recruited to Government service—and home guards establishment is Government service for all practical purposes—it will include the names of members of that party alone.

Shri Tyagi: Are they paid anything?

Shri Vasudevan Nair: Also, that goes against the very spirit of the Constitution.

Shri D. C. Sharma: Are there not members of his party in Government service?

Shri Vasudevan Nair: Then there have been complaints that the formation of the village volunteer force was also based on the list prepared by the ruling party. There are many such instances which do not at all contribute to the growth of healthy traditions in this country. So, Government, specially the Home Ministry should look into such cases and take suitable action to prevent such abuses of power.

Lastly, I would like to refer to the arrests of a large number of people of this country, which has been mentioned by other speakers also. I would like the hon. Home Minister to tell us whether he has got a single case of any such arrested member obstructing the defence effort or standing against the declared policy of this government.

Shri K. N. Tiwary (Bagaha): May I know from the hon. Member....

Mr. Deputy-Speaker: He is not yielding.

Shri Vasudevan Nair: Can he point out a single instance in the last four months of any responsible Communist party leader, arrested or not arrested, having obstructed the defence effort or opposed the policy of this government on this question? I am sure he will not be able to produce a single case. There is no justification for suppressing the most important opposition party in this country, which has offered its unstinted and complete support to the policy of the government. If the Government is prepared to rectify the mistakes that it has committed and if the Government is really prepared to mobilise the entire nation on a popular programme, or a real socialist programme, then we can be confident enough that we can meet any challenge that comes from any quarter without looking for or depending upon any kind of help from outside.

Shri Gajraj Singh Rao (Gurgaon): Mr. Deputy-Speaker, I rise to suport the motion of thanks before the House. There are two very important phrases which are elementary things but which have been very diversely interpreted here in this House. One is non-alignment. By non-alignment it has been taken in some quarters that we are aloof from the whole world in regard to all matters, may be defence or any-

thing. On the other hand, according to the ideology to which particular gentlemen belong, non-alignment means that if we do not subscribe to their ideology, we are non-aligned. The other is emergency. It is said vehemently that China is never to be trusted, that it is a nation which has betrayed us while calling us friends and that while we trusted them as friends, they are on the border mobilising their forces. Still, it is said that there is no emergency. These are very contradictory things and I would respectfully submit to my hon. friends on the Opposition Benches that such speeches will not help our defence effort and that the defence of the nation is common to all of us whether we sit on this side or on that side. That should be the position that we should take.

There are some elements which have become patriotic overnight. We welcome it that they are patriotic now and support the national cause against the Chinese who are no longer the ultra-Communist creed. We welcome them, but is it not known to everybody in India who knows India that there have been saboteurs and that there have been people who have been giving out news that has been helping somehow or the other the Chinese before the aggression began? Can any responsible government sleep over these matters? No. Certainly, those who are not saboteurs and who are not undermining the nation's security are not to be taken into custody under the Defence of India Rules; but those who are undermining it should be arrested. I should say that this is the gravest emergency that exists and the emergency should continue.

It has been said by one or two groups that there has been coercion for contribution to the National Defence Fund. Such like things have been said. Would it help? Even if there are a few such instances out of lakhs and lakhs of them, would it help? I would say, 'No'. I can safely say that the poorer section of the people, the Kisans and specially the village people, have voluntarily come forward with all the money for the National Defence Fund. If it is lacking, it is the rich factory owners and the big businessmen who are not coming forward for contributing to the National Defence Fund. Just near Delhi, in Faridabad you can see that the labourers have said that they will give one day's pay and other contributions *per capita*. But what have the others done? I should say that in this emergency the big business people should have been the first to come forward because the risk is the greatest for them and the Government has given them every help from every country. But what are they doing? Have they come forward and said that now they would manufacture at least for one month in a year things which are required for our Army and for our Jawans who are fighting for us? Has any company or any factory come out with such an offer? The masses want the integrity and honour of India and to live as a self-respecting nation and not under the continued threat of China, Pakistan or any other country.

About China I need not say anything. It has been said by so many hon. friends that we should be clear in our mind. There are old saying by Shastris, Sanskrit scholars and by others, but as a layman coming from a village I can only say this. Never trust persons whom we had been supporting to the last even estranging our relations with our friends sometimes—we have gone to that extent—but who, still, stabbed us in the back and proved to be the worst aggressors. I would plainly say that these Colombo talks or some other talks by Afro-Asian nations have slackened our efforts. From my own experience I can say that now this is the general talk among the public who, as a nation, had risen to the occasion. Now they plainly say, "Oh! it is going to be a simple affair.

[Shri Gajraj Singh Rao]

As we never got back Kashmir, we are never going to get back those portions which we have lost to China. There are going to be only talks and talks." But still I would say that our acceptance in toto of the Colombo proposals has raised our prestige in the world, that even with a most treacherous nation who played a most scandalous part as friends we are still prepared to talk on the intervention of some friends. But still that is not there. Even now the Chinese position is not clear and we are debating it here like a debating society. We should not do that. We should be prepared to defend ourselves with our own resources and with our own strength.

It is said by some quarters that we should align with one bloc or with the other bloc. Why? Our war is with China. It is not even with the Chinese people but it is with the Chinese Government. They may happen to be Communists. Why should we deplore the whole Communists world and say, "You are our enemies" and then ask the other side, the non-Communist countries, to come and make India, our homeland, the battlefield of the two blocs? Should we invite them? Is that the logic behind this theory that is talked about? Our non-alignment policy is the best policy at this juncture. We are not going to invite anybody to help China or to give suggestions that they may be forced to help China. We should be restrained.

So far as our friends are concerned, paragraph 10 of the Address is very clear where it says that we are thankful to the United Kingdom, America and other friendly nations who at the time of crisis have come to our help. Is that not a clear indication? Is that not a clear statement of the policy of our Government? If it is not that, what else is it? I can say with experience that my nearest and dearest—I do not say that I have got so many; every Indian is my kinsman—are on the battlefront. They should be encouraged by our action, by our speeches and by our doing here and outside in the country. If they are well armed from friendly countries with proper arms and equipment, our one soldier can fight the Chinese. That I can say. That is not only my experience. Read what is said by the press. Two lines from the *Tribune* of the 18th December, with your permission, Mr. Deputy Speaker, I may read.

> "The dream of the Chinese was shattered by the heroism and bravery of Indian troops who fought almost to the last man at Rezang La and Gurung Hill near Chushul, writes a P.T.I. correspondent.
>
> Except six or seven men, a company of Ahirs perished at Rezang La, but not before inflicting heavy casualties on the invaders. A company of Gorkhas on Gurung Hill also dealt heavy casualities on the advancing waves of the Chinese."

In the foreign press also these heroic deeds have been praised. If my friends want to learn about them, how they fought, I have got men who have returned from there. If we go to them we do not go to them for mourning. We go to congratulate them: you people have fought like anything at Chushul. If we hear that, we should not have been able to say what we have been talking here inside and outside. These brave people, two companies have been wiped out and still they are sending letters: you come from Parliament and visit our places and see with what arms and ammunition and how bravely we have fought. I would most respectfully submit that there is not a word in the Address about how bravely our people have fought. There should have been mention about these brave people.

What about development? I can frankly say that block development is blocked development. If this defence work is given to these block developments, they will block the defence of India, finish the defence of India. They are making people quarrel in the vil-

lages and litigate unnecessarily and then report, we have gone for defence purposes and we had been making speeches. This is what they are doing. I am a born villager. Certaily this is my experience. I can go to any resident in any village and I can show what they are doing, actually helping our defence or retarding our defence.

The second front is agriculture. I am thankful to the Minister of Agriculture for giving us a patient hearing. Look here, the soldiers, the men are on the fighting front. Boys, old men and women are working in the fields. For luxury purposes of the people who are only talking and reading papers and having things this way or that way they say electricity is there. But, for the supply of electricity for the wells, the time was changed in this winter from 8 p.m. to 12 p.m. The women folk of these brave soldiers have to go and water the fields. Is this the way of helping agriculture? Are we helping? I would say, we should fully sympathise with these people. We should give the first priority to our brave soldiers who are fighting without caring for their health, hearth or home. That is what I would submit.

Mr. Deputy-Speaker: He has taken 15 minutes; his time is up.

Shri Gajraj Singh Rao: In one or two minutes, I will finish. There is an Ilaqa called Hariana prant near about Delhi. It may be called old Delhi territory. It is being victimised because they mutineed against the Britishers in 1857 and that is going on in the same way for the last 107 years. The biggest usury on loans is 2 per cent, 3 per cent or 5 per cent. One hundred years and seven years more: is it not a usurious loan? This is going on. I would submit there is an army of profiteers and blackmarketeers. Instead of the other army, they have come to the fore. They are crying sometimes against gold control and sometimes some other thing. That army must be checked ruthlessly under the Defence of India Act. This emergency should be used against them who are harassing the whole nation and are detrimental to the growth of the nation. That I would submit is the proper application of the Defence of India Rules. They are not touched by anybody. They are rather posing as if they are the leaders and masters of India and not the Government This much about profiteers and blackmarketeers.

I was just now submitting about the Hariana prant. I can say about my own constituency. Four hundred are missing or dead. But, none of them have come to say that we are not going. Their women have come to say, send us to the front. For 100 years, this area is victimised on the pattern or on the analogy of what the Britishers did. I would declare it a politically suffering area. That wrong should not be done. They are coming in thousands and thousands. I can say that every soldier from my area is at the disposal of this House and this Government. They are ready to help and go anywhere as volunteers. They have offered themselves. In these circumstances, at least we should have pity on their womenfolk and their children I have just now said that for the sake of luxury of other people, these womenfolk are made to suffer. That is a shame on us. We should congratulate them. We should certainly help them at least in their humanitarian demands. We should go to them and say, well, you have done your duty, we are at your disposal.

I thank you for having allowed me sometime to say something very frankly.

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North): Mr. Deputy-Speaker, with great pleasure do I associate myself with those who have extended a hearty vote of thanks to the President for his Address to the Joint sitting of the two Houses on the 18th of February.

The President's speech was strictly in keeping with the nobility and magnanimity of his personality and also the dignity of the nation. In

[Dr. Sarojini Mahishi]

fact, he gave a clarion call to the nation saying:

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत

I wish to add a couplet from the Brahmana literature:

आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ।
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भाग : ।।

In the case of a person who sits down, his fortune also sits down. In the case of a person who moves about, his fortune also moves about. In the case of a person who lies down, his fortune also lies down. In the case of a person who rises up, his fortune also rises up. We are a moving nation. We are a nation who have responded to the call of the country. We are a nation who have readily united to face the national emergency.

The President has rightly referred to the different developments that have taken place in the country. Within the short period of an Address, I do not think it would have been possible for the President to cover all the subjects on the surface of the earth. He has rightly, with all dignity, referred to certain matters and problems which are now before the country. The first one was agriculture. Land in India is the main source of our income. More than 50 per cent of our national income proceeds from the land. And 70 per cent of the people in India live on agriculture. But the fluctuations of the agricultural produce mainly depend upon the vegaries of the monsoons, and we must note that also. Therefore, whatever facilities are necessary for helping agricultural development must always be encouraged.

But to my utter dismay I may say that even the irrigation potential which has been created has not been fully utilised, and the different schemes that have been sanctioned have not been fully implemented. The Second Finance Commission gave a report that even the interest charges on the amounts invested in the creation of irrigational facilities were not being recovered, and so is the opinion of the experts in agriculture also. What are the causes for the non-utilisation of these facilities? That is a matter which we must investigate into. We cannot go on saying always that it is the cultivator who should make use of these facilities. I must say that the officials also should give a correct idea and a correct picture of all these facilities and thus try to help the poor agriculturists who have no idea as regards these things.

Many a time we have got laudable statistical figures on record saying that so much of medium-term loans had been given, so much of short-term loans had been given and so much of long-term loans had been given. And we say also that the short-term loans have been expanded from Rs. 30 crores to Rs. 150 crores, which is nearly five times, and so also the medium-term loans have been expanded from Rs. 10 crores to Rs. 50 crores during the Second Plan period and so on. But at the same time I would ask, with all these figures on record, why the output is not there, and why the outcome is not up to our expectations.

We expected that there should be a 6 per cent increase in agricultural production every year normally, but we see at the same time that during the preceding decade, the increase in agricultural production has been to the extent of something like 3·8 per cent only, and the total fertility rose only to the extent of 1·5 per cent or so. Why is it that we are lagging behind in respect of all these things? That is a serious question to be considered, and I hope that the concerned

Departments and the Agriculture Ministry will take all these things into consideration. Not only should the irrigational facilities be created by sanctioning money, not only should the agriculturists be helped by proper publicity being given to the different schemes and so on, but we should also see that there is consolidation of landholdings, proper distribution of fertilisers, proper supply of power, proper supply of improved seeds and so on, because all these things also go a long way in promoting agricultural development. I hope the officials concerned will take greater interest in implementing the schemes and in enlightening the poor cultivators on this aspect also.

The second point that had been referred to by the President in his Address is that we have in our country today a lot of development in the industrial field also. There also, I must say that we expected an increase of something like 9 per cent in the physical target, but during the preceding year we saw that there was only a 6 per cent increase in industrial output. No doubt, we are a democratic country, and we wish the people to participate at every level, and we wish that in a socialistic pattern of society, the means of production should be distributed in the proper way. At the same time, we see that the investments made in the public sector are not fully paying. Why is it that they are not fully paying in time? What supervision and what sort of control are being exercised?

Recently, I read in the papers that the Planning Commission was going to pilot a study in order to initiate a proper evaluation of the work done in the public sector. At the beginning of the First Five Year Plan, the amount invested in the public sector was to the tune of Rs. 21 crores, and subsequently it grew up to Rs. 81 crores or so Now, in the Third Plan, I think that it comes to about Rs. 2500 crores covering not less than 20 great or heavy projects, including the steel plants of Rourkela, Bhilai and Durgapur, the Hindustan Machine-tools Limited, and the Indian Telephone Industries Limited and such other factories. It is an appreciable thing. The study team is going to evaluate the work done and also suggest measures for remedying the loopholes and the lacunae that exist on account of which a proper output could not be there.

I learn that the national laboratories in our country also could not give out the correct results or the anticipated results within the period expected, and I was surprised to read the other day that the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs was going to take the services of world experts in the matter of evaluating the work done in our national laboratories, at least those laboratories which have already put in work for some ten years now. I think that out of the 23 national laboratories in the country, more than 13 will be completing their service of ten years, and the working of all these is going to be evaluated by the world experts. Are our Indian experts and scientists not able to evaluate the work done in our national laboratories? What were we doing during all these years? This again is a problem to be considered.

The President has rightly referred to the fact that 50 million children in our country are undergoing education at the primary level. In addition to that, he has also referred to technical education. Is it on account of the shortage of hands in the technical field that the retirement age of Government servants especially in this field was extended from 55 to 58? If there is such a shortage, on account of which the retirement age had to be increased to 58, I would like to know what efforts are being made to increase the number of educational institutions that are imparting technical education in the country, and to what extent the shortage has been met. That is also a thing which has to be

[Dr. Sarojini Maheshi]

looked into. No doubt, university education, primary education as well as secondary education are being attended to. In spite of all these things we find at the end of the Third Plan that only 60 per cent of the children in the age group from 6 to 11 would be attending the primary schools. So, the physical targets in these fields also could not be met.

Even at the university level, I would like to refer to one thing. No doubt, the universities are autonomous bodies. At the same time I would like to draw the attention of the concerned Ministers and also of this House to the fact that an autonomous body which frames rules is not a master to violate its own rules and thus create a bad precedent in the country. I am especially referring to the Gauhati University about which the Pavate Committee has submitted its report; we know that that committee has stated that the University never cared to conduct examinations regularly, and never cared to hold convocations regularly; and *The Indian Express* dated the 31st August, 1962 came ut with an editorial 'Shocking, Shocking' and pointing out that this was the shocking state of affairs in the country. That university was given huge grants by the University Grants Commission. I think that the university's work does come under the supervision and control of the concerned Ministry and also of Government. But herein, of course, things were never taken into consideration, until the students raised a hue and cry that an enquiry committee should be appointed to go into the matter and investigate. I am really sorry to see this sort of affairs existing in our country even during the year 1962.

Therefore, I would say that with all our broader ideas and outlook on education, with all our appreciative schemes of education, let us not shut our eyes towards this scandalous state of affairs which exists in the country, and let us be clear that we must remove all the lacunae and drawbacks, and try to correct ourselves and see that the youth of the country get proper education.

I am sorry to say that there is also inefficiency in the administration. Efficiency and integrity are expected at all levels of administration. No doubt, we are a democratic country, and we wish that the people should participate, and that the people should take interest at all levels, from the topmost level to the bottom-most level. At the same time, we should see also that efficiency and integrity in the administration are kept up, right down to that level where they come directly into contact with the people.

I was sorry to read in today's papers that it appears that income-tax arrears to the tune of Rs. 253 crores have not been recovered. We are saying so many things about the National Defence Fund and that every naya paisa that is given to the National Defence Fund should be utilised for the proper development and the defence of the country, and every pie or farthing that is given by the poor labourer should be utilised for this purpose; it is the expectation also of the labourer and he desires also that every pie that he contributes should be utilised for the proper purpose. Apart from all the criticism that we hear in this House and outside, is it not the duty not only of Government but also of all the people and all the authorities concerned to see that proper utilisation is made of every naya paisa that is contributed to it? But we find that on account of the slackness in the efficiency of the administration, a sum of Rs. 253 crores could not be recovered, and the Public Accounts Committee of Parliament has recently exposed and brought this scandalous state of affairs to light, saying that the money could not be recovered, and even proper steps were not taken to recover the amount in spite of the recommendations made by the Direct Taxes Inquiry Committee to take proper steps in the matter.

In addition to this, on account of under-assessment and also efforts made to evade tax, huge amounts could not be collected. I hope the authorities will properly look into these matters.

The people of our country are united irrespective of caste, creed, sect or place of birth; every man and woman from every nook and corner of India have come forward to do their bit in the face of the emergency. It is the spirit behind this union, it is the spirit of this unity, which has responded at the proper time to the challenge posed by the Chinese that is all-important. Indian history shows that for want of unity, India suffered a lot. We have learnt a lesson from that. Therefore, the people have risen to the occasion and responded fully.

I do not wish to say much about the Gold Control Rules. But women have contributed a lot. Wherever I have gone in my constituency or even outside it, I have found the poorer women coming forward with their ear-rings and nose-rings voluntarily without even consulting their household members.

We have heard much about the Colombo proposals of course, with a few dissenting voices, the House has accepted the proposals. Outside the House, I have found good response in regard to our acceptance of the proposals. I do not know whether it is an unfortunate coincidence that the Communist Party has got an opinion similar to that of the ruling party. It is perhaps on account of this unfortunate coincidence that my hon. friends in the Opposition have criticised us severely. Perhaps they think that it is the duty of the Opposition to oppose everything said and done in the House by the ruling party. I do not know how many of them are able to realise their duty. Of course, it is the duty of the Opposition to guide the Government properly when it does not go on proper lines. But many of them seem to be under the impression that because they are in the Opposition, therefore it is their duty to oppose everything said and done by the ruling party. The behaviour of some Opposition party Members at the time of the President's Address clearly speaks volumes. They do not know what is their duty. Our love for our *lingua franca* or national language must not be exhibited by such behaviour. Let us love our language. Let us love our country. I am also a lover of Hindi. I know Hindi. Let us try to encourage Hindi, enrich its vocabulary and add to its literature by other means. This is not the means we must adopt for the purpose. We must maintain our dignity as Members of the House, we must maintain the dignity of the House and observe decorum during its deliberations.

The Colombo proposals have been very severely criticised by some friends of the Opposition. Taking into consideration, developments in the inernational field, I think they will revise their opinion in the matter. The spirit of understanding created between the East and West over the Cuba affair must be a guide to us also. The action of the USSR in withdrawing or dismantling its missile bases in Cuba has gone a long way in creating a good understanding between the east and west. Though our policy with China is not directly dependent on the withdrawal of missile bases, we must view this in the light of international affairs and the new developments that are taking place. Some experts go to the extent of advising us that we should not keep two borders alive. This relates to our negotiations with Pakistan and our going to the negotiating table with China. In the light of the new developments that are taking place in the world, I hope these things will be considered properly and in the proper atmosphere.

As the people of India, we have solemnly resolved to constitute India

[Dr. Sarojini Mahishi]

into a sovereign democratic Republic. We have solemnly resolved to safeguard our integrity; we have solemnly resolved to safeguard the honour of the country. We shall also solemnly resolve to fight for every inch of our country, safeguard the integrity of the nation and defend the country at any cost.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Koya—absent. Dr. M. S. Aney.

Dr. M. S. Aney: The Address of the President to the Members of Parliament assembled at a joint session summoned by him is an important pronouncement not only for the Members of the Indian Parliament but for responsible statesmen and diplomats of all the civilised countries of the world.

One of the factors that adds to this importance is the personality of the President himself. He is a profound and renowned scholar, a well-known philosopher of international fame, an eloquent speaker, a humanitarian patriot and a representative of Indian culture with a one-world-family outlook. "वसुधैव कुटुम्बकम्" The other factor consists of the peculiar conditions in which the Parliament is meeting.

The President has given in his Address a brief description as to how the Government of India has been trying to fulfil the objectives laid down in the Constitution and what degree of progress we have secured in making our long pilgrimage to reach the objective of a democratic and socialistic order and how we have adopted planned approaches to that end.

The President has told the world that notwithstanding our preoccupations in internal affairs 'we took purposeful interest in international affairs, always laying stress on the vital importance of world peace'. This was the first illusion. 'On some occasions', the President mentions with considerable pride, 'our participation made a difference and helped the cause of peace'. The President has very delicately suggested that 'we had hoped not only that world peace would be progressively assured but that we also would continue to live at peace with our neighbours',—this is the second illusion—and that any problems that arose would be settled by peaceful methods'. This is the third one. While the Government of India were living in a state of complacency and sense of self-satisfaction, events were occurring in Pakistan and in border territories between India and China, which began to give a rude shock to the pleasing dreams which the Government of India were having.

I do not want to give here the story of the betrayal by China whose Prime Minister pledged his faith in *panchsheel* while he had been visiting this country as an honoured guest, adored and respected not only by the Government of India but by the people of India also. The whole episode of Chinese invasion of Ladakh and NEFA in utter disregard of previous friendship, plighted word and of all international conventions is one of the most disgraceful events in the latter part of the 20th century. No incidents in the first world war or the second world war can be compared to what the Chinese had done in violating the Indian borders. We will find parallel to it only in the invasions of Chengiz Khan, Tamerlane and Nadir Shah, who had invaded India, slaughtered innocent people, looted cities, carried fire and sword everywhere and then voluntarily returned with their hordes and the booty and wealth they were able to get. The spirit of China has all the trace in it of that barbarism which the historian has condemned in the strongest terms in the pages of history. We are dealing with a nation of that kind. I am glad to find that the President has characterised the conduct of the Chinese as gross

betrayal and further stated that "inevitably the first duty of the nation in these circumstances was to meet this aggression effectively and to prepare the country to that end" I only wish to add that the President evidently meant by using the word 'effectively' that the aggressor must be required to vacate every inch of the Indian territory which he had surreptitiously, forcibly brutally occupied. This and this alone can be an honourable end of the situation created for us by the Chinese warmongers and in keeping with the solemn oath which the Speaker administered to all Members of the Lok Sabha.

14 hrs.

In this connection, the President has laid down another principle for the guidance of those who have to administer the country and deal with the situation. He says:

> "The issue of the Chinese Aggression has been and is today the over-riding issue before us and everything else has to be considered in that context. The freedom and honour of a country must be given the first place and if a country cannot defend them, then other matters lose significance. National activities have thus been concentrated on this issue."

I appreciate, like the President, the utility of several steps taken such as the formation of National Defence Council and starting of a National Defence Fund. Similarly measures to expand our Armed Forces and increase production of ordnance factories, etc. are all welcome. But all this has value if they make us strong enough to defend ourselves.

The situation created by the withdrawal of the Chinese forces in one of seeming peace and not of real peace. India cannot have a real peace unless the aggressor vacates the territories forcibly occupied. So long as he is on any part of the Indian soil, however small it may be, with his army, he is standing and holding a pistol to the forehead of the motherland. We cannot afford to ignore that.

It is stated and rightly stated that we would require considerable period to be fully prepared and equipped with modern weapons, to successfuliy challenge the Chinese forces to drive them out of India or to compell them to sue for peace.

But the question is that China under the term of her own unilateral withdrawal will be in occupation of considerable part of Indian territories in Ladakh and even in cerain parts of the so-called middle sector. The Chinese may not remain quiet and may think of invading India at any time before the Indian army is fully expanded and adequately equipped. If they make such a movement, is there no danger of ourselves being again taken by surprise and again found unprepared to meet them? I ask what is the force or power on which India can rely for quick help or assistance to fight the enemy? I do not want the Government to make any statement as regards the details of some such source to fall back on in case of a contingency which cannot be ruled out as improbable. If the House be assured by the Minister of Defence that the Government is fully prepared to meet such a contingency, then the Indian people will feel themselves secure from such a menace, even if they keep the detailed inforation a close secret. But the Government spokesman must be able to reply that we are preparing and shall be preparing fully to defend the country in a contingency of that kind. I wish to admit however that the statement made by the Prime Minister in reply to Shri Kamath's motion on air-umbrellas the other day has shown that the Government is not only alive to this danger but is proceeding courageously. though courageously on right lines to be pre-

[Dr. M. S. Aney]

pared against any danger of surprise attack by the enemy.

I wish to state that in the whole Address of the President the determination of the Indian Government to defend the integrity of India has been duly emphasised but the words "they will not stop till the Chinese are driven out of the Indian soil" are not specifically mentioned. In my opinion that is obviously implied in the language used by the President. But it will be better if the Prime Minister will make that point perfectly clear and leave no ground for ambiguity or equivocation. I have no doubt that the Government of India respects freedom and integrity of Indian territory as of greater and more vital importance than the adherence to any principle of policy which is but a means to an end and not an end in itself. Alignment and non-alignment are mere words. They may be looked upon as two facets of the same coin at times hardly distinguishable from each other on account of long use. What name the policy may have can be considered at some future time after the catastrophe has ended. Looking at the substance and not at the form, I reaffirm that the Government of India must have a few friends in the civilised and powerful nations on whose help it can count in case of a sudden attack by China on India again. If you think you can have that by persisting in talking of your policy as one of non alignment, I have nothing to say against it.

One word about the Colombo proposals. We have accepted them as clarified by them later on. I give the Colombo powers credit for their bona fides and appreciate whatever efforts they had made hitherto with good motives. But the members of this group have called themselves non-aligned. They have no time to study our case and closely follow the aggressive movements of the Chinese. They somehow want us to meet China and have direct negotiations with them now. That is the aim of China also. They have not shown the courage to name China as the aggressor. As common friends their opinion on Chinese invasion would have helped bring round China to a more reasonable frame of mind than their non-committal attitude on a vital issue like that. However, we have accepted the proposal as clarified by them and I beg to remind the Colombo powers that they should do their duty as common friends even now without fear or favour bearing in mind the words of highest wisdom which the great sanskrit poet Bharavi has uttered:

"हितम् मनोहारि च दुर्लभम् वच"

It is seldom that the advice will be both salutary and pleasant. That is the duty of a friend who stands for truth and spurns flattery when they talk of serious matters and not indulge in jocular talks.

Our preparations must continue. We have accepted their proposals. We have to wait for some developments in some quarters of which we have no idea. We must concentrate our efforts—war efforts and other efforts that are conducive to the war efforts.

I submit that India must take the first opportunity to give notice to the Chinese to vacate the territory illegal occupied by them after we feel we are fully prepared. If no reply is received from them, it will be the duty of the Government of India to take other steps to drive them out of the positions and not sit waiting with folded hands for what the aggressor may or may not do.

Our preparations must have this aim. All sacrifices the people are required to make in the state of emergency demand that the Government of India is pursuing its objective of regaining the lost territories from the Chinese. This alone can

sustain the people's enthusiasm, and I have no doubt that the Government will not slacken in their war efforts and remain adamant in their determination to regain our territories and our prestige as a brave and self-respecting people.

This, Sir, is what we owe to India and particularly to those brave jawans who have shed their blood and laid down their lives in the defence of the motherland. I feel somewhat disappointed to find that no reference was made to this supreme act of self-sacrifice of our jawans in the President's Address.

Without aiming at and achieving this objective with regard to our lost territories and restoring the integrity of our Indian motherland, we shall not prove curselves worthy of the awards, *varas*, which the President has so earnestly asked us to strive for, in the language of the holy Upanishads: *Uttisthata jagrata prapyavaran nibodhata*,—Awake, arise, and realise your aspirations.

In conclusion, I thank you for giving me an opportunity to express my views. I support the motion moved by my hon. friend Shri Pandey.

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष माननीय सदस्य, श्री पाण्डेय, द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद-प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे मनीषी राष्ट्रपति ने यह उचित ही किया कि उन्होंने अपने भाषण के आरम्भ में समाजवादी व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। समाजवादी व्यवस्था केवल एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि वह जीवन को एक नई दिशा देने का सिद्धान्त है। आज की दुनिया की बहुत सी दुरवस्था तब तक समाप्त नहीं हो सकती, जब तक कि सब देशों में समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती। माननीय सदस्य, श्री रंगा, ने यह चिन्ता प्रकट की है कि हमारी योजनाओं से, समाजवादी योजनाओं से देश का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, वह नष्ट हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि श्री रंगा की चिन्ता का विषय क्या है। क्या श्री रंगा उस सामाजिक ढांचे के नष्ट होने से चिन्तित हैं, जिस में एक इन्सान दूसरे इन्सान से नीचे है? क्या श्री रंगा की चिन्ता का यह विषय है कि वह आर्थिक ढांचा नष्ट हो रहा है, जिसमें मुट्ठी भर आदमी मौज उड़ाते हों और अनगिनत लोग हैवान की जिन्दगी गुजार रहे हों?

जहां तक समाजवादी व्यवस्था का प्रश्न है, उसके प्रति हमारे देश की आस्था बहुत पहले से चली आ रही है। सच तो यह है कि हमारे राष्ट्रनायक, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, १९३६ से ही जबकि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापतित्व स्वीकार किया, हमारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करते चले आ रहे हैं और इस सिद्धान्त की घोषणा और इसका समर्थन देश में सैकड़ों नहीं हजारों मंचों से बराबर होता चला आ रहा है। तब से लेकर अब तक, जब कि हम स्वतंत्र हुए और हम को अपने देश को एक निश्चित दिशा में लेजाने का अवसर मिला, हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश का नेतृत्व उस दिशा में सफलता पूर्वक करते चले आ रहे हैं।

स्वतंत्र पार्टी की सदस्या, महारानी गायत्री देवी, ने नेतत्व में परिवर्तन की बात कही है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेतृत्व में परिवर्तन तो तब हो गया, जबकि दुनिया में फ्रांसीसी राज्य-क्रन्ति हुई। वह जमाना लद गया, जबकि लोग गाया करते थे: "यशस्वी रहें हे प्रभो, हे मुरारे, चिरंजीव रानी व राजा हमारे" यह जनयुग है, जनता के प्रतिनिधियों के

[डा० महादेव प्रसाद]

हाथ में देश का नेतृत्व है। जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में नेतृत्व इतिहास के विकास के क्रम के परिणामस्वरूप आया है और इतिहास के विकास के क्रम को पलटना अब राजाओं और रानियों के वश में नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने कुछ बुनियादी सिद्धान्तों में अपनी आस्था प्रकट की। उनके उदात्त नेतृत्व में हमारे देश ने इस सदन में और इस सदन के बाहर कुछ मूल्यों में अपनी मान्यता प्रकट की। वे मूल्य और वे सिद्धान्त भारतवर्ष की विशेषता रहे हैं और उन्हीं मूल्यों और सिद्धान्तों की भूमिका पर खड़े हो कर हमारे देश के अंग्रेजों ने विश्व को अपने चरित्र की शिक्षा दी।

एतद्देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना :
स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पथिव्यां
सर्वमानवा :।

राष्ट्रपति जी ने कृपा कर हमारा ध्यान अपने भाषण में इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि जहां एक ओर हमारा यह उद्देश्य और लक्ष्य है कि अपने देश में हम सब के लिए सुख और समद्धि प्राप्त करने की दिशा में योजनायें बना कर आगे बढ़ें, वहां यह भी आवश्यक है कि हम दुनिया में शान्ति-स्थापना की चेष्टा भी करें। इस ओर हम बराबर प्रयत्न करते आए हैं। ये हमारे सिद्धान्त, हमारे मूल्य और हमारी आस्थायें हैं। ऐसा नहीं कि इन सिद्धान्तों, मूल्यों और आस्थाओं पर हमले नहीं हुए। हमले हुए। बाहर से और भीतर से भी हमले हुए। लेकिन २० अक्तूबर, १९६२ को एक बहुत बड़ा हमला इन सिद्धान्तों और मूल्यों पर हुआ हमारे पड़ौसी देश चीन के द्वारा। यह सही है कि इस हमले के परिणामस्वरूप चीन की फौजों ने हमारे देश के एक काफी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने कब्जा तो किया, लेकिन उस समय देश एक व्यक्ति की तरह एक साथ उठ खड़ा हुआ। हममें जो अभूतपूर्व एकता आई, उसके परिणामस्वरूप चीन को पीछे हटना पड़ा और वह पीछे हटा। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है, यह हमला केवल जमीन के एक टुकड़े पर ही नहीं हुआ, बल्कि हमारे बुनियादी सिद्धान्तों पर हुआ। अगर चीन हमारे बुनियादी सिद्धान्तों पर हमला करे, अगर चीन की यह कोशिश हो कि हम अपने सिद्धान्तों को त्याग दें, तो हम को कोई ताज्जुब या आश्चर्य नहीं होता है। किन्तु हमारे देश के लोग ही उन आस्थाओं और उन मूल्यों को ठुकराने की बात करें उन नीतियों को छोड़ने की बात करें, तो ताज्जुब होता है।

हमारे मित्र, श्री बृजराज सिंह, ने सैनिक गठबंधनों से अलग रहने की हमारी नीति के विषय में कुछ कहा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतने वर्षों के बाद भी उन को यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सैनिक गठबंधनों से अलग रहने की नीति का अभिप्राय क्या है। उस नीति का मतलब यह नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर, उचित होने पर, हम अमरीका से सहायता नहीं लेंगे, आवश्यक होने पर हम रूस से सहायता नहीं लेंगे, या दुनिया के किसी और मुल्क से सहायता नहीं लेंगे। हमने इन मुल्कों से सहायता ली है। सच तो यह है कि आज दुनिया में कोई भी मुल्क अकेले, बिना किसी की सहायता या सहयोग लिए चल ही नहीं सकता है। इस सिलसिले में मैं आप की आज्ञा से यहां पर प्रधान मंत्री के उस भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं, जो उन्होंने इंडियन कौंसिल आफ़ वर्ल्ड एफ़ेयर्ज के सामने अपनी इस सैनिक गठबंधनों से अलग रहने की नीति की व्याख्या करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था :

"When I say that we should not align ourselves with any power blocs, obviously it does not mean that we should not be closer in our relations with some countries than with others. That depends on entirely different factors, chiefly economic, political and many other factors. At the present moment, you will see that, as a matter of fact, we have far closer relations with some countries of the western world than with others....These closer relations will no doubt develop and we will encourage them to develop, but we do not wish to place ourselves in a position where, politically speaking, we are lined up with a particular group or bound up to it in our future foreign activities."

श्रीमन्, श्री बृजराज सिंह जी ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के ही एक वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे । ३ जून, १९४८ को डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने एक वक्तव्य में रूस को निमंत्रण दिया था कि भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में और सुदूरपूर्व के देशों में भी, उनकी आर्थिक स्थिति को वह उन्नत करे । आज अगर हम रूस से कोई सहायता की बात करते हैं, या रूस से सहायता की आशा रखते हैं तो क्या कोई गलत काम कर रहे हैं ?

मैं, जहां तक चीन के साथ हमारी नीति का सम्बन्ध है, इस सदन का और आपका ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पहली तो सिद्धान्त की बात है और दूसरी तथ्य की बात । सिद्धान्त का जहां तक प्रश्न है, विचारने की बात यह है कि दो राष्ट्रों में जब झगड़ा हो तो वह झगड़ा या तो युद्ध से तय हो सकता है या फिर समझौता करके, बातचीत के द्वारा तय हो सकता है । युद्ध का रास्ता सर्वनाश का रास्ता है । इस सिलसिले में मैं महाभारत की एक कथा का उल्लेख करना चाहता हूं । महाभारत के विषय में स्वतंत्र पार्टी के नेताओं की और जनसंघ की प्रायः मान्यता है । राजाजी का कहना है कि महाभारत की कथायें ऐसी हैं जिन को पढ़ कर, जिन से नसीहत ले कर आदमी अच्छा आदमी हो सकता है, विचारक अच्छा विचारक हो सकता है । एक अवसर ऐसा उपस्थित हुआ महाभारत के समय में कि जब पाण्डव लोग इकट्ठे थे यह विचारने के लिए कि दुर्योधन तथा अन्य कौरवों से जिन्होंने उनके साथ बराबर विश्वासघात किया था, जिन्होंने उनको काफी सताया था और जिन की बातों पर विश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, उन से लड़ाई की जाये या नहीं । आप जानते ही हैं कि भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवों के सलाहकार थे । वह वहां पर मौजूद थे । उन से राय ली गई । भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो एक बार फिर जा करके दुर्योधन से शान्ति की बात, सुलह की बात करना चाहता हूं । धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने इसके जवाब में कहा कि आपका वहां जाना बिल्कुल बेकार है और आप वहां जायें, इसका मैं समर्थक नहीं हूं । उस वक्त भगवान् श्री कृष्ण ने जो बात कही, वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । उन्होंने कहा :

जानाम्येतां महाराज धार्तराष्ट्रस्य पापताम् ।
अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम् ।।

हे महाराज मैं जानता हूं कि धृतराष्ट्र कौरव किस प्रकार के पापी हैं । उनके पापों को मैं जानता हूं । वे किस प्रकार से अपने वायदे से मुकर सकते हैं, इसको भी मैं जानता हूं । लेकिन फिर भी मैं यह चाहता हूं कि संसार के राजाओं के सामने हम निर्दोष सिद्ध हो जायें और सब को यह ज्ञात हो जाये कि हमने शान्ति को कायम रखने के लिए अपनी तरफ से हद से बाहर जा करके कोशिश की है ।

[डा० महादेव प्रसाद]

दूसरी बात इस संदर्भ में जो विचारने की है वह भौगोलिक स्थिति की है । एक बात स्मरण रखी जानी चाहिये कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और यह जरूर है कि हम को उसकी तकलीफ है लेकिन श्रीमन्, चीन के विषय में हम कोई भी नीति निर्धारित करने जायें, पाकिस्तान के विषय में हम कोई भी नीति निर्धारित करने जायें, तो यह बात हम को ध्यान में रखनी होगी कि वे दोनों हमारे पड़ोसी थे, आज भी हमारे पड़ोसी हैं और आगे भी हमारे पड़ोसी रहने वाले हैं ।

राष्ट्रपति का मैं बड़ा अनुगृहीत हूं कि उन्होंने नेपाल से हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का उल्लेख किया है । मेरा अपना क्षेत्र नेपाल की सीमा पर पड़ता है । हम जानते हैं कि नेपाल के और हमारे कितने घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । सच तो यह है कि नेपाल और भारत के बीच की सीमा कोई सीमा ही नहीं है, वह तो मानने की सीमा है । हजारों लोग हमारे अपने क्षेत्र से नेपाल में काम करने जाते हैं, नेपाल से बहुत से लोग हमारे क्षेत्र में काम करने आते हैं । बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे और नेपाल के सम्बन्ध घनिष्ठ रहें । थोड़ी बहुत जो कमी इधर किसी कारण से आ गई थी, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे स्वराष्ट्र मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की यात्रा के फलस्वरूप वह दूर हो जायेगी और हमारे सम्बन्ध और भी घनिष्ठतम हो जायेंगे और जहां कहीं भी शिकन आ गये हैं, वे दूर हो जायेंगे। इतना होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल की सीमा पर जो हमारा क्षेत्र है, उस में सैनिक दृष्टि से हम को तैयारी मजबूत करने की जरूरत है । यदि सम्भव हो तो नेपाल और भारत सहयोग करके, दोनों की संयुक्त अगर वहां पर तैयारी हो सके, तो बड़ा ही उत्तम होगा ।

मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं । सीमा क्षेत्रों में यातायात की स्थिति अत्यन्त दयनीय है और उसको उन्नत करने की ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये । एक उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का देना चाहता हूं । सड़कों की बात तो जाने दीजिये, रेलों की स्थिति क्या है, इसको आप देखिये । नौतनवा सीमा से चार मील की दूरी पर स्थित है । वहां पर आनन्द नगर से एन० ई० रेलवे की लाइन जाती है । वह लाइन १८८९ ईस्वी में बिछाई गई थी । उस वक्त जब वह बिछाई गई थी वह ४१ पाउंड की थी । इस वक्त शायद ३० या ३२ पाउंड की होगी । १३ मील फी घंटा की रफ्तार से उस पर आजकल गाड़ियां चलती हैं । अजीब बात है कि अगर सीमा पर साधारण गाड़ियों की यह हालत रहेगी तो फिर किस तरह से युद्ध के लिए तथा दूसरी किसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सचमुच में हम तैयार हो सकेंगे । मेरा निवेदन है कि सीमा पर स्थित जो भी क्षेत्र हैं उन में जल्दी से जल्दी बड़ी लाइन बिछाई जानी चाहिये और उनको अच्छी से अच्छी स्थिति में रखने की कोशिश की जानी चाहिये ।

नेपाल से घनिष्ठ सम्बन्ध की मैं इसलिए भी लालसा करना चाहता हूं कि अभी पिछले साल हमारे जो क्षेत्र थे, देवरिया और गोरखपुर के जो उत्तरी क्षेत्र थे वे बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हो गये थे और वे इसलिए हो गये थे कि हम गंडक योजना को पूरी नहीं कर पा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि हमारे शास्त्री जी जब नेपाल जा रहे हैं तो गंडक योजना को पूरा करने की दिशा में भी वहां बातचीत करें ताकि अगली बरसात में हम बाढ़ से अपने उन क्षेत्रों को बचा सकें ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में योजनाबद्ध कार्य करने की ओर भी संकेत किया है । यह दूसरी बात है कि हमारे कुछ

भाई उसके खिलाफ हैं । योजना के फलस्वरूप देश एक कदम से दूसरे कदम पर जब आया तो प्रायः आगे बढ़ा, हमारी स्थिति अच्छी हुई । यह ठीक है । लेकिन हम जहां तक देश को ले जाना चाहते हैं, वहां तक नहीं ले जा पाये हैं, वहां तक देश को नहीं पहुंचा पाये हैं । एक बात इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं । योजनाओं से राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ी है, लेकिन गरीबों की सम्पत्ति उतनी नहीं बढ़ पाई है जितनी बढ़नी चाहिये थी । इसका कारण यह है कि हमारी जो योजना है वह खर्च करने की योजना है । केन्द्र के द्वारा और राज्यों के द्वारा कुछ रकमें हम खर्च करते हैं और लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस रुपये से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं । इन रुपयों से फ़ायदा जिन के पास रुपया है, जिन के पास शक्ति है, जिन के पास साधन हैं वे ज्यादा उठा पाये हैं और जो गरीब हैं, वे नहीं उठा पाये हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि तकावी के, अनुदान के, कर्ज के नियमों आदि में बुनियादी तौर पर परिवर्तन होना चाहिये जिससे गरीब भी इससे लाभ उठा सकें ।

आपात स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । यह भी कहा गया है कि जबर्दस्ती चन्दे इकट्ठे किये जा रहे हैं । यह बात हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने तथा स्वतंत्र दल के भाइयों ने भी कही है । जहां तक मेरी वाकफियत है मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है । किस तरह से इस तरह के आरोप लगा दिये जाते हैं, पता नहीं । एक तरफ कहा जाता है कि सुरक्षा कोष में सहायता देने के लिए सभी लोग उठ खड़े हुए हैं, स्वेच्छा से चन्दे दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है जबर्दस्ती वसूली की जा रही है, इन दोनों बातों की संगति नहीं बैठती है । जब लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं तो जबर्दस्ती का प्रश्न कहां उपस्थित होता है । इस प्रकार की बातें करके वे हमारे देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, यह उनके ही सोचने की बात है । एक कम्युनिस्ट भाई से मैं बात कर रहा था और मैंने उस से पूछा कि उनको यह सूचना कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि पेकिंग रेडियो से इसका प्रसारण हुआ है । पेकिंग रेडियो की बात के ऊपर विश्वास करके इस तरह के आरोप लगाये जायें और जो कुछ यहां कहा जाता है, उस पर विश्वास न किया जाए, यह कहां तक सही है, यह मैं उन से पूछना चाहूंगा ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपातकाल के होते हुए भी, हम को समाजवादी ढांचे को अधिक से अधिक मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का हृदय से आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया । इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार प्रकट करने के लिये मैं भी खड़ा हुआ हूं ।

उस दिन जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया तो एक अशोभनीय घटना घटित हुई थी, हिन्दी के विषय में, और वह हमारे अपने ही साथियों के द्वारा हुई थी । उस की जांच के लिये जो जांच समिति बनी है, हमारा उस में विश्वास है । हम यह अवश्य देखते हैं कि इस सदन का, दूसरे सदन की और संसद् का प्रशंसा और संसद् की सम्मानीय पद्धति को ध्यान में रखते हुए ऐसी घटना फिर घटित नहीं होगी । इस प्रकार की घटना से हिन्दी का कार्य आगे बढ़ता भी नहीं । वैसे तो हिन्दी अपना स्थान प्राप्त कर रही है लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दी को जिस प्रकार का प्रोत्साहन और स्थान प्राप्त होना चाहिये, सरकारी तौर पर वह प्रयत्न कुछ ढीलेपन से ही चल रहा है । उधर कुछ तेजी आनी चाहिये और हिन्दी को अपना उचित स्थान प्राप्त करने का अवसर

[श्री बाल्मीकी]

जल्दी से जल्दी मिलना चाहिये, राष्ट्र भाषा के रूप में। हिन्दी वह स्थान धीरे धीरे प्राप्त कर रही है। जिन राज्यों के भाई हिन्दी नहीं जानते हैं, मैं उन राज्यों में भी गया हूं। वहां भी मैं ने देखा है कि हिन्दी अपना स्थान प्राप्त कर रही है। जिस तरह से हिन्दी वहां बढ़ रही है वह सराहनीय कार्य है और मैं उन की प्रशंसा करता हूं। उन की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी के कार्य को ले कर चलना है। हमें उस में किसी प्रकार की जिद्द की बात नहीं लानी है। अब हिन्दी का काम किसी भी प्रकार से रुकने वाला नहीं है क्योंकि हिन्दी भाषा भाषी लोगों की संख्या इस देश में बहुत ही ज्यादा है। इस लिये मैं इस बात को यहां सदन में रखना चाहता हूं।

हमारे राष्ट्रपति महोदय ने चीन के हमले की विभीषिका और विकट समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है कि सारे देश के अन्दर संकटकालीन स्थिति है और आज भी है। यद्यपि चीन के अपने तरीके से विराम सन्धि के कारण हट जाने से हमें थोड़ी सी शांति सी प्रतीत होती है, फिर भी हमारे सीमावर्ती इलाकों पर से अभी चीन की निगाह कोई हटी नहीं है, और चीनी अजगर आज भी फुंकारता हुआ नजर आता है। चीन के जो अपने विस्तारवादी प्रयत्न हैं वे शान्त नहीं हैं। चीन के इस हमले का खतरा केवल इस देश को ही नहीं है, केवल एशिया को ही नहीं है, सारे संसार को है। चीन के इस भर्त्सनापूर्ण हमले की निन्दा सारे संसार ने की है, और हम विशेषकर उन संसार के राष्ट्रों के प्रति जिन्होंने इस संकटकालीन समय में हमारी सहायता की है, आभार प्रकट करते हैं। यह बात अवश्य है कि मैं सरकार का ध्यान विशेषकर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यकीनी तौर से एक प्रकार की ढील, शिथिलता और बर्दाश्त बरती गई है और देश में एक प्रकार की कमजोरी रही। लेकिन वह उस वक्त रही। यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारे देश के फौजी जवानों ने आज एक शौर्य और बलशाली वीरता का परिचय दिया है। जिस प्रकार से कोई प्रबन्ध न होते हुए उन्होंने चीनी अजगर के दांत खट्टे किये हैं और अनेक चीनियों को पछाड़ कर लोथों पर लोथें बिछाई हैं, उस के लिये उन के कार्य की चारों ओर प्रशंसा की जाती है। यहां यह बात जरूर है और देश चाहता है, देश की इच्छा है, यहां के जन जन की इच्छा है कि हमारे फौजी प्रयत्न, फौजी तैयारियां के प्रयत्न तेजी से बढ़ने चाहियें और इस तरह से बढ़ने चाहियें कि देश में आशा का संचार हो। देश चाहता है कि उन में किसी प्रकार की ढील न बरती जाय।

हम जानते हैं कि हमारे देश की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि है। देश की रक्षा के लिये जो भी बलिदान किया जाय वह थोड़ा है। तन का, मन का और धन का जो भी बलिदान किया जाय वह थोड़ा है। सारे देश ने इस संकट काल में जिस एकता का परिचय दिया है वह सराहनीय कार्य है। आज सारा देश एक है, अनेक मत मतान्तरों का यह देश, अनेक देवों को पूजने वाला यह देश, अनेक बातों के यहां रहते हुए इस में हर प्रकार के भेद विभेद नजर आते हैं, लेकिन आज संकट के समय में वे सारे भेद विभेद विलीन हो गये हैं और सारा देश दृढता के साथ, वीरता के साथ, शक्ति के साथ और धैर्य के साथ खड़ा हो गया है। अन्त में संसार में वे कौमें ही जीतती हैं जो धैर्य रखती हैं, जिन में साहस होता है, जिन में मनोबल होता है।

त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले,
धैर्यात् कदाचित गतिमाप्नुयाच्च,
यथा समुद्रे ऽपि च पोत भंगे,
सांयात्रिको वाञ्छति ततुमेव।

हमारे इस कठिन काल में धैर्य की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक यात्री समुद्र में जहाज के टूट जाने पर लकड़ी के सहारे को भी सहायक समझता है, उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि

देश के लिये धैर्य की बहुत आवश्यकता है। लेकिन धैर्य कोई शिक्षा नहीं, धैर्य कोई विश्वास नहीं, धैर्य मनुष्य का अपना कर्तव्य है। लेकिन जहां तक सरकार का और शासन प्रबन्ध का सम्बन्ध है, शासन को धैर्य रख कर भी तीव्रता के साथ तेज़ी के साथ फौजी तैयारियों को जारी रखना चाहिय ।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे लड़ाई का सामान तैयार करने वाले कारखाने हैं, जो आर्डनेन्स फैक्ट्रीज हैं, उन में दिन रात बल लगाकर तेज़ी के साथ सामान तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से जो मजदूर भी प्रयत्न कर रहे हैं मैं उनके प्रयत्न की भी सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आशा है कि जो भी अस्त्र शस्त्र आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, और आधुनिक पद्धति से चलाये जाते हैं, उन के निर्माण के सारे प्रयत्न चलते रहेंगे। वे यहां भी तैयार किये जायेंगे और अगर नहीं तो जहां से भी वे उपलब्ध हो सकेंगे वहां से प्राप्त किये जायेंगे। इस बात की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमारी जो तैयारी है वह एक विशेष प्रकार की तैयारी होनी चाहिये। आज भारत की प्रभुसत्ता को जो एक प्रकार की चुनौती है उसे हम ने स्वीकार किया है। हम ने चीन को ललकार दी है यह चुनौती स्वीकार करके कि हम अपनी इस पवित्र धरती से चीनी दरिन्दों के पैरों को उखाड़ कर फैंकेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार से यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा वह संकल्प ज्यों का त्यों खड़ा है और हम को उस संकल्प में किसी प्रकार की ढील नहीं लानी है क्योंकि उस संकल्प में सारे देश का सहयोग है।

इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि नेवी, अर्थात् हमारे पानी के बल में भी पूरी शक्ति होनी चाहिये और उसमें तेज़ी से, तीव्रता से वृद्धि होनी चाहिये। यही नहीं, हमारा वायु बल, हमारी वायु सेना भी दृढतर होनी चाहिये। उस में मज़बूती होनी चाहिये। जिस प्रकार से भी हो सके यह सारे प्रयत्न हम को सभी ओर से करने हैं और भली प्रकार से करने हैं। इस प्रकार से आपको अपनी सारी सेना में मज़बूती लानी है तभी हम चीनी हमले का डटकर मुकाबला कर सकते हैं।

यह बात ठीक है कि हमारे यहां ऐसी स्थिति में एक बलशाली सेना की आवश्यकता है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी सेना का सम्बन्ध है, वह सारे संसार में प्रसिद्ध रही है। यदि हम इसी प्रकार तैयार रहे और इसी तेज़ी से चलते रहे और हर प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते रहे, तो इस प्रकार का कार्य विशेष रूप से सराहनीय होगा। हमारी जो फ़ौज है वह सारे संसार में स्थान रखती रही है और आगे भी रखती रहेगी, इस प्रकार का मेरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रयत्न किसी भी प्रकार से ढीले नहीं पड़ेंगे।

यह मेरी समझ में भी आता है, कि रक्षा और रक्षा की तैयारियों में ख़र्च बढ़ेगा। खर्च बढ़े। अगर आवश्यकता हो तो हमें अपने प्रयत्नों में तेज़ी लाने के लिये अपने खर्च में बचत का प्रयत्न करना चाहिये। जब हम इस बात की ओर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि इस ओर बहुत कम प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार के प्रयत्न भी ढीले रहे हैं और नहीं के बराबर हैं क्योंकि जो शासन तथा सरकारी कार्यालय में साज सज्जा की बात है, जो शौकीनी की बात है वह ज्यों की त्यों नज़र आती है, और जहां तक संकट कालीन स्थिति का सम्बन्ध है, उस के होते हुए भी कोई उसका रूप देश में हमें नज़र नहीं आता है। मैं समझता हूं कि हमें अपनी बचत में तेज़ी लानी चाहिये। जहां तक फ़िज़ूलखर्ची को रोकने की बात है, मैं समझता हूं कि उधर भी कम ध्यान दिया गया है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फ़िज़ूलखर्ची को रोकने के लिए, लाल फ़ीते

[श्री वाल्मीकी]

शाही को रोकने के लिए, अफसरशाही को रोकने के लिए जिस प्रकार की ताकत के साथ प्रयत्न करने चाहिये वे नहीं किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सारे संसार से एक एक पैसा जहां ले रहे हैं वहां अपने यहां भी बचत कर के इस तरह के प्रयत्न करने चाहिय और सरकारी फ़ुजूलखर्ची को यक़ीनी तौर पर रोकना चाहिये। यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो अधिक नहीं तो कम से कम सात आठ करोड़ रुपये बचाये जा सकते हैं, जो कि देश के इस संकट काल में हमारे देश के काम आ सकते हैं। अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो इस का प्रभाव हमारी योजनाओं पर पड़ेगा।

पहली और दूसरी योजनाओं में देशों ही श्रम की आदत पैदा हुई है और विश्वास पैदा हुआ है, विचारों में दृढ़ता आई है। लेकिन जहां तक हमारी तीसरी योजना का सम्बन्ध है, मैं इस ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस के लक्ष्यों को किसी भी प्रकार से गिरने नहीं देना है। हालांकि तीसरी योजना के लक्ष्यों में कटौती की गई है लेकिन उस कटौती का प्रभाव केवल जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है, हरिजनों या दूसरे कुछ वर्गों पर पड़ता है। मैं जाहता हूं कि तीसरी योजना के तथ्यों को सामने रख कर, चीनी आक्रमण की विभीषिका को सामने रख कर तीसरी योजना के लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जाये। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि तीसरी योजना एक प्रभावशाली योजना है जो इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। लड़ाई केवल फौजी मैदानों में ही नहां लड़ी जाती, केवल सीमा पर ही नहां बल्कि पर्वतों पर भी लड़ी जाती है। चूंकि यह लड़ाई पर्वतों पर लड़ी जा रही है इसलिए इस तरह का प्रशिक्षण सैनिकों को देने की आवश्यकता है कि वे उस पहाड़ी स्थिति में अच्छी तरह से दुश्मनों से लड़ सकें। केवल इस शिकायत से काम नहीं चलेगा कि वहां पर कुछ ऊंचाइयां थीं, कुछ नीचाइयां थीं या कुछ गहरी खाईयां थीं। अभी भी चीनी आक्रमण-कारी हमारी भूमि पर मौजूद हैं इस तथ्य को हमें भुलाना नहां होगा। हमारे ऊपर यह छलपूर्ण और बर्बरतापूर्ण आक्रमण उस चीन द्वारा किया गया जोकि हमारा अपना मित्र रहा है, जिस के सम्बन्ध विगत में हमारे साथ मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इसी चीन को हम ने संसार की पंचायत में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है। इतना होते हुए भी उस ने हमारे साथ यह धोके भरा और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया आज वह बात नहीं है कि हम आज की स्थिति के प्रति जागरूक नहीं हैं बल्कि उन के इस धोखे ने हमें झकझोर दिया है। हिन्दी, चीनी भाईभाई तथ्य को देश ने समझ लिया है और हम देशवासियों को इस तथ्य को समझना है और यह ध्यान में रखना है कि उसने कैसा छलपूर्ण व्यवहार उस देश के साथ किया है जिस के कि साथ मिल कर हिन्दी, चीनी भाई भाई का नारा लगाया था। जो ग़लती और ग़फ़लत भूतकाल में हम से हो गई है उस को दुबारा नहीं करना है। अपने युद्ध प्रयत्नों में हमें किसी तरह की भी ढील नहीं करनी है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को भी हमें ध्यान में रख कर उन के लिए प्रयत्न करना है और देश की कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी उन्नति करनी है। आज की लड़ाई युद्धक्षेत्र में ही नहीं अपितु कल, कारख़ानों और खेतों में भी लड़ी जाती है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार उधर संजग है और उस के लिए सक्रिय प्रयत्न हो रहे हैं। कारख़ानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है लेकिन अभी मैं अपने इलाक़े या आसपास में घूमा हूं और मैं देखता हूं कि इस साल की फ़सल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार का ध्यान उस ओर जायेगा। सरकार को चीनी

हमले का सामना करने के सवाल को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए । लेकिन उस के अलावा दूसरे प्रश्न भी देश के सामने हैं जैसेकि देश की कृषि और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना । यह संतोष का विषय है कि इधर प्रयत्न हो रहा है । मेरा निवेदन है कि यह प्रयत्न रुकना नहीं चाहिए ।

आज देश के सामने जो संकटपूर्ण स्थिति है उस में यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने युद्ध प्रयत्नों में किसी तरह की ढील न आने दें । आपात स्थिति क़ायम रहनी चाहिये क्योंकि यह सारे देश को तैयार करने का सवाल है । लेकिन जैसाकि कुछ भाइयों ने शिकायत भी की है कि संकटकालीन स्थिति के दौरान मिली इमरजेंसी पावर्स का दुरुपयोग हो रहा है, वह दुरुपयोग उन का नहीं होना चाहिये । मैं समझता हूं कि जहां सरकार इस बात का ध्यान रक्खे और रक्खा भी जा रहा है कि इमरजेंसी पावर्स का सही इस्तेमाल हो ।

इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि देश में जो भी ऐसे देशद्रोही और देश के ख़िलाफ़ तत्व मौजूद हैं सरकार उन को उभरने न दे और उन को सख्ती से दबाये । ऐसे देश और समाज विरोधी तत्वों को जोकि देश को हानि पहुंचाने वाले हैं उन को दबाना और उभरने न देना देशहित में है और ऐसा कर के ही सरकार देश की सुरक्षा सुदृढ़ कर सकती है ।

हमारे देश में समाजवाद और प्रजातांत्रिक व्यवस्था चल रही है और उन के अंदर मनुष्य का भाग्य खुल रहा है, नये भाग्य का उदय हो रहा है । भारत रक्षा कोष और अन्य युद्ध प्रयत्नों में मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि धनी वर्ग ने अपना पार्ट अदा नहीं किया है । उन का उस में सहयोग न के बराबर रहा है । इस के विपरीत इस देश की आम जनता ने किसानों और मजदूरों तथा दलितों ने दिल खोल कर अपना सहयोग प्रदान किया है ।

जहां हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि देश के अंदर लोक-तंत्री और समाजवादी परम्परा जागृत हो रही है वहां यह देख कर दिल को एक ठेस सी लगती है कि अभी भी देश के अंदर हजारों और लाखों निर्धन आदमी दलितों की शक्ल में, मामूली किसानों की शक्ल में, मजदूरों की शक्ल में और सर्वहाराओं की शक्ल में मौजूद हैं । मैं सारे देश में घूमा हूं और उन की स्थिति देखी है । आज भी उन को कोई आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिलता है । वह न्याय उन्हें मिलना चाहिये । सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री बाल्मीकी : आपने सबको इतना इतना समय दिया है । मुझे तो अभी दस मिनट भी नहीं हुए हैं । मुझे कुछ और अधिक समय दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दस एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें ।

श्री बाल्मीकी : मैंने खेतों के उत्पादन में वृद्धि करने और उसके लिए किसानों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए सुझाव दिया है । दूसरा निवेदन मेरा यह है कि हमें उद्योगीकरण में भी प्रगति करनी है । हमें देश में अपने उद्योगों को इस तरह से चलाना है जिससे देश में रक्षा सम्बन्धी तथा जवानों के उपयोग का सामान ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके और इसके लिए हमें जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिये और इस प्रकार का सामान उनके अन्दर भी बनाना चाहिये । उनको इसके लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और हर प्रकार से धन की सहायता करनी है ।

[श्री बाल्मीकी]

अन्त में मैं और अधिक न कहते हुए किसानों की हालत की तरफ सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। आज की स्थिति में किसान को सारी जरूरी कर्ज तकावी आदि की सहूलियतें पूरे तरीके से मिलनी चाहिएं। हमें यह नहीं भूलना है कि हमारी जो अर्थ नीति है वह किसान के ऊपर निर्भर है। ग्रामीण जीवन तथा किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि वहां स्वस्थता, एकता और मजबूती लाने के लिए वहां के जीवन में भारी परिवर्तन किये जांय और उनको ऊपर उठाया जाय। सरकार को इस दिशा में विशेष रूप सक्रिय से और ठोस कदम उठाना चाहिए। तभी विकास के प्रयत्न सफलीभूत हो सकते हैं।

Shri Y. N. Singha (Sundergarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to express my dissatisfaction with the address presented by the President. From the address no one can know that our country has been invaded by a powerful enemy and that the Parliament has given a mandate to the ruling party to take measures to vacate this aggression. The address talks of industrial output, rural reforms and all types of meaningless things that have no direct connection with the supreme task which now faces the nation. How can a Government or a country waste time on matters which can have meaning only if the country is free? Freedom of the country comes first and things like patterns of society come afterwards. What do our steel output, co-operative farms and other such things mean when our country has been invaded by the Chinese and they threaten us with the loss of our independence and self-respect? In any other period of history in India, as elsewhere, a government which talked of such things when the country had been invaded by an enemy would stand discredited completely. In any other country a government which behaves in this manner would be thrown out of power. It is only in our country that this Government has thus let us down ever since it came to power and yet can even get away with such deeds as are indicated in the address of the President.

Shri Maurya (Aligarh): Are there no representatives among the Swatantras who can make an unwritten speech?

An Hon. Member: This is his maiden speech. So, please do not interfere.

Shri Y. N. Singha: The address talks of peaceful methods and it refers to Chinese invasion of our country as if it is just one unimportant occurrence. The address makes it clear that our Government have neither the heart nor the desire to face the basic task that now confronts them.

Sir, the defence of the territorial integrity is a primary task that a ruler has to discharge. In our own history, when Anangpal, the King of North Western India was once defeated in the battle with Mahmood of Ghazni, he immediately set himself to prepare for avenging his defeat. When even in his second effort he failed, he took the only honourable course open to a ruler. He had a funeral pyre set up in Lahore and ascended it to perish in the flames. These are our traditions and such are the duties of a ruler. But now we are being ruled by a strange set of men. They put the country in a mess. They make mistake after mistake. They blunder into criminal deeds of omission and commission, again and again. Nevertheless, they feel no shame in clinging to their seats of power.

Sir, I say that it is a great shame that our rulers have gone to this extent against the true interests of the country. They have brought grievous damage to the country by surrendering to the Chinese. Now they insult

mankind by telling them that the Indians must accept forced labour. This is not where they stop. The Congress rulers also insult the intelligensia of the country be telling that through peaceful means they shall liberate occupied territories of India.

In his speech in the Lok Sabha on the 5th December, 1961, Prime Minister Nehru had declared that his whole soul reacts against the idea of war anywhere. He added that he cannot get rid of this attitude at the age of seventy-two. Now that he is a little older, the country cannot expect him to face situations that need more realistic action. War is a terrible thing, but those who are afraid of war are put into slavery.

Sir, do we want slavery and peace or do we want war if necessary to preserve our independence? Our Prime Minister has told us, frankly enough, what is beyond him. His duty, therefore, is clear. He must take the country into confidence and seek advice from those who are his patriotic and real friends.

श्री शिव नारायण (**बासी**) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है।

हमारा यह देश बड़ा गौरवशाली है कि ऐसे राष्ट्रपति जी हमारे बीच में हैं, जो कि फिलासफर के बड़े विद्वान, राजनीति के प्रकांड पंडित और गुरुजन रहे हैं। उन्होंने यह सदुपदेश दे कर कि "उठो, जागो, जाग्रत रहो, सोओ नहीं", देश को जगाया है और संकेत दिया है। उन्होंने हमें कहीं विचिलत नहीं किया है। हम सब को इस बड़े भारी विद्वान, राजनीतिज्ञ और फिलासफर के इस उपदेश से प्रेरणा और प्रकाश लेना चाहिये।

जहां तक कोलम्बो-प्रस्तावों का सम्बन्ध है, उनको इस सदन और इस पार्लियामेंट ने माना है और इस प्रकार हम ने अपने देश की नान-एलाइनमेंट पालिसी को एक सनद दे दी है। कोलम्बो-प्रस्तावों को बनाने वाले पांच देश नान-एलाइन्ड कंट्रीज हैं और उन प्रस्तावों को मान कर हमने अपनी पालिसी को एक सर्टिफिकेट दिलाया है। यद्यपि चीन ने दुनिया भर में किताबें आदि बांट कर और कुप्रचार कर के हम को बदनाम कर रखा है कि हिन्दुस्तान ने उस पर अटैक किया है, लेकिन कोलम्बो-प्रस्तावों को मान कर हम ने यह सिद्ध कर दिया कि हम सही रास्ते पर हैं और चीन गलत रास्ते पर है।

श्रीमन्, दुनिया में अच्छा से अच्छा युद्ध भी खराब से खराब पीस से अच्छा नहीं होता है। किसी भी युद्ध के बाद अन्त में टेबल के गिर्द बैठ कर शान्ति और सुलाह के लिए बातचीत करनी पड़ती है। आप को याद होगा कि पहली बड़ी लड़ाई के बाद वारसाई में जर्मनी के साथ सुलाहनामा हुआ। फिर उस वारसाई सुलाहनामे का रिजल्ट दूसरा बड़ा युद्ध हुआ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : यहां तो पहले ही सुलाह है।

श्री शिव नारायण : माननीय सदस्य, श्री यादव, बहुत परेशान हैं। मैं अभी उन को बताऊंगा कि वे वह क्या हैं और क्या कर रहे हैं।

मुझे इस बात की खुशी है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि चीन ने हम को अच्छा सबक दिया, उसने हम को सचेत और जाग्रत किया।

श्री रामसेवक यादव : इस से बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है?

श्री शिव नारायण : बेशर्मी माननीय सदस्य की होगी।

[श्री शिव नारायण]

श्रीमन्, मुझे एक कहावत याद आती है : "तमीजे न बाशद, कमन्दे हवा, उलटने को रोटी, उलट दीं तवा"। हमारे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन यह हालत उन की है।

मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन ने हम पर हमला नहीं किया है, दोस्त ने हम पर हमला किया है। चीन ने दुनिया के सामने यह एक नई मिसाल पेश की है। हिस्ट्री में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि दोस्त ने हमला किया हो, दुश्मन ने नहीं। चीन के इस हमले को हम फेस कर रहे हैं, लेकिन पंचशील पर आधारित जो पीसफुल पालिसी हमने अख्तियार की थी, उस पर हम टिके हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री उस पर स्थिर हैं। हमारे कुछ मित्र इतना शोर-गुल करते हैं, लेकिन वह शान्ति और गम्भीरता के साथ इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल क्या हैं। जवाहरलाल वह हस्ती है, जिस ने हिन्दुस्तान के अप्स एंड डाउन्ज, सुख और दुख दोनों के दिन देखे हैं। वह अंग्रेज से लड़े हैं। १९४२ की मूवमेंट के बाद जेल से छूटने के बाद गांधीजी ने नहीं कहा कि हम १९४२ की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। वह हिन्दुस्तान का शेर जवाहरलाल नेहरू था, जिस ने पंजाब में कहा कि १९४२ के रेवोल्यूशन का जिम्मेदार मैं हूं। उस के बाद अंग्रेज का मुंह बन्द हो गया। आज उसी जवाहरलाल के पीछे हिन्दुस्तान खड़ा है। वह कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, कोई कमजोर लीडर नहीं है। उन में बड़ा तपोबल है। वह उन्नीस बरस जेल में रह चुके हैं। श्री यादव का तो शायद उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। यह कीमत है जवाहरलाल की और इसी लिए आज सारी कौम उन के पीछे खड़ी है।

हम ने कोलम्बो-प्रस्तावों को माना है और गलत नहीं माना है। नान-एलाइनमेंट पालिसी और कोलम्बो-प्रस्ताव दोनों एक दूसरे के समर्थक हैं। हमने उन प्रस्तावों को माना और इस प्रकार दुनिया के सामने नान-एलाइनमेंट पालिसी की फिर पुष्टि की। हमारी इस नीति का ही फल है कि आज दुनिया के सत्तर मुल्क हमारे पीछे खड़े हैं। हम कमजोर नहीं हैं। अमरीका, रशा, ब्रिटेन, फ्रांस, कोई देश भी हमारी मदद करे, तो हम उस को वैलकम करते हैं। मैं फ्रांस को बधाई देना चाहता हूं कि उस ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने अधीनस्थ भारतीय क्षेत्रों को स्वतंत्र किया और इस बारे में एक मुलाहनामा किया। यह उस देश का बड़प्पन है।

तुलसीदास जी ने कहा है, "जे न मित्र दुख होंहि दुखारी, तिनहिं बिलोकत पातक भारी"। चीन ने इस नीति के विरुद्ध काम किया है और इस लिए उस का नाम दुनिया के सभ्य देशों से मिट गया है। उस की बदनामी हुई है। आज कम्युनिस्ट वर्ल्ड में चीन की क्या पोजीशन है ? स्वयं कम्युनिस्टों ने उस को कन्डेम किया है। मैं राजनीति का छोटा सा तिनका हूं। "जाकी धन धरती हरी, ताहि न लीजो संग, जो संग राखत बने, तो करि राख अपंग"। हम ढोल नहीं पीटते हैं कि हम यह हैं और वह हैं। हम खरगोश की चाल नहीं चल रहे हैं। हम कछुवे की चाल चल रहे हैं। हम उतावले नहीं हैं। हम शान्ति के साथ अपनी गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे पहले थे, वैसे ही अब हैं। वह सदा एक से हैं।

श्री रामसेवक यादव : जैसे सूखे सावन, वैसे हरे भादों।

श्री शिव नारायण : सूरज के विद्यमान रहते हुए भी जिस को दिन में भी न दिखाई

दे, तो यह उस का दोष है, मेरा दोष नहीं है। हमारी गाड़ी तो आगे चलती जायगी।

गवर्नमेंट ने जो गोल्ड कंट्रोल पालिसी को लांच किया है, मैं उस के सिलसिले में फिनांस मिनिस्टर को दिल खोल कर बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने देश में ओपनली एलान किया कि जिस के पास सोना है, चाहे वह फेयर मीन्ज से प्राप्त किया गया हो और चाहे फाउल मीन्ज से, वह उस को जमा कर के गोल्ड बांड्ज ले ले, वर्ना बाद में हम उस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या यह कोई गुनाह है? मेरे लायक दोस्त, श्री रंगा, इस वक्त बैठे नहीं हैं। उन्होंने औरतों की बड़ी वकालत की। मैं ने उस दिन व्हिप साहब से कहा था कि उनके बाद किसी लेडी मेम्बर को बुलवा दिया जाये, लेकिन इन्तजाम दूसरा था। हम सब जानते हैं कि हमारी मां बहनों ने दिल खोल कर अपने सुहाग के जेवरात दिये और सोना-चांदी दिया। भारतीय नारियों के त्याग की गाथायें हमारे इतिहास के एक एक पन्ने पर लिखी हुई हैं। झांसी की रानी और दुर्गावती आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज भी वे ललनायें हमारे बीच में मौजूद हैं, जो अपने बेटे को तिलक लगा कर रण-क्षेत्र में भेज देती हैं।

इस के बाद श्री रंगा ने पचास लाख सुनारों की भी बड़ी वकालत की। जिन लोगों के घरों में ब्लैक मार्केटिंग का सोना होता है और चोरी से सोना गलाया जाता है, श्री रंगा ने उन की वकालत की। इस से मुझे दुख हुआ। इस मुल्क में हम ने जमींदारी एबालिशन किया। "गरीबों को मिले रोटी, तो मेरी जान सस्ती है", हम ने यह नारा लगाया था। कांग्रेस वाले आज भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। जनसंघ के एक मेम्बर ने भी आज उन की तारीफ की है। हम में यह हिम्मत है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरों से लड़ते-झगड़ते हैं, लेकिन हम सौ और पांच आपस में होते हुए भी दूसरों के लिए १०५ हैं।

15 hrs.

इस पवित्र सदन में १४ नवम्बर को हमने युनैनिमसली एक संकल्प पास किया था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन मुझे दुख है कि आज जब कि मुल्क के सामने इतनी बड़ी प्राबलम है, जब कि मुल्क पर विदेशी एटैक हुआ है, हमारे कुछ मित्र बाहर बड़ी बड़ी गालियां सुनाते हैं। हमारे देश में चार बड़ी हस्तियां हैं, जिन के नाम मैं नहीं लेना चाहता। कांग्रेस की बदौलत वे मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे, गवर्नर-जनरल रहे, क्या क्या नहीं रहे? वही लोग आज कांग्रेस के विरोध में और इस देश के बड़े लीडरों के विरोध में काम करते हैं। कल तक वे मिनिस्टर थे, लेकिन चूंकि आज हम उन को नहीं रख पा रहे हैं, इस लिये हम बुरे हो गए। यह कितने अफ़सोस की बात है। मुझे क्षमा किया जाए, लेकिन हमारे यहां गांवों में एक कहावत मशहूर है कि जब कोई बुजुर्ग सत्तर बरस से ऊपर हो जाता है, तो वह सठिया जाता है। मियां जब बूढ़ा हो जाता है वह होशियार हो जाता है। यह है नमूना हमारे देश की चार बड़ी हस्तियों का। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जब वे इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। इस तरह का जो व्यवहार करता है, उससे बड़ा ट्रेटर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। बगावत का बिगुल बजाते हुये वे देश में घुमते फिरते हैं। आप को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राणा प्रताप को जब जरूरत पड़ी तो भामा शाह ने खजाने खोल दिये थे। आज मैं पूछना चाहता हूं रंगा साहब से कि वे क्या कर रहे हैं। मुझे दुख है कि गायत्री देवी जी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने ललकार कर कहा कि

[श्री शिव नारायण]

दस परसेंट और चौदह परसेंट प्रिवी पर्स का उन्होंने दान में दे दिया। ऐसा करके आपने बड़ी कृपा की है। इस आपातकाल में मैं तो कहूंगा कि आपने राजपूती शान को बट्टा लगाया है। राम राम। वह जब बोल रहीं थीं तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब वह यहां पर बैठी हुई थीं उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी तेजपुर गई हुई थीं। प्रो० रंगा भी उस वक्त यहां पर बैठे हुए थे। आज भी वह देश के कौने कौने में दौड़ फिर रहीं हैं और लोगों को तैयार कर रहीं हैं। उस बेचारी का नाम लिया जाए और उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, यह कहां का न्याय है। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मां बेटी दोनों जेल गए हैं। बाप जेल गया है। सारा खानदान तबाह हुआ है। आज भी वह देश के कोने कोने में मारी मारी फिर रही हैं और देश को तैयार कर रहीं हैं। जान उन्होंने अपनी हथेली पर रखी हुई थी जब वह तेजपुर गई थीं। वह नेफ़ा भी गई थीं। वहां पर कोई भी बम गिर सकता था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। उन में देश की श्रद्धा है, उन पर देश का विश्वास है।

रंगा साहब कहते हैं कि वह कम्युनिस्टों के विरोधी हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैं उनसे भी ज्यादा कम्युनिस्टों का विरोधी हूं। मैं सांपनाथ और नागनाथ में कोई अन्तर नहीं जानता हूं। हम भी कम्युनिस्टों में विश्वास नहीं करते हैं। हम तो यह कहते हैं कि हर एक को वैन करो। उनके लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी के आठ सौ, आदमी जेल में हैं। मैं तो कहता हूं कि टेलीफोन कर दो चीन को, टेलीफोन कर दो रशिया को कि यह इंडियन गवर्नमेंट में ही म है, यह नेहरू गवर्नमेंट में ही दम है जो आप सब को जेल से बाहर रखे हुए हैं, उनको बाहर रखे हुए हैं जिन्होंने राज़ की बातों को कनवे किया है। इससे बड़ा आदर्श इससे बड़ा नमूना आप को दूसरा मिल नहीं सकता है। यह हमारे देश का आदर्श रहा है और इसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। आज भी हम आपको सीने पर रखे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि एमरजेंसी पावर्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं अगर एमरजेंसी इंचार्ज डिफेंस मिनिस्टर होता तो रंगा जी को भी जेल में डाल देता। हमने इन एमरजेंसी पावर्ज का इस्तेमाल ही कहां किया है? हमने तो बड़ी लीनियेंसी बरती है। आपके इस व्यवहार पर आपको बड़ी आसानी से अन्दर किया जा सकता था।

पाकिस्तान के सिलसिले में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। उसके साथ हमारे भाई चारे के सम्बन्ध होने चाहियें। हमने बांट कर पाकिस्तान दिया है। हम भाई भाई रहे हैं। आज भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ उनका प्रेम हो जाए, आज भी हम चाहते हैं कि हमारा मेल मिलाप हो जाए। अगर ऐसा हो सका और माननीय स्वर्ण सिंह जी अपने मिशन में कामयाब हो सके तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अगर वार्ता में सफलता मिलती है, तो उनका नाम रौशन हो जाएगा। जो नीति हम पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपनाये हुए हैं, वह सही है। लेकिन हम को टीज़ किया जा रहा है। आज भुट्टो साहब पेकिंग गए हैं। वहां पर वह बातचीत करेंगे। क्या हिन्दुस्तान को उन्होंने कमजोर समझ रखा है? हमारे चार हजार जवान मारे गए हैं लद्दाख और नेफ़ा में। लेकिन हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। हमने सीने पर गोलियां खाई हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पीठ में कोई दूसरा छुरा घोंपे। जो हमारे जवान मरे हैं वे बहादुरी दिखाते हुए मरे हैं। यह भारतीय इतिहास है और इसी का पालन उन्होंने किया है, इसी परम्परा का पालन

उन्होंने किया। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीर अभिमन्युओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चीन की गोलियां खा कर उन्होंने अपनी जान गंवाई है, देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है।

अब मैं एग्रीकलचर के सिलसिले में तथा कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। दोनों मिनिस्टर यहां मौजूद हैं। मेरी उन से शिकायत है। जो खाद पहुंचता है, जो फर्टिलाइजर आप देते हैं, वह समय पर नहीं मिलता है, आपके अधिकारी बड़ा रोड़ा अटकाते हैं रास्ते में। किसान आप से संतुष्ट हैं। आपकी चीज पहुंचती है लेकिन समय से नहीं पहुंचती है। समय पर चीज देने का आप प्रबन्ध करें। कम्युनिटी डिवेलेपमेंट मिनिस्टर साहब से मैं कहता हूं कि जो जीपें हैं, उनको आप विदड्रा कर लें। हम से मिलिटरी के लोगों ने इसकी शिकायत की है, दूसरों ने शिकायत की है कि उनका मिसयूज होता है। आप देखिये कि कांग्रेस वालों में ही दम है कि गवर्नमेंट की शिकायत गवर्नमेंट के सामने कर रहे हैं। आप भी इसको कान खोल कर सुन लीजिये। हम पिछवाड़े से चोट नहीं करते हैं, सामने से करते हैं। इस चीज को आपको मोबिलाइज करना चाहिये। एन० सी० सी० की जो ट्रेनिंग हो रही है, उस में डिसिप्लिन आना चाहिये।

यहां पर शिकायत की जाती है कि चन्दे जबर्दस्ती वसूल किये जाते हैं। मैं अधिकारियों के साथ गांव गांव घूमा हूं। पैसा लोग दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। किसी अधिकारी ने उनके डंडा नहीं मारा है और न ही उनको किसी ने डंडा मारा है।

श्री रामसेवक यादव : अधिकारियों ने मारा है।

श्री शिव नारायण : कहीं पर को कोई ज्यादती नहीं हुई हैं। आप बाराबंकी जिले से आते हैं जहां पर एनार्की है, जहां पर हुल्लड़बाजी है। लेकिन वहां भी आज लोग दे रहे हैं और खुशी से दे रहे हैं। किसी अधिकारी के वहां पर गोली नहीं मारी गई है। हां मेरे एक साथी के वहां गोली मार दी गई थी पहले और मैं जानता हूं कि आप उस जिले से आते है। वहां पर अधिकारी आज पैसे पा रहे हैं और किसी के गोली नहीं मारी गई है।

हमारे रंगा साहब ने कहा कि इन एमरजेंसी पावर्ज को विदड्रा कर लो। मैं उन से कहना चाहता हूं कि हम तो इनको विदड्रा किए ही हुये हैं, इनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करते तो आपकी बोल बन्द हो जाती। आप परेशान हो जाते। अंग्रेजों के जमाने में एमरजेंसी पावर्ज का नक्शा आपने देखा था। जब दूसरी वर्ल्ड वार हो रही थी या जब १९४२ की मूवमेंट चली थी उस वक्त जो पावर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली थीं, उनका नंगा इस्तेमाल होते हुये आपने देखा ही था। क्या उस को आप भूल गए हैं? लेकिन हमारे यादव जी उस वक्त १८ साल के रहे होंगे और कालेज में पढ़ते रहे होंगे।

मान्यवर मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश में ऐसी एकता आज तक कभी नहीं देखी गई है जैसी इस चीनी हमले के वक्त देखी गई है। हमारे रंगा साहब बड़े विद्वान हैं। उन से मैं कहता हूं कि वह कृपा करके हिन्दुस्तान के उत्तर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जा कर देखें कि किस तरह से सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। हमें चाहिये कि हम पहले चीन से निपट लें और बाद में हम आपस में निपटते रहेंगे। आज हमें अपने सारे मतभेद भुला देने चाहिये। हमारी एकता कायम रहनी चाहिये। मैं चार बड़ी हस्तियों का नाम

[श्री शिव नारायण]

लेना नहीं चाहता हूं जो गलत प्रचार कर रही हैं। मैं भगवान से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूं कि वह उनको सद्बुद्धि दे।

इन शब्दों के साथ श्री आर० एस० पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें जो यह सन्देश दिया है "जागो, उठो" यह कितना सुन्दर है। इस का हमें पालन करना चाहिये।

Shrimati Akkamma Devi (Nilgiris): Mr. Deputy-Speaker, I rise to express deep gratitude to our President for his valuable Address which has given us so much of encouragement. His concluding words,

> "Awake, arise, understand the opportunities you have and stop not till the goal is reached."

have instilled in us the spirit to shoulder our responsibility by keeping our conscience as the dictator in our day to day routine of work.

Despite our initial set backs, we have implemented the First and Second Five year Plans and now we are in the Third Five Year Plan. Undoubtedly, we have made much progress in the march towards building our country economically, educationally and socially. We have corrected our mistakes and now, as our President has stated, we will strive unceasingly towards our goal, namely, the establishment of a socialistic pattern of society. Mere criticism, fault finding and shouting will not help us in solving our problems. It shows one's own weakness and nothing else. We are prepared to take in constructive criticism.

Shrimati Gayatri Devi, the other day, in her speech said that Indira Gandhi is too clever in making use of her father. Certainly not. She must understand that she is the source of inspiration not only to the women of India, but to the whole world. She is the leader of her sex in our country. She has shown the women what is their responsibility in building the country not only in times of peace, but in times of war also. She has contributed not only her jewels including the jewels of her dolls, but let her understand that she has visited the affected areas when real fighting was going on, and as a mother, she has given hope and encouragement and help to our fighting jawans and also to our wounded jawans. She believes in constructive work rather than in mere platform speeches.

Our President has stated in his Addreses that many steps have been taken to expand our Armed Forces and increase production in our ordnance factories, and he has paid gratitude to the thousands of workers in these factories. These workers deserve our wholehearted support and encouragement because they have worked not only day and night but they have worked even on holidays, to put forth maximum production. Apart from their strenuous effort, they are contributing regularly to the National Defence Fund every month.

In this connection, I am proud to say that there is absolute co-operation between the General Manager and the officers and staff and workers of the Cordite Factory at Aravankadu, and that unstinted co-operation has helped them to reach the target.

Again, I am proud to say that members of the women's association attached to this factory are knitting 25 woollen sweaters every month for our jawans from their own collections.

As I happen to stay near the Cordite Factory at Aravankadu, I find from personal experience that there are many more items on which our Government should concentrate and take immediate action. I was told that in most of our ordnance factories, the plants are not less than 20 years old.

Our factories have to bring out maximum production, and for this magnificent outturn I request that these old plants should be replaced by new and modern plants.

Along with our President, I am grateful to our friendly countries, especially the USA and the UK for their wholehearted support to us, when the venomous and treacherous Chinese took us by surprise and made a massive attack on us.

I request our Government to arrange to equip our ordnance factories with modern weapons from the USA or the UK, so that the production will be raised to the maximum and our defence effort will be strengthened.

Secondly, housing facilities should be made available to those workers who come from distant places to the factory-site. At present, there are about four thousand workers working in this Cordite factory, and I am sorry to say that only five to ten per cent of these workers are provided with housing facilities. We have staff from all over India, and these officers, after joining duty are asked to wait till accommodation is provided. In cold places it becomes very difficult for workers to live without proper accommodation. Recently, circulars have been issued by Government to the effect of doubling the houses, but there are practical difficulties when two families share a house unless proper partitions are made. I request that Government should give top priority to the needs of our ordnance factories. As a temporary measure, I would submit that housing for workers will be beneficial to some extent; also, another humble request of mine is to arrange for technical experts either from the USA or from Germany to give guidance and training to our ordnance factories so that our defence efforts will be strengthened to the usmost.

Now, I would like to speak about the gold ornaments. We purchase gold ornaments, and we put by our savings in gold for our future, in order to help us in times of unavoidable danger and to help us in our retired days. We save for our future but when our sacred soil is in danger, what is gold to us, and what is hoarded wealth to us?

In this connection, I would like to say that the threat to our country by the Chinese has shaken the whole country, and we have seen the unity of our people, young and old, rich and poor, men and women and even the physically handicapped, irrespective of party and creed, and this we have seen from the pouring contributions to the National Defence Fund, and I am very happy to say that this contribution has been spontaneous and not by compulsion as some of the Opposition members have stated. We see old men and women coming from distant places to the district headquarters and to the State headquarters, standing in a queue and then giving away their ornaments and cash. This shows the inward desire on their part to help their country, and this is not at all compulsion as some hon. Members have stated.

Again, this flow of contributions has been much more from women than from men. I am simply shocked to listen to my hon. friend Shri Ranga saying that there will be confusion among women when they are asked to wear jewellery made of 14 carat gold. May I tell him that they are not after gold? They are ready to sacrifice everything on this earth for the sake of their Motherland? They have already started the utmost economy in their households, to save for the adequate supply of nutritious food and warm clothes for our jawans fighting on the border.

My hon. friend Shri Ranga and others are really happy internally because this Gold Control Order has prevented their daughters, wives and sisters from worrying them to make gold necklaces and the latest design

[Shrimati Akkamma Devi]

gold bangles; but outwardly they are saying like this.

Indian women are blessed with perseverance and the ability to take up great responsibilities on their shoulders, and with a noble quality of *dharma*, and women are prepared to prove this noble quality in deed and in action.

15.17 hrs.

[SHRI KHADILKAR *in the Chair.*]

They have given away the gold ornaments, and are ready to offer their services as doctors and nurses to look after the welfare of the families of our jawans who have laid down their lives for the honour and freedom of the country; and they are also ready to look after the welfare of our jawans who are still guarding our frontier. They knit woollen garments for our jawans, and they run canteens in an efficient and economic way, and they collect funds for our defence efforts; and they are even ready to offer their services in the front also. I am very pleased to mention here that many women from the rural areas have given their names to take up rifle training. At least now my hon. friend Shri Ranga will understand what Indian women are. Before I conclude, I would like to say a few words about agriculture. The agriculturists of our country are in the rural areas, and the measures taken under the Five Year Plans to improve agriculture and to step up production are not at all adequate to make our country self-sufficient in foodgrains and other agricultural produce. In rural areas thousands of acres remain uncultivated because of water scarcity. In the villages also people suffer a lot for want of adequate supply drinking water. Large acres of land, and fertile land at that, are lying uncultivated because of want of irrigation facilities. In my constituency in the rural areas of Mettupalayam and Avinashi of Coimbatore District, I am sorry to say that the electricity charges come only to one rupee a month, and from that one can just imagine the dryness of these areas. Therefore, my humble request to Government is to arrange for adequate supply of water to these areas by making use of the surplus and waste water of the Kundah project so that agriculture will be improved and production stopped up a hundred-fold.

Before I conclude, I would like to make a small point, in regard to Prohibition. In order to see that Prohibition is implemented successfully, I request Government to raise the morale of our police. For this they should be given a handsome salary. This will prevent them from stooping to corruption. As Prohibition is there, it seems they are making it an opportunity to supplement their ordinary income. Therefore, I request that the salary of the police should be raised so that the culprits who distil illicit liquor from rotten plantain skins, boot polish, spirit and bark of some trees which are injurious to health and kill people—which shorten life by 50 per cent—are not allowed to ply their trade.

With these words, I support the motion of thanks to the President for his Address moved by Shri R. S. Pandey and seconded by Dr. K. L. Rao.

Shri Swell (Assam-Autonomous Districts): Mr. Chairman, the debate on the motion of thanks to the President is a solemn occasion in the proceedings of this House and I believe it is only right and proper that the subject should be approached with dignity, not only because of respect to the Head of the State but because also it affords an opportunity to review the entire field of the Government's work and achievements. But I know that the time that is left for me is very short, and therefore, even at the cost of sounding bit crude, I shall plunge into the heart of the subject by posing a number of questions which arise from what the President has said in

his Address and what he should have said but has not.

The first question is: why has the President this time thought it necessary to preface his Address by a reiteration of the fundamentals of our Constitution, which assure, among other things, freedom of speech, movement, worship, faith, and justice—political, social and economic—and why almost immediately after he has thought it necessary to embark on a discourse of the present emergency which has taken away almost 11 paragraphs out of the 30 paragraphs of his Address? It may be argued that the emergency at present is singly the most important subject in the country and, therefore, it deserves the importance which the President has attached to it. On the face of it, the question that I have posed may appear academic and a bit trite. But in the context of the relentless stream of accusation levelled in this House and also outside in the country against the Government for misusing their powers this question assumes a significance which cannot be ignored. Could it be that even the Government, although they may not like to admit it, are uncomfortably conscious that the powers which the emergency has conferred upon them, have, to a certain extent, been abused, and that the accusations brought to their notice cannot be absolutely baseless? I will not go into that because the subject has been stressed more than once, by almost every speaker on this side of the House.

Some Members on the ruling party side have had the courage to say that we cannot advance a single instance of the misuse of these powers of emergency, although they will not go to the extent of saying that there have not been arrests under the Defence of India Rules. I suppose this is not the occasion here to go into the merits or the demerits of those arrests, whether they have been done right or they have been done in a wrong manner. But I would like to bring to your attention just one particular instance which involves a Member of this House. Quite a number of Members of this House have been arrested. But most recently a Member of the Socialist Party, Shri Krishan Pattnayak, has been arrested on the alleged ground that he had said something prejudicial to the Government's war effort. I do not hold any brief for Shri Krishan Pattnayak; I do not hold any brief for the Socialist Party either. As a matter of fact, I disapprove of much of their tactics in this House. But if I know Shri Krishan Pattnayak, if I know the Socialist Party, it is this that, in spite of their chankiness, if they err at all, they err on one thing, and that is in their impatience at the fact that this Government has not done enough to teach the Chinese a good lesson. Shri Pattnayak must have said a few things like that and he might have been arrested, because he has been loud and strong in the criticism of Government. I mention this just to bring this to the notice of this House that it is very dangerous to criticise the Government at present. I would also like to stress here that the Defence of India Rules do not contain in them any foolproof machinery by which to prevent abuse of the powers of the emergency.

The next question I want to pose is with regard to by-elections. I am personally deeply concerned with this question, because I have as many as 7 Assembly constituencies awaiting by-elections in my area. Now, I would like to put this question straight to the Government: how are they going to conduct these bye-elections together with the emergency? Are they going to be democratic elections? If Opposition parties are to fight the elections, on what platform will they fight? Will they be accorded the freedom, the ordinary democratic freedom, of criticising the Government, of tearing Government's policies into shreads, of accusing this Government for its failure to safeguard the frontiers of this country, of accusing this Government for its failure in its defence

[Shri Swell]

policy—in other words, of seeking to shake the people's confidence in this present Government? I would like Government to give a clear answer to this question. Unless they are prepared to say that for the period of the elections, they are prepared to lift the emergency, that for the period of the elections they are prepared to allow Opposition parties to criticise freely, I say these elections are a farce. They may just as well nominate a few Members to fill the seats that are vacant. I should like the spokeman of the Government to reply and make this position clear because, as I have said, I am personally deeply involved in the question. I do not think there is any other representative in this House who has as many as seven constituencies which are coming up for elections together.

My next question is with regard to Government policy for the control of gold. The Finance Minister is very touchy about criticism. A few years ago I had the privilege of meeting him in Shillong with my group and I can say that the bitterness of that interview is still in my mouth. Still this country is as much my country as his country. I would like to put this question straight to him: is he convinced that his present gold policy is in the best interests of the country? Yesterday in this little paper which is published here in Delhi, there is a news item. A number of distressed goldsmiths met the Finance Minister in a deputation and he is supposed to have said something to the effect that he was responsible to God alone. I quote:

> "Mr. Morarji Desai is further stated to have said that he did no considered himself responsible to the people but to God."

I would like the Finance Minister to give a reply to that. If the report is correct it is highly offensive to this House and to the people. The Finance Minister is here by virtue of the vote of his people (*Interruptions.*) The paper is the *Evening News* dated February 24th. I can lay this paper on the Table of the House if it is wanted for reference by the hon. Members. That is, by the way.

Since the introduction of his gold policy how much gold, hidden gold in this country, has come to the Government treasury? I have been told that out of Rs. 4,000 crores worth hidden gold in this country only about Rs. 5 crores worth gold has come to the Government treasury. The measures he has adopted have caused misery to a large number of people in this country, as many as 10 million as some say and if you add five members to each artisan, it comes to 50 million who would be thrown into the streets at one stroke. I would ask the Finance Minister to answer this: whether the Rs. 5 crores worth of gold that has come to the Government Treasury is compensation enough for the sufferings of about 50 million people of this country.

There is another question I would ask. The policy is that the people are to declare the amount of non-ornament gold that they have; they can keep the gold ornaments. Now, what prevents the gold speculators and gold profiteers and gold hoarders in this country from secretly converting their hidden non-ornament gold into gold ornaments in the secret recesses of their mansions? What prevents them from doing that? There are rumours in the country that already gold hoarders and profiteers are taking advantage of the position, creating, panic in the minds of the people, trying to buy the gold that is there in the hands of our poor villagers—that is their life savings—and then selling them in the black market. I am also told that only right across the border, the price of gold in Pakistan is at present Rs. 160 whereas you have fixed Rs. 62.50 nP. here, if I am correct. Under the present circumstances, my quesion is, what

prevents the gold profiteers of this country to acquire large amounts of gold and what prevents this gold from going out of the country? These are some of the questions to which we expect a reply; and the Finance Minister owes his answer to this House and to the people and not to God.

My next question is about us, the tribal people. I have been told by some hon. Members who have been here in the House longer than myself, that ever since the inauguration of this Parliament, never has the President referred to the question of the tribal people in his Address. We hear a lot about what the Government intend to do for the tribal people, but the very fact that that question has consistently been ignored in the Presidental Address has caused some feeling that all that is being said about the tribal people is in the nature of lip sympathy. But that is a different question to which I shall have occasion to refer to and to discuss on other more appropriate occasions. But I come in particular to the question of tribal people inhabiting the north-east frontier of India. The Chinese aggression has revealed many things but among the many things things but among the many thing that have been revealed, it has revealed the importance of the tribal papulation in the northeastern part of India. A lady Member from Assam the other day was good enough to say that we now should take measures to integrate the entire north-eastern area. I wish she had said that before the people who are dominant politically in that area had decided in the face of opposition of all the minorities there to make Assamese the official language. If she had said that at that time, I would have placed some amount of faith and confidence in what she said, but when she says that now, after all the trouble has taken place, after so many hundreds of people have been put to suffering, after a few hundred houses have been burnt in the plains of Assam in the name of Assamese language, after a number of women have been dishonoured, after a number of people have been killed, all that kind of talk now sounds to me a kind of mockery. If you want the tribal people, who are the natural sentinels of this country, to play their full part in the defence of the country and in the economic development of the country, it is for you to give these people a feeling that they are respected, that they are being treated as equal citizens of this country, that they can be entrusted with responsibility.

On many occasions I have spoken about this in this House and I want to repeat it here that if the tribal people of the north-eastern part of India are to feel that they are free to play their full part in the country, that could be had only by freeing them from the domination of a particular community in that area, and at present the only solution to the problem lies in giving them a full state of their own. It is only then you would have taken the right step. You have given the people of Manipur their right to function in a responsible manner; you have a Bill before this House by which you are making the union territory of Manipur a responsible State, that is to say, with a legislature and a Government of their own. You have given that kind of thing to the people of Nagaland. You have given that kind of feeling to the people of Tripura, while there are a large number of tribal people in Assam who have not yet been given that sense of responsibility and respect that they deserve.

Before there is any real integration, the first thing is for the people to feel that they are equal and responsible as others. Let history take its own course. You have to deal with the problem as it is now. I am sorry that in spite of my best efforts, in spite of my respect for the President, I am unable to fully support the motion of thanks. As you know, I am an independent Member.

[Shri Swell]

I am not here to criticise the Government, just for the sake of criticism. I try to judge each question on its merits. But I am sorry to say that I am not able to fully associate myself with the motion of thanks to the President.

15.46 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Dr. Colaco (Goa, Daman and Diu): Mr. Spaker, Sir, in his calm and philosophic way, the hon. President of India has drawn a broad and on the whole reassuring picture of the situation prevailing in the country—in retrospect and prospect—and that has induced many Members of this House to point out also the shadows that mar the somewhat optimistic view of the picture. Are we not falling in some sort of complacency—ask many of them—practically ignoring the state emergency in which we are deeply entangled and which only treoretically or officially we seem to recognise? Are we not closing the eyes to the vast problem of unemployment in the country, to which the Gold Control Order is adding another great and sad chapter? And what about corruption, inefficiency and nepotism? What—say others—about the dictatorship of the Congress Party and its one-sided stress on non-alignment, socialist pattern of society, prohibition and such matters? In a different tone, some others go to ask: what about the deplorable mining situation in Kerala, with its thousands of unemployed? What about the tribal areas of North-East India? What do you know of the backward conditions of the eastern U.P.? What again about the poor thousands of gold-smiths thrown out of job?

I will not obviously enter into this field of discussion, nor add to it as I wanted to my particular criticism of the so called Family Planning, with all its moral and socio-economic and medical implications. But one point I want to stress is that the overwhelming weight of the Congress majority has been sometimes, to my knowledge, a national necessity, although I would like to have the Party making more frequent contacts with the opposition Parties and groups, because so often a middle course has to be adopted and, moreover, this way of tackling the affairs would at least lead to pacify the minds of the people and get fuller support from and for the country, in all its relevant endeavours and projects, and especially in this war effort and obviously in the peace effort that war always implies. Another point that I must here emphasise, and I think is far about all discussion, is that corruption, nepotism and bribery must be ruthlessly wiped out and rigorously suppressed and high moral standards must be introduced in and out of the bureaucratic machinery, for due sustenance of the dignity and the honour of the country, which have to be upheld not only in our international conduct and in our external relations and negotiations, but also in our conduct of internal affairs.

As you have seen, while, criticising with due respect and restraint the Presidential Address, each one of the speakers in this House and each mover of so many amendments has stressed also a particular point of his own local or regional interest or of the interest sometimes of a particular section of the population. I will also draw to the serene and broad picture sketched by the hon. President of India—I think it is my duty to do so—the shadows that still prevail upon our beautiful country of Goa, Daman and Diu whose real situation has certainly been ignored by the President and the Government of India, in all its full colour and relief. Goa is now, without exaggeration, one of the black spots in the map of India. I will not say, as the American Time of the 1st instant has ironically put it, that we have changed there from a province to a colony, but only, that we seem to have changed from a colony to

something not far distant from it. There, in my country, unemployment is still rampant, with the latest victims in the sector of lotteries suddenly closed and, now, the additional hundreds of goldsmiths thrown out of job by the stroke of a pen; there, the same confusion of the old Latin laws and of the new Indian laws still persists, throwing its shadow on the whole administrative and even judicial machinery, with the latest novelty, coming from November, of the extension to our country of 105 Indian laws, although with some reservation regarding their immediate execution; there, the presence of the additional administrators continues to be a handicap to the smooth and quick running of the services and may even be interpreted as a mark of an unjustified lack of confidence in the smart and reliable Goan personnel; there also, the narrow commercial policy suddenly established after liberation continues to be harmful to the commercial class and to the public at large, and all know that the prices of some commodities (fortunately not all) and of medicines and drugs have jumped to almost unbearable hights; there again,—but I must stop here, because in my very first speech in this House I had already emphasised other points, some of them fortunately not so relevant at this moment. To this confused picture. I regret to say, another somewhat odd aspect was added some weeks back by some otherwise respectable persons from a neighbouring State, who, forgetting that in this emergency we have to avoid all unnecessary controversy, had made themselves bold enough to go there and and talk about the merger of Goa into the State to which they belong, and cast some aspersions on our Konkani language, whose status is at least supported by men of such calibre as Katre, Dalgado, Valauliker, Salatore and others, and which is spoken practically by the totality of Goans (having the rare distinction of its Grammar being the first Grammar to be printed in the whole of Asia), while the other languages spoken in Goa score only a very very limited percentage.

Fortunately, as a silver lining in these black clouds, we have the old and emphatic promises of the Government of India and, if we go carefully through the many and repeated utterances of the hon. Prime Minister from 1946 onwards, we will find always a strong emphasis laid on the maintenance of our separate entity and of the standard of our mother-tongue: the Konkani language. Happily also, these same points have been again timely stressed by the Prime Minister, in his recent interview with a Goan journalist, Mr. Chandrakant Koni, editor of the fortnightly *Triveni*. To this ray of light, I will add another beam, and that is the work done by the Planning Board which, with all its unavoidable imperfections and shortcomings, comes to inaugurate a new era in our life, and strikes an altogether new note of optimism that was terribly lacking in our country. Some time back we were living there, (not ignoring many black clouds and grave ills), amidst many beautiful things minus this most precious and sacred thing—freedom—and now we seem to have there only liberty minus all these beauties and blessings of the modern world. Now, with this Plan, a new stage is attained in which a quick pace of progress and development is dawning on our country. And yet another happy sign I see in the Bill already introduced in this House regarding the future political status of the Union Territories. I will speak on this Bill in due course, but I must emphasise here and now that this Bill, with due adjustments and comprehensive modifications, will certainly open a new broad way to our further advancement, with wide powers conferred on our people, through the electoral system, to conduct their own affairs through a Legislative Assembly with a responsible Ministry, and two elected representatives to Parliament, as I have already pointed out in my first speech in this House. This done, I personally take my job as finished in the political field of my country to which I had to jump unwillingly, hearing, I may say, some distant and sudden call from that compelling force

[Dr. Colaco]

that guides human destinies. But, before ending these few words, I must again stress, as I had done last September, that a status of a Union Territory, although it does not mean at all, as some seem candidly to believe, any prospective merger with some State, will not satisfy our real aims and we will try to develop into a full-fledged State in the Indian Union, as for that purpose we find in ourselves and in our country full aptitude, full self-confidence and full economic viability.

I only pray God that my countrymen, from inside and outside Goa, join hands, in this really decisive hour, in the great task that confronts them, irrespective of creed, caste and social differences, and endeavour to build a greater Goa, along with Daman and Diu, within a prosperous and peaceful Indian nation.

United we stand.....

श्री मौर्य : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय, राष्ट्रपति जी के ३,००० शब्दों के सुन्दर और उच्च कोटि के भाषण को पढ़ने का मुझे मौका मिला । मैंने उसे बड़े गौर से पढ़ा । उस में मुझे बहुत सी विद्वतापूर्ण हुई बातें देखने को मिलीं । इस के लिये मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं ।

परन्तु आश्चर्य और खेद इस बात का है कि लाखों प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की आर्थिक समस्या, लगभग २० करोड़ भूमिहीन मजदूरों की भयंकर दुर्दशा, २ करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, ७ करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट्स, १६ करोड़ बैकवर्ड क्लासेज, अर्थात् २५ करोड़ शोषित, पीड़ित, कठोर कर्मों सर्वहारा समाज की आर्थिक तथा सामाजिक दुःखदायी समस्या के सम्बन्ध में एक शब्द भी आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है । इस से आगे बढ़ कर जब मैंने देखा कि भारत में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और संकटकाल (इमर्जेंसी) के दुरुपयोग तथा भारतीय सेनाओं की भारी पराजय के उपरान्त सरकार को चेतावनी के रूप में एक शब्द को भी आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्थान नहीं दिया गया है । इन बातों को देख कर मेरे मन को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची ।

सब से पहले मैं शिक्षा को लेना चाहता हूं जिस के विषय में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारा संविधान है, हम संविधान को अपनी सब से ऊंची धार्मिक पुस्तक मान कर चल रहे हैं । उसी के आर्टिकल ४५ में, जो कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है, लिखा है :

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

आज संविधान का लागू हुए लगभग १३ वर्ष हो चले हैं । दस वर्ष की बात कही गई थी । कहा गया था कि दस वर्ष में भारतवर्ष में १४ वर्ष तक के बालकों के लिये अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा होगी । यह तो हमारे संविधान की पवित्र धारा ४५ कहती है । इसी तरह के सब १४ डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं । परन्तु आज मुझे खेद होता है कि संविधान की एक पवित्र धारा भी आज तक लागू नहीं हुई है । अभी भी राष्ट्र में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १४ वर्ष तक के बालकों को नहीं दी जाती । इससे आगे बढ़ कर मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा को देने वाले जो अध्यापक हैं, अगर उन की दुःखदायी स्थिति और उन की दुर्दशा को देखा जाये, जो कि इस

राष्ट्र के निर्माता हैं, जो इस राष्ट्र के भावी नेताओं के भाग्य विधाता हैं, जिन के ऊपर एक तरह से यह राष्ट्र आधारित है, कि वह ६० और ६५ रु० में किस प्रकार से अपना गुजारा करते हैं, तो और भी दुःख होगा। दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले मेहतर को भी ८० रु० मिलते हैं। खेद इस बात का है कि राष्ट्र के निर्माता, यहां के बालकों के आदर्श के रचियता को ६० या ६५ रु० मासिक मिलते हैं। इस के बारे में भी कोई विशेष संकेत आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है।

खेती के बारे में स्वयम् राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैरा ४ में जोर दिया है, इस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं। वे कहते हैं :

"Agriculture....is the most important sector of our economy...."

यही नहीं आगे बढ़ कर उन्होंने पैरा १५ में कहा है :

"A strong agricultural base is a pre-requisite of national security."

अगर राष्ट्रपति जी की इन भावनाओं को देखा जाय, और खेती के लिये राष्ट्र में जो तैयारी है उस को देखा जाय तो वह एक दूसरे से अलग अलग नजर आती हैं। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में खेती के लिये कितना धन रक्खा गया था और अन्य कार्यों के लिये कितना रक्खा गया था ? तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। उस के दौरान में जो भारत में ७५ फी सदी खेती से ताल्लुक रखते हैं, उन के लिय कितना रुपया खर्च किया जा रहा है ? खती के लिये कितना खर्च होगा। इस से पता चलेगा कि हमारी योजनायें उस भावना के ऊपर आधारित नहीं हैं जो कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैरा ४ और १५ में इस राष्ट्र के सामने, और संसार के सामने रक्खी है। यही नहीं है, बल्कि यहां पर भूमिघरी आन्दोलन चला था, लोग भूमीधर बनें। किसान भूमि के मालिक बनें। उन्होंने दस गुना दिया। किसी ने अपने बैलों को बेंच कर, किसी ने अपनी स्त्री के जवरों को बेंच कर और किसी ने अपनी जमीन को बेंच कर या मकान गिरवी रख कर दस गुना दिया। उसके बाद आज चकबन्दी की बीमारी उन के पीछे लगी है। यहां बहुत से आदरणीय सदस्य बैठे हैं, चाहे वे कांग्रेस के हों या विरोधी दलों के, वे स्वयम् जानते हैं कि किस प्रकार चकबन्दी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किस प्रकार से गरीब किसान का शोषण हो रहा है। चकबन्दी के बाद वे कुछ आशा करते थे। उसके बाद कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। लेकिन मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फ़ार्मिंग में यहां के २० करोड़ लैंडलेस लेबर के लिये, २० करोड़ खेतिहर मजदूर के लिये कोई जगह नहीं है। जिन २० करोड़ मजदूरों ने जन्म जन्मान्तर से खेत जोता है, बोया है, पानी लगाया है नराया है, काटा है और गहाया है लेकिन खाया नहीं है, उन २० करोड़ मजदूरों के लिये जो कि भूमिहीन हैं उन के लिये कोई भी प्राग्राम काआपरेटिव फार्मिंग के पास नहीं है। इस कारण हम कहते हैं कि जो हल चलाने वाले शोषित समाज के किसान और मजदूर हैं और जो रात दिन पसीना बहा कर काम करते हैं उनको उनकी कमाई का अंश नहीं मिलता है और इसलिये ऐसी जमीन जहां कि हल चलाते हैं उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। इस भावना के ऊपर हमारे राष्ट्रपति जी की भावनाएं आधारित हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यह जरूरी है कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स का सरकार राष्ट्रीयकरण करे। हम शोषितों के बाजुओं में इतनी ताक़त

[श्री मौर्य]

है कि राष्ट्रीयसंकट के अवसर पर इतना अनाज पैदा करके दिखा सकते हैं कि अपने देश क्या समस्त एशियावासियों को हम अन्न खिला सकते हैं लेकिन सरकार अनएकोनामिक होल्डिंग्स का राष्ट्रीयकरण करे। डालमिया और बिड़ला जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के बड़े बड़े फार्म स्थित हैं और उन से कोई भी इस देश को लाभ नहीं होगा।

16 hrs.

इस से आगे बढ़ कर भ्रष्टाचार के बारे में मैं जब देखता हूं तो पाता हूं कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक भी शब्द भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं कहा है। देश में आज भ्रष्टाचार का दमन चक्र लोकशाही के ऊपर बड़े जोर से चल रहा है और किसी दिन वह लोकशाही को हड़प सकता है। यह खेद का विषय है कि उन्होंने एक भी शब्द इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं कहा।

यह ठीक है कि मूंदड़ा और डालमिया को सजा मिली है लेकिन केवल मूंदड़ा और डालमिया को सजा दे कर आप फारिग नहीं हो जाते हैं ' और आप का कर्त्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। इस देश के कोने कोने में और गली गली में मूंदड़ा और डालमिया मौजद हैं। मैं स्वयं एक पूंजीपति के बारे में बतला देना चाहता हूं जो कि सत्ताधारी वर्ग को बहुत काफ़ी धन दे कर यहां के उद्योगों पर ऐसे बैठे हुये हैं जैसे काला नाग धन पर बैठा रहता है, खजाने पर बैठा रहता है। इन्हीं पूंजीपति महाशय को यहां दिल्ली में एक फ़ील्ड आफिसर चाहिये। ५००० रुपये तनख्वाह देंगे जो फ़ील्ड आफ़िसर उनके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनायें, जो फ़ील्ड आफ़िसर उनके काला बाजार के कमाये हुये पैसे को जो कि उन्होंने मजदूरों की आह लेकर कमाया है, उसे वहां दूसरों पर खुले खजाने काम करके दिखा दे कि वह वहां पर उनका व्हाइट पैसा है। मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस तरह के उद्योगपति और पूंजीपति जो कि आज शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे पूरा राष्ट्र तबाह होता चला जा रहा है। कम से कम वह शख्स शेखसादी के इस शेर से तो सबक सीखें :—

चूं आहेग रफ्तन कुनद जाने पाक।
च बर तख्त मुर्दन च बसूये ख़ाक।

ऐ पूंजीपतियों हमेशा के लिये तुम जिंदा नहीं रहोगे, मरोगे, तुम्हारा भी अंत होगा लेकिन वहां पर लाखों करोड़ों मजदूर मजलूमों को मार कर और राष्ट्र का पतन करके तुम्हारा क्या भला होगा ?

इसके आगे मैं संकटकाल (इमरजेंसी) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि संकटकाल (इमरजेंसी) का दुरुपयोग हुआ है और हो रहा है। सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार ने बहुत से राजनैतिक कार्यकर्ताओं की चाहे वे सोशलिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों या अन्य राजनीतिक दल या पार्टी के कार्यकर्ता हों, उनको अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल कर गिरफ्तार किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस इमरजंसी में नौकरशाही पनप रही है। उसको बढ़ावा मिल रहा है। स्वयं जिस अलीगढ़ से मैं आता हूं वहां पर मुहम्मद नादिर उर्फ़ नादिर अली के नाम से एक इन्सान है। किसी पार्टी में वह चार आने का सदस्य नहीं है। किसी राजनीतिक मंच से वह कभी बोल नहीं। बोलना तो दरकिनार कभी किसी राजनीतिक मंच पर बैठा नहीं चाहे वह कांग्रेस का हो या विरोधी दल का हो। जो राजनीति का नाम नहीं जानता लेकिन आज वह वहां के कलक्टर साहब की तानाशाही का शिकार हो रहा है। डी० आई० आर० लागू

करके उन बेकसूर इन्सान को जेल के सींखचों में डाल रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मैम्बर साहब से कहूंगा कि एक इंडिविजुअल का, किसी एक शख्स का केस रिप्रेजेंट न करें।

श्री मौर्य : यह केस बड़ा जरूरी है। म इसे नहीं रखना चाहता था लेकिन इसको लेकर पूरे जिले में तूफ़ान सा मचा हुआ है .....

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से एक इंडिविजुअल केस को नहीं रख सकते और कलक्टर साहब के बरखिलाफ इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।

श्री मौर्य : खैर मैं इसे छोड़ कर आगे चलता हूं।

आदरणीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा १४ में यह कहा है :—

"Soon after the declaration of Emergency, the central organisations of labour and management unanimously adopted an industrial truce resolution aiming at the total elimination of industrial disputes, and increase of production and reductian of cost to the maximum extent possible. In pursuance of this, Emergency Production Committees have been set up at the Centre, in the States and in many industrial establishments."

इस तरह की भावना मजदूरों के अंदर जागृत हुई। स्वयं राष्ट्रपति जी ने इस की ओर पूरे राष्ट्र का ध्यान इस ओर दिलाया है लेकिन यह खेद और दुर्भाग्य का विषय है कि पूंजीपतियों ने मजदूरों की इस भावना से नाजायज फ़ायदा उठाया है। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने इस पवित्र प्रतिज्ञा की आड़ में कठोरकर्मा सपूतों का शोषण किया है। जितना काम उन्हें करना चाहिये था उससे ज्यादा किया, पीक आवर्स में काम किया। उससे पूंजीपतियों का फ़ायदा हुआ।

स्वयं मेरे यहां के एक पूंजीपति हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी बात कहूं तो कहा जायगा कि फिर अलीगढ़ की बात करते हैं लेकिन मुझ से कहे बगैर नहीं रहा जाता कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर वहां रहते हैं। इसी इमरजेंसी के जमाने में ४ लाख की जायदाद, चार लाख पैसा लगा कर उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर आकर आराम करते हैं। एक तरफ़ तो यह चक्कर हो और दूसरी तरफ़ मजदूर इमरजेंसी में धन दे रहे हैं :....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। मैंने मेम्बर साहब को कहा है कि यहां किसी के बरखिलाफ़ जिसको कि उसका जवाब देने का मौका न हो, कुछ न कहा जाय।

श्री मौर्य : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा .....

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा क्या नाम लिया जा सकता है? क्या कोई सदस्य समझ नहीं रहे हैं?

श्री मौर्य : मैं यही कहूंगा कि इस इमरजेंसी को हटाया जाय। इससे राष्ट्र को फ़ायदा नहीं हो रहा है बल्कि इससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। इमरजेंसी के हटने पर जो लोग चीन से मिल कर मुल्क को दगा देना चाहें या किसी और मुल्क से मिल कर देश के प्रति गद्दारी करना चाहें उन के लिये हमारे पास कानून है। उनके नौर्मल लाज ऑफ़ दी लैंड काफ़ी हैं। प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट है और ला ऑफ सेडीशन आदि हमारे पास मौजूद हैं। इनकी सहायता से हम देश द्रोहियों से निपट सकते हैं। मैं इसलिये मांग करता हूं कि इमरजेंसी को समाप्त किया जाय।

[श्री मौर्य]

इमरजेंसी के होते हुए यहां पर उप-चुनाव होने की बात चली है। बात साफ यह है कि इमरजेंसी के रहते उपचुनाव ईमानदारी तथा स्वतंत्रता के साथ सम्पन्न नहीं हो सकते। आज हमारी जबानों पर ताला पड़ा हुआ है और वहां पर खुल कर कोई बात नहीं कही जा सकेगी। सत्तारूढ़ वर्ग के खिलाफ़ कोई भी बात नहीं कही जा सकेगी, सत्ताधारी नेताओं और उनके द्वारा चलाई जा रही गवर्नमेंट के खिलाफ़ खुल कर कुछ भी कहा न जा सकेगा, जिससे कि सारे राष्ट्र को धक्का पहुंचा है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इमरजेंसी के रहते हुए उपचुनाव ईमानदारी से निष्पक्ष नहीं कराये जा सकते।

भारतीय सेनाओं के बारे में म यह कहना चाहता हूं कि सेना में भरती जातीयता के नाम पर हुई है। सन् ४३ में अंग्रेजों के ज़माने में इसके बारे में इश्तिहार निकलते थे जिनमें लिखा जाता था कि क्षत्रियों की भरती है, ठाकुरों की भरती है। इस तरह के पैम्पफलैट्स सन् ४३ में देखे थे लेकिन आज जब कि जनतंत्र राज्य है, जबकि हम यह दावा करते हैं कि हम जातीयता में विश्वास नहीं करते है तब इस तरह के नोटिसबोर्डस लिखे जायें कि यहां पर अछूतों की, चमारों की और भंगियों की भरती नहीं है, यह इस राष्ट्र के लिये शोभाजनक प्रतीत नहीं होता। यह बड़ अफसोस की बात है। जहां तक मार्शल कम्युनिटी की बात है मैं यह बता देना चाहता हूं कि मार्शल कम्युनिटी के बारे में अगर इतिहास उठा कर देखा जाय तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि शैडयूल्ड कास्ट्स या बैकवर्ड क्लासेज किसी भी माने में किसी भी मार्शल कम्युनिटी से कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। सन् ४३ के बाद में भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि चुमार और महारे रेजीमेंट बनीं। उन्होंने इस देश की सीमाओं पर और यूरोप और इंग्लैंड में जा कर अपनी बहादुर का सबूत दिया है। सर पेटरिक कारडिन, जनरल ब्रिग्स के लेख, माहेर, तथा चमार रेजीमेंटस की वीरता से भरे पड़े हैं। जातीयता के नाम पर सेना में भरती होना और जातीयता के नाम पर रेजीमेंट बनाना देश के भविष्य को खतरे में डालना है। मैं यहां पर यह नहीं कहता कि चमार रेजीमेंट खोली जाय, भंगी रेजीमेंट खोली जाय। वहां पर महार रेजीमेंट ने जैसी बहादुरी से काम किया उसी तरह से चमरा और अन्य जो छोटी कहो जाने वाली जातियां है व भी बहादुरी के साथ काम कर सकती है। इसलिए जातीयता के नाम पर रेजीमेंट की समाप्त किया जाय और अगर उनको समाप्त न किया जाय तो जातीयता के नाम पर जो रैजीमेंट सन् ४३ में बनी थी, ४४ में थी, ४५ में थी, उनको सन् १९४६ में कांग्रेस सरकार ने क्यों समाप्त कर दिया?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री मौर्य : प्रदेश आपस में झगड़ रहे हैं। इस तरह की चर्चा सदन में आई और अखबारों में भी सुनने में आता है कि केवल प्रदेश ही आपस में नहीं झगड़ रहे हैं बल्कि केन्द्रीय मंत्री भी इस बात की शिकायत करते हैं कि वह केन्द्रीय सरकार के साथ कोआपरेट नहीं करते है, केन्द्रीय सरकार को सहयोग नहीं करते हैं। इस के बारे में आदरणीय प्रेसीडेंट साहब को कुछ कहना चाहिए था। आज तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, केन्द्र में भी और प्रदेशों में भी। जब उन में आपस में यह नहीं चल पाता है तो भविष्य में किस तरह से निबटारा होगा, जबकि कहीं कम्युनिस्ट सरकार होगी, कहीं सोशलिस्ट सरकार होगी, कहीं रिपब्लिकन सरकार होगी तो कहीं कांग्रेस—कांग्रेस का तो मेरे खयाल से कहीं नामोनिशान कुछ दिन बाद इस देश में नहीं रहेगा। जब बहुत सी पार्टियों की सरकार बनेगी तब साथ में किस तरह से पटरी बैठेगी और काम चलेगा?

चिकित्सा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा । म यह नहीं कहता कि बराबर का सब को खाना मिले, मैं यह नहीं कहता कि एक तरह के सबको रहने के वास्ते मकान मिलें, लेकिन मैं इतना जरुर कहूंगा कि अगर किसी पूंजीपति का बालक टी० बी० का शिकार हो और मिल में काम करने वाले मजदूर का बालक टी० बी० या तपेदिक का शिकार हो, तो कम से कम अगर खाना उनको एक जैसा नहीं मिल सकता, पढ़ने की व्यवस्था एक सी नहीं मिल सकती, रहने को एक जैसा नहीं मिल सकता तो कम से कम उनका इलाज तो एक जैसा हो । मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह का प्रजातंत्र है ? यह किस तरह का स्वतंत्र भारत है जिसमें लाखों मजदूरों के बच्चे वगैर इलाज के मर जाते हैं ? हजारों अस्पताल इस मुल्क में ऐसे हैं जोकि देहात या कस्बे में हैं और जिनमें कि कोई डाक्टर नजर नहीं आता ।

एक बात कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा । मैं अध्यक्ष महोदय से तीन मिनट का समय और चाहूंगा । मेरी पार्टी से कोई भी नहीं बोला है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं केवल एक मिनट और ले लीजिए ।

श्री मौर्य : कृपया दो मिनट तो मुझे दे ही दिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा आगे बढ़िये ।

श्री मौर्य : श्रीमन्, यहां पर २५ करोड़ शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति बसते हैं जिनमें कि २ करोड़ शैडयूल्ड ट्राइब्स हैं, ७ करोड़ शैडयूल्ड कास्ट्स हैं और १६ करोड़ बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं ।

भारत के इन २५ करोड़ शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के विरुद्ध एक शब्द भी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं है । राष्ट्र के २५ करोड़ शूद्र कहे जाने वाले विशाल जनसमूह को यदि सामाजिक तथा आर्थिक शोषण की धधकती ज्वाला से नहीं बचाया गया तो लोकशाही का यह शीशमहल भी उसी ज्वाला में जल कर खाक हो जायेगा . . .

एक माननीय सदस्य : अब कोई शूद्र नहीं कहता ।

श्री मौर्य : यह भी खूब रही । आप शूद्र के नाम पर इनाम देते हैं, आप नौकरियों देते हैं । आप बहुत से लोगों को एम० एल० ए० और एम० पी० केवल अछूत के नाते से इस सदन में बैठाते हैं । किस तरीके से आप नहीं मानते हैं? आप मानते हैं अबलत्ता हम नहीं मानते और हम इस बात को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन आपकी सरकार माननी है और जातीयता का नाम देती है । वह जातीयता के नाम पर पगड़ियां और तमगे देती है । माननीय सदस्य उस को कैसे नहीं मानते ?

मैं कह रहा था कि अगर पिछड़े वर्गों पर यह दमनचक्र इसी तरह से चलता रहेगा, अगर यह ज्वाला इसी तरह से उन के सिरों पर धधकती रहेगी, तो यह ज्वाला लोकशाही के शीशमहल को भी एक दिन जला देगी । मेरी विनती है कि हम इस देश के एक बहुत बड़े अंग को भुला कर लोकशाही को इस मुल्क में जीवित नहीं रख सकते हैं । आज मुझे आदरणीय बाबा साहब डा० अम्बेदकर के ये शब्द याद आते हैं कि "जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है ।" यद्यपि आज हम आजाद हैं, लेकिन जातीयता के अजायबघर आज भी इस मुल्क में मौजूद हैं । इस तरह की आजादी को आजादी कहना आजादी की तौहीन है आजादी का मजाक उड़ाना है । यह किस तरह की लोकशाही है ? इस तरह की लोकशाही पर चल कर हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण खत्म कर दें ।

श्री मौर्य : अखबारों से मुझे मालूम हुआ है कि राज्य सभा में श्री वाजपेयी ने काश्मीर के सम्बन्ध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस-चासलर, श्री तैयबजी, के भाषण के कुछ अंश को क्वोटकिया । लेकिन उन के भाषण की एक लाइन उस में से छोड़ दी गई है अगर उस लाइन को जोड़ दिया जाए, तो जिन के खिलाफ वह बात कही गई थी, उन के साथ न्याय हो सकता है और श्री वाजपेयी को अपनी बात का जाब भी मिल जाता है । राज्य सभा में उन्होंने इस भाग को क्वोट किया था :

> "The territory Pakistan holds in Kashmir should go to Pakistan together with such portions along the cease fire line that India now occupies but which are essential to Pakistan for developing the areas under her control."

लेकिन श्री तैयबजी ने इस सम्बन्ध में जो यह कहा था कि "The Valley should go to India" उस को छोड़ दिया गया है अगर इस लाइन को उद्धरण के साथ जोड़ दिया जाये, तो श्री वाजपेयी ने राज्य सभा में जो कुछ कहा, उस के माने उल्टे हो जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री मौर्य : अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हम इस देश के बदबे हुए उत्पीड़ित और शोषित लोगों को उठाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें । अगर हम इस देश के करोड़ों लोगों को भूल जायेंगे और जातीयता पर आधारित असमानता और विषमता को बढ़ायेंगे, तो फिर लोकशाही कभी भी इस मुल्क में जीवित नहीं रह सकती है । लोकशाही और जातीयता एक साथ नहीं रह सकते । जनतंत्र और असमानता एक साथ नहीं रह सकते । समता में ही लोकशाही जीवित रह सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जबर्दस्ती बोलते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वह मुझे धन्यवाद देते हैं ।

Shri H. P. Chatterjee (Nabadwip): Mr. Speaker, the situation which we are facing today is very grave, probably the greatest danger that has ever overtaken our nation. The Chinese have declared from the housetop their intention. They are after world revolution. There is no 'hide and seek' about it. When they entered Tibet, they said they were going to free Tibet from imperialism. How they have 'freed', we know. They destroyed Tibetan culture, their religion—in fact, everything—and imposed their own system of government on them. They converted the whole of Tibet into a war base. A network of all-weather roads has been constructed. They are still going on constructing roads, and first-class aerodromes where they have assembled jet bombers and everything.

They are now fraternising with Pakistan and Nepal, following the policy of divide-and-rule. Of course, Nepal and Pakistan are of our own flesh and blood; they will soon feel the embrace, if they are not cautious enough, of the bear, rather the Chinese dragon. Swollen with insolence of power, the Chinese now do not care even for their brother, the USSR. They do not care for world opinion, nothing of the kind. They will soon come down upon us. Now they are simply resting and preparing. In the Chinese war manual, they have said: "ta'ta tan tan, ta'ta tan tan". That means: fight a while; talk a while;

fight a while; talk a while. So, the 'talk a while' is now going on. The "fight a while" will soon follow. We must be very cautious about it. Our very existence is at stake. We should sink all our differences. I am an unattached Member and I can therefore speak what I feel without caring for any party obligations. All the parties should now be dissolved. There should be one party to face the gravest danger that is before us. The Chinese dragon with blood shot eyes is staring at us. Look at the language of their diplomatic correspondence and what they speak. They have also declared that they are after this game, we should not be caught napping. We must be very careful now.

I am glad that the Government has been armed with extra-ordinary powers. I would have preferred to have a national government here. Even otherwise, we must all stand solid behind the present Government now. But there should not be any misuse of these extra-ordinary powers. That will not create enthusiasm for the defence efforts. Now, I come from a very important constituency of West Bengal. People have sent me here knowing that I am an independent Member. What is happening there? In the name of national emergency, the freedom and civil liberties of innocent people are taken away. I shall fail in my duty if I do not report these things to you. Otherwise, I would not have spoken at all. I shall give a typical example. I have representations; I met deputations. They came here as many such things are happening. Here is a typical example. Here is the case of a gentleman, the headmaster of a high school, an M.A.B.T., honest and dutiful. I have enquired into this matter and I am responsible for what I say. I am therefore bringing it to your notice.

Mr. Speaker: There is this difficulty. If the Members take up individual cases such as the case of a headmaster and it is brought here, how will the Minister reply? He has to reply. The hon. Member says that he has verified them. That may be even true. But if these facts are sprung suddenly on the Minister, how is the Minister to reply to these facts? If individual cases are to be discussed, or brought before the House, prior notice should be given to the Minister that a case is being brought so that he may be ready. Otherwise, this would go unchallenged and it would not be proper.

Shri H. P. Chatterjee: I have given this representation already to Shri Lal Bahadur Shastri: he has a copy of it already. He will reply after he gets his chance and after he has enquired. If I were not to bring such things here, why am I here?

Mr. Speaker: He is not here simply to take up individual cases.

Shri H. P. Chatterjee: I assure you I have given him this and I shall read another letter which I have written to him. He will reply when he has his chance. It is not my fault that he is not present here just now.

Mr. Speaker: Individual cases should not be taken up. Did he say that he would be taking up this case here, in his letter?

Shri H. P. Chatterjee: I am not mentioning anybody's name. I will not name anybody. Give me a patient hearing and you will understand that what I am saying is necessary for strengthening the Government.

Mr. Speaker: Order, order. I am not objecting to the hon. Member making any observations. Whether he does it for strengtheing the Government or for weakening the Government, that is not my purpose. He might criticise the Government as much as he wants. but what I am objecting to is that individual cases, when they are taken up, go unchallenged or unreplied to. Then, it might create a very bad impression among the people. So, no individual cases might be taken up. That was

[Mr. Speaker]

what I said. Otherwise, in general terms he can say anything that he likes.

Shri H. P. Chatterjee: Then, I shall simply say XYZ. I do not say 'headmaster'.

Mr. Speaker: Let it be X then.

Shri H. P. Chatterjee: Yes; let it be X. Then, X is an M.A., B.T. He is the headmaster of a school. Can I not say that he is a headmaster?

Mr. Speaker: He can say "teacher".

Shri H. P. Chatterjee: All right. Let us say he is a teacher of that school. Now, there is the PUB—President of the Union Board. That president is known to me because I was for long the Congress President in that district. During British regime, this president was an ardent supporter of the British. When the non-cooperation movement was launched by the Congress, he fought the Congress on every front. Then, when the Muslim League came to power, this president of the Union Board became a great and ardent champion of the League. Wherever there was power, he was there. He is a businessman and he has borrowed Rs. 40,000 from a bank, and that bank is in liquidation now, and to avoid decreetal dues, he has transferred his property. He is such a powerful person. He hobnobs with officials and knows how to please them: he gives them good dishes when they come to the union. Not only that; he plays card with them to.

Now, this gentleman—the headmaster—XYZ, or say, X—the teacher,—whatever he is was in charge of that school. When he came to the school, he never knew the situation. He is a new man, an honest, sincere fellow. The fault of this teacher, according to the PUB, was this. He refused to admit in the voters' list, 50 heads of voters submitted by the PUB after the final publication of the voters' list. That was the first fault of the teacher. Secondly, the headmaster disqualified —I am sorry—X, who was in charge of the school, disqualified.....

Mr. Speaker: I am sorry I shall have to stop him. He is persisting in the same thing, and is trying to make out a case.....

Shri H. P. Chatterjee: I am only referring to what is happening; nothing else. Then, my point is.....

Mr. Speaker: He should take care not to refer to any inidvidual case.

Shri H. P. Chatterjee: I am sorry; I shall take care.

Mr. Speaker: Hon. Members have freedom here, but that should not be misused by mentioning some person and making representations. That is not the business of Members of Parliament here. It should not be done. The persons concerned are not here to defend themselves, however much the Member might say that he has verified the facts. Of course, he has to get information from others he does not do it or throw on his own personal knowledge. Even if he has verified it, that does put the Minister in a very awkward position because he cannot answer all those charges that are being made. I have warned the hon. Member twice that he hould not indulge in such a thing.

Shri H. P. Chatterjee: Let me finish, and then you will see that I am speaking of a general case only and not a single, individual case.

Mr. Speaker: But the facts that he has given are about an individual.

Shri H. P. Chatterjee: The situa- is general and I am bringing it out by citing a typical case. My point is this. This is true of many other cases. So, that teacher, that gentleman, did not allow those names in the vaters' list. I will not go into this, because I find that it is not pleasing to you.

Mr. Speaker: It is not a question of pleasing.

Shri H. P. Chatterjee: I shall be very obedient to you here. My point is, this gentleman in charge of the school is a newcomer. He incurred the wrath of the mighty PUB, and the report went against him by the henchmen of the PUB that he is communist minded! The only thing is, he is communist minded. Our hon. friend, Shri Surendranath Dwivedy, the leader of the Praja-Socialist Party, even termed some of the Congress Members who hold progressive views as communist-minded! Look at it what a funny thing? Everyone can be communist-minded! They do not say he is communist; but they say he is 'communist-minded!' And then the law come down upon him and he is taken and put behind the prison bars. He is rotting there shedding tears. So are others. Why am I here, if I cannot present their case here and tell what is happening in my constituency? They have sent me here. Innocent persons are suffering. It I cannot help them it is better that I be also sent to Jail. I volunteered to go to the front and now I shall volunteer to go to the jail, because then I shall be able to share the hard lot of those who are rotting there and shedding tears. This is not the only case. There are other cases about minorities. This is one P.U.B. He is the nephew and his maternal uncle is there, who is another P.U.B. They are birds of the same feather. Sir, I like to tell you in general what they are doing. The maternal uncle P. U. B. is after the minorities who have voted for Shri Kashi Kant Maitra, a P.S.P. M.L.A., son of Late Pandit Lakshmi Kant Maitra who was a member here. He is an able advocate and he got the victory over the Congress Candidate. Fantastic charges are being made against those who have voted for the P.S.P. Party. They have voted for me also. I cannot help them in any way. If we move bail applications, the courts will say—we have given them this power—that no bail can be given until the person is known to be innocent, by the magistrate. But before the trial is finished, how can the magistrate say that he is innocent.

Mr. Speaker: He has taken 15 minutes. He should conclude now.

Shri H. P. Chateerjee: I have so so many things to speak about, because I have given three amendments. I was asked to move one amendment only.

Mr. Speaker: He should have talked about the amendments, instead of saying all these things.

Shri H. P. Chatterjee: I have brought it to your notice; this is about innocent persons, who do not dabble in politics. Now about political persons, *i.e.* persons belonging to political parts, I shall tell you in general what is happening in Bengal? You will kindly allow me to read this letter which I wrote to Shri Lal Bahadur Shastri. This is about an M.L.A. of Shantipur in my constituency. He does not belong to the communist party. He belongs to a party which is dead against the stalinist communists. The house of this MLA was looted. This is not an individual case; several persons have been arrested like that. I shall read the letter:

"Dear Shastriji,

I wish to bring to your attention certain disquieting incidents in West Bengal, about which I have direct information.

Shri Kanai Pal, M.L.A. (West Bengal) was elected in 1962 from one of the constituencies comprising my parliamentary area. He was a candidate of the Revolutionary Communist Party and defeated the Congress nominee. He is a political sufferer of long standing having been convicted during the 1942 movement. In November 6 he fas committed to prison under the West Bengal Security Act and he has written to me a long letter

[Shri H. P. Chatterjee]

from jail. It makes distressing reading. Some days before his arrest a number of people including Congressmen attacked and looted Shri Pal's residence and also the local office of the Revolutionary Communist Party (Shantipur): Shri Pal (and his party) follows an indisputably patriotic policy regarding the India-China issue, but it appears that on account of political vindictiveness certain interested Congressmen have crudely misrepresented his views, carried on slanderous propaganda and exercised their influence to get him imprisoned. He writes that he was consulting his lawyer about the vendetta against him when he was requested to go to the Police Station where he was arrested and detained. Another member of the RCPI with a long record of service and suffering, Janab Maksed Ali has also been similarly detained and refused classification in jail."

They are not classified. If he happens to be a Muslim, he will never get a classification.

Mr. Speaker: These charges are too general and even too wide. (*interruption*). He should not take advantage of this floor. If he does it outside, he may be run down in court.

Shri H. P. Chatterjee: They are doing it and I shall not be able to expose them. I have some experience of parliamentary life....

Mr. Speaker: If he has that experience, then he has to submit to the rules that are here inside this House.

Shri H. P. Chatterjee: Inside this House a spade should be called a spade, and I am calling a spade a spade.

Mr. Speaker: No, no; I would not allow that.

Shri H. P. Chatterjee: I am sorry, Sir. I am always obedient to your ruling. Let me finish this letter and then I will sit down.

Mr. Speaker: Why should he finish it, when I am asking him not to read it. He has read enough now.

Shri H. P. Chatterjee: These things are happening.

Mr. Speaker: If we disagree on a particular point.....

Shri H. P. Chatterjee: This will kill our enthusiasm for the defence work, if these things go on.

Mr. Speaker: He has read most of the letter. If he has to say anything further he may do so.

Shri H. P. Chatterjee: Only a few more lines are left; if you will allow me I will finish it. I have been waiting for three days to place this before the House. I know I am an Independent Member and I thought I will have no chance. Some times I feel I will have to resign and go away. Perhaps that I may do one day.

Mr. Speaker: Whatever he might do, that is his job and not mine.

Shri H. P. Chatterjee: Thank you. Parliament should be a real Parliament, a democratic Parliament representing democracy.

"I know something of the political....

Mr. Speaker: This will not be recorded now.

Shri H. P. Chatterjee:....*** All right, Sir.

Mr. Speaker: I hope the House would like to sit up to six o'clock today. There is much pressure and I hope hon. Members would agree. We cannot sit beyond five o'clock, perhaps, day after tomorrow. Therefore, we must sit today up to six.

***Not recorded.

श्री बालकृष्ण सिंह (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे भी धन्यवाद देने का अवसर प्रदान किया । राष्ट्रपति का अभिभाषण यद्यपि संक्षेप में है लेकिन उसमें अपने देश के वर्तमान और भविष्य का स्वरूप देखा जा सकता है । भारत ने जिस समाज की रचना का संकल्प किया है उस लक्ष्य की तरफ अब तक देश ने क्या किया है उसका संक्षिप्त विवरण देते हुये राष्ट्रपति ने उस संकट की ओर संकेत किया है जो चीन के आक्रमण से इस देश के सामने है । भारत शांतिप्रिय देश है और शांति के तरीके से अपने देश का निर्माण कर रहा था । लेकिन चीन को यह बात पसन्द नहीं थी कि भारत अपने प्रयोग में सफल हो । वह चाहता था कि भारत की तमाम योजनायें विफल हो जायें । इसलिये सीमा का झगड़ा खड़ा करके हमारे देश पर आक्रमण किया है । हमारी सभी योजनाओं को विफल करने की उसकी मंशा है । यदि इस बात का हमारी योजनाओं पर असर पड़ता है तो चीन की जो मंशा है उसकी पूर्ति होती है । लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि साधारण परिवर्तन के साथ तृतीय पंच वर्षीय योजना चलती रहेगी । राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च संरक्षक की हैसियत से इस सदन को विश्वास दिलाया है कि यह सदन साहस, बुद्धिमानी, धैर्य, सहिष्णता और कोआपरेशन के साथ उसे कार्यान्वित करेगा। यह सलाह समय के अनुसार है क्योंकि यह सदन जिम्मेदार है इस देश की नीतियों का निर्धारण करने के लिये और उसके नेतृत्व के लिये ।

चीन ने इस देश के साथ विश्वासघात किया, उसने मित्र की परिभाषा को बदला है । अचानक इस देश पर आक्रमण करके उसने अपने सैन्य बल का प्रदर्शन किया है । शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्या को सुलझा लेने में हमारा विश्वास है, लेकिन यदि कोई देश शांति नहीं चाहता और जिससे विश्व की शांति को खतरा है, जरूरी है कि उसे शांति का पाठ पढ़ाया जाय । जिस धृष्टता के साथ चीनियों ने हमारी भारत भूमि पर अपने अपवित्र चरणों को रक्खा है उससे देशवासियों को बड़ा रोष है । उस आक्रमण के कारण आज अपने देश में जिस तरह की राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है और जिस तरह की एकता हुई है, वह इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं थी । इसलिये जितने शीघ्र हो सके इन चीनियों को इस भारत भूमि से निकाल बाहर किया जाय । लेकिन यह सब काम होना चाहिये पूरी तैयारी के साथ । कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों को मान कर इस देश ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है । इससे तटस्थ और मित्र देशों को यह समझने का अवसर मिला है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान नहीं चाहता चीन सीमा समस्या को सुलझाना नहीं चाहता । उसकी नीति दूसरी है । उससे इस देश को छुटकारा मिले, इसके लिये जरूरी है कि अपने यहां पूरी सैनिक तैयारी हो । राष्ट्रपति को चाहिये था कि कुछ इस संकट के प्रति भी वे अपने अभिभाषण में अधिक उल्लेख करते । लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ही संकेत किया है । देश को विश्वास है अपने देश के सैनिकों के शौर्य और वीरता पर । वे स्वतंत्र भारत के सैनिक ही नहीं हैं बल्कि उस भारत माता के लाल हैं जिसके सिर पर चीनियों ने आघात करके उसकी मर्यादा को धक्का पहुंचाया है । आज देश के बच्चों का स्नेह उन्हें प्राप्त है तो युवकों का सहयोग और बुड्ढों का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त है । आज उन्हें अच्छे हथियार दिये जायें । अच्छे हथियार जिनका निर्माण चाहे देश में हो या जो हमारे मित्र देश हैं उन से मंगाये जायें, ताकि हमारे सैनिक समर्थ हों चीनियों को भारत भूमि की सीमा से बाहर कर देने में ।

इस संकट की घड़ी में उद्योगपतियों में अभी राष्ट्रीय भावना का बहुत कमी है । उन

[श्री दालकृष्ण सिंह]

की मिलों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूर उनसे आगे हैं। उनको प्रेरणा लेनी चाहिये अपने यहां के मजदूरों और श्रमिकों से। एक तरफ तो मजदूर इस देश का निर्माण करने के लिये, उत्पादन को बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प हैं और दूसरी तरफ मिल मालिक उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण बतलाऊं। हमारी कांस्टिटुयेन्सी में एक साहू केमिकल फैक्ट्री, वाराणसी में है। वहां पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस्पात को बनाने के लिये कारबन मोनो आक्साइड गैस तैयार होती है। वहां पर जो ब्वालयर हैं। एक ब्वायलर में काम होता है और दूसरे की मरम्मत होती है। सन् १९६० में जिस ब्वायलर की मरम्मत हो रही थी उसमें मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उसमें कारबन मोनो आक्साइड गस आ गई और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। सूचना मिलने पर जितने कर्मचारी वहां पर थे या जो दूसरे लोग ने वे उनको बचाते के लिये दौड़े। सब उसमें बेहोश होते गये। एक नौजवान इंजीनियर भी पड़ा कि किसी तरह से उन लोगों को बाहर निकाला जाय, वह भी ऊपर से गिरा और उसके सिर में चोट आई। वह खून से लतपत होकर बेहोश हो कर गिर पड़ा। जब किसी तरह से प्लान्ट को बन्द किया गया और आदमियों को उसमें से निकाला गया तो ३४ आदमी बेहोश थे। उस फैक्ट्री में एक भी ऐम्बुलेंस नहीं थी कि उन लोगों को ढोकर के अस्पताल ले जाया जाता। उस गैस के उपचार के लिए उस कारखानेमें कोई सामग्री नहीं है। ट्रकों में लाद कर उन्हें वाराणसी में कबीर चौरा अस्पताल ले जाया गया। उनमें से तीन आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ा। धन्यवाद है उस कबीर चौरा के डाक्टरों और वहां के कर्मचारियों को जिन्होंने तत्काल उपचार का प्रबन्ध किया और उनको होश में लाए। मुझे शिकादत मिली है कि उस फैक्ट्री म जो गैस को धोने के लिये पाइप होते हैं बहुत निकृष्ट कोटि के हैं और किसी वक्त भी इस किस्म की दुर्घटना हो सकती है। यह जो दुर्घटना हुई है वह बहुत बड़ी चीज है और स चीज को साबित करती है कि तनी बड़ी फैक्ट्री में जहां इतनी जहरीली गैस तयार होती है कोई ऐम्बुलेंस नहीं है और न वहां पर गैस के उपचार के लिये कोई अस्पताल या साधन है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संकट की घड़ी में जब मजदूर देश के निर्माण और औद्योगिक उत्पादन में लगा हुआ है तो उसको मिल मालिकों की इस प्रकार की असावधानी से बचाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इस फैक्ट्री की खुली जांच हो।

मुझे आप का अधिक समय नहीं लेना है। केवल दो तीन बातों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय हिन्दी के प्रश्न को लेकर जो घटना घटी उस के लिये मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं हिन्दी भाषी क्षेत्र का रहने वाला हूं, उस बनारस जिले का हूं जहां पर नागरी प्रचारिणी सभा है और जो हिन्दी के उत्थान के लिये बहुत बड़ा कार्य कर रही है, और पहले भी हिन्दी की तरक्की और उत्थान के लिये उस संस्था के सदस्यों ने अपना जीवन लगाया था। मुझे बड़ा दुःख है कि हिन्दी को लेकर एक अशोभनीय घटना घटी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी किसी एक पार्टी की भाषा नहीं है, वह समूचे देश की भाषा है, हिमालय पहाड़ से लेकर कन्या कुमारी अन्तरीप तक। हमारे देश निवासियों में हिन्दी पढ़ने की लगन है। हिन्दी के प्रति उन का प्रेम है। दक्षिण भारत के जिन वक्ताओं ने यहां पर कहा उन लोगों ने भी इस बात को बताया कि दक्षिण में लोग बड़ी तेजी के साथ हिन्दी सीख रहे हैं। हिन्दुस्तान की जितनी भाषायें हैं सब पूरे देश की भाषाएं हैं चाहे हिन्दी हो या दूसरी भाषा हों। हिन्दी राष्ट्रभाषा के

पद पर आसीन की गई है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा के प्रति कोई भी व्यक्ति कोई दूसरी बात नहीं सोच सकता। हिन्दी की आड़ में किसी पार्टी को अपने पोलिटिकल स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। हां यह अलग बात है कि हिन्दी के विकास के लिए यदि कहीं पर कोई रुकावट होती हो या कहीं सरकारी तौर तरीके के माध्यम में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसकी ओर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि कुछ टैक्निकल संस्थाओं जैसे बम्बई, खड़गर, कानपुर और मद्रास की टैक्निकल संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा मई के पहले सप्ताह में होगी। उसके लिए प्रश्नपत्र अंग्रेजी में होंगे और यह कहा गया है कि उसका उत्तर अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से दिया जाए। अंग्रेजी से हमारी कोई शिकायत नहीं है। अंग्रेजी से मुझे भी प्रेम है और जब तक हिन्दी में तमाम काम ठीक से और सब टैक्निकल टर्म्स ठीक नहीं हो जाते तब तक अंग्रेजी भी इन संस्थाओं में रहनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, जो राष्ट्रभाषा है और हमारे देश के कई प्रान्तों में साइंस की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम से होती है तो जब हिन्दी के माध्यम से साइंस की पढ़ाई होती है और यहां अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए अगर कहा जायेगा तो हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े हतोत्साहित होंगे और हिन्दी के विकास में इसका बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन टैकनिकल स्कूलों में जहां पर इन संस्थाओं में भरती होने के लिए परीक्षा होने वाली है वहां अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी उत्तर देने की अनुमति दी जाय क्योंकि हमारे देश में साइंस की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम से भी होती है।

मान्यवर, आज देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि खेती को प्रोत्साहन दिया जाय। ऐसी बंजर और ऊसर जमीनें जहां हैं उनको किसान तोड़ कर खेती के योग्य बनायें।

एक और अव्यवस्था हो रही है। हमारी कांस्टीटुएंसी में चकिया तहसील है। वह एक पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाके के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं समझता हूं कि वहां के निवासियों के पास खेती योग्य भूमि नहीं है और जीविका का अन्य कोई साधन नहीं है, तो उन्हें अगर कानन में परिवर्तन करने के बाद भी कोई सुविधा उनके जीविकोपार्जन और विकास के लिए अगर मिल सकती है तो देनी चाहिए। वहां पर महाराज के टाइम की जमीन माल विभाग के अधीन थी और बाकी फौरेस्ट की जमीन फौरेस्ट विभाग की देखरेख में थी। मैं निवेदन करूंगा कि विलयन के बाद भी जो जमीन महाराज के टाइम में माल विभाग के अधीन थी वह माल विभाग की रहे और जो जंगल विभाग की है वह जंगल विभाग की रहे।

अन्त में मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि अभी मैंने अखबारों में देखा है कि दो, एक सर्वोदयी नेता यह कहते हैं कि लद्दाख और नेफ़ा के ऐरिया में जहां चीनियों ने कब्जा कर लिया है, कुछ बिना हथियार के लोग वहां जाकर सत्याग्रह करें। अब मान्यवर, सत्याग्रह की बात तो मेरी समझ में आती नहीं, हां एक बात समझ में आती है कि यदि सर्वोदयी नेता और उनके कार्यकर्ता उस चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र में जाकर दो, दो, एक, एक की टोली बना कर गांवों में बसें और वहां के लोगों के मनोबल को ऊंचा करे और अपने रचनात्मक कार्य द्वारा उन गांवों का विकास कर तो देश का बड़ा कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री धुलेश्वर मीना (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आपको

[श्री घुलेश्वर मीना]

इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि अपनी मैडेन स्पीच देने के लिये आप ने मुझे समय दिया ।

राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण जो कि संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष दिया गया उस का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं । कुछ बातें जो उनके भाषण में मिलीं उनको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में देश को यह आवाहन किया कि उठो, जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाय । श्रीमन्, हमारा देश आजादी के पश्चात् शनैः शनैः प्रगति कर रहा था और अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास कर रहा था परन्तु इसी बीच हमारे पड़ौसी देश चीन ने भारत पर आक्रमण किया । वह आक्रमण केवल आक्रमण ही नहीं वरन् एक बर्बरतापूर्ण आक्रमण था । इस आक्रमण से देश को एक फायदा यह हुआ कि इतिहास ने एक नया सबक पेश किया और वह यह कि देश एकता के और संगठन के सूत्र में बंध गया और देश का प्रत्येक नागरिक यह महसूस करने लगा कि देश के प्रति उसका क्या कर्त्तव्य है । देशवासी यह समझने लगे कि मुल्क की आजादी को क़ायम रखने के लिये उन्हें क्या करना चाहिये । लोगों ने खुशी से धन दिया, खून दिया और जवानों को भी दिया । इसके साथ ही न केवल हमारे देश के ही अन्दर बल्कि विदेशी राष्ट्रों ने भी हमारा साथ दिया चाहे वह कम्युनिस्ट मुल्क हों या नौन कम्युनिस्ट मुल्क हों । हम यू० एस० ए० और यू० के० के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं साथ ही यू०एस०एस० आर० का भी कि ऐसे विपत्ति काल में वायदे के अनुसार उसे जो मिग विमान देने थे उसे देना स्वीकार किया ।

इस सदन के कुछ माननीय सदस्य देश के नेताओं से यह बारबार कहते हैं कि इमरजेंसी को खत्म कर देना चाहिये । इस समय सरकारी पार्टी ही इस इमरजेंसी का फ़ायदा उठा रही है । खास कर मैं प्रोफेसर रंगा के इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा कि समय आ गया है जब कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपातकालीन स्थिति का नाजायज फायदा सत्तारूढ़ पार्टी उठा रही है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस को यह कहना चाहता हूं कि क्या इस आपतकालीन स्थिति का फ़ायदा सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं उठा रही है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कि इमरजेंसी चल रही है, हमारी कांस्टीटुएंसी के अन्दर रक्षा कोष के लिये धन इकट्ठा किया जा रहा था तो दूसरी तरफ स्वतंत्र पार्टी की मीटिंग चलती थी और उन्होंने लोगों में यह गलत धारणा फैलाई कि देखिये आपने पहला गलत काम यह किया कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और वोट देने के साथ साथ आप से अब चंदा वसूल हो रहा है । "कल आप से ब्लड लिया जायगा । आज जवान लिये जाते हैं । कल अपनी जमीन को बेच कर आप को चन्दा देना पड़ेगा ।" इस तरह से जनता में ये ग़लत धारणायें फैलाई जाती हैं । इससे प्रकट होता है कि इमरजेंसी का नाजायज फ़ायदा ये उठा रहे हैं, न कि सत्तारूढ़ पार्टी । मुझे यह कहने के लिये माफ़ किया जाये कि सरकार की ढीली नीति भी इस के लिये जिम्मेदार है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस इमर्जेंसी पीरियड में इस प्रकार की पार्टियों और इस प्रकार के लोगों पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता है ।

यह दिखाई देता है कि दो तीन दिन के बाद फ़िनांस मिनिस्टर साहब जो बजट

पेश करेंगे, उस में कुछ इनडायरेक्ट टैक्सज लगेंगे । लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेज लगते हैं, वे केवल इनडायरेक्ट ही नहीं रहते हैं, बल्कि वे ग़रीब लोगों पर भी असर डालते हैं । मैं समझता हूं कि इस से बेहतर तो यह होगा कि सरकार के जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनको क्यों न बन्द कर दिया जाये । चाहे केन्द्र हो और चाहे स्टेट्स हों, मिनिस्टरों की इन लम्बी पल्टनों को क्यों न कम किया जाये ? जिन गवर्नमेंट बाडीज का महत्व नहीं है, उन को खत्म कर दिया जाये । उदाहरण के लिये हम ने देखा है कि पहले प्रशासन में कमिश्नरियां चलती थीं, लेकिन अब उन को खत्म करके कलेक्ट्रेट को उस के अधिकार दे दिये गये हैं । वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में डी० आई० जी० और एस० पी० की पावर्ज और क्वालिफ़िकेशन्ज बराबर होती हैं । तो क्यों न डी० आई० जी० को खत्म कर के एस० पी० को उस की पावर्ज दे कर पैसा बचाया जाये ?

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट का उल्लेख किया है । मैं मानता हूं कि १९६०–६१ और १९६१–६२ में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन वर्तमान साल में उत्पादन के कम होने की आशंका है । इस का कारण यह है कि गवर्नमेंट खेती के विकास के लिये जो प्रयत्न कर रही है और किसानों के हित के लिये जो कार्य कर रही है, उस का फ़ायदा पूर्ण रूप से किसानों के पास नहीं पहुंचता है । इस सम्बन्ध में जो सरकारी पैसा लगाया जाता है, वह किसानों तक नहीं पहुंच पाता है । इसी तरह जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, वे गांवों में जा कर किसानों को खेती करने के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं करते हैं । या तो वे लोग वास्तविक एक्सपर्ट्स नहीं हैं और या उन को समय नहीं मिलता है कि किसानों के पास जा कर सही ढंग से खेती करने की विधि उन को बतायें ।

जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बताया है, इस साल के अन्त तक सारे हिन्दुस्तान में कम से कम पांच करोड़ से भी अधिक विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटीज और कालेजिज़ से पढ़ कर निकलेंगे । यह बात सही है कि हम को शिक्षा के प्रसार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और अशिक्षा, इल्लीट्रेसी, को खत्म करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्रेड्एट्स हमारे कालेजिज़ और यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, उन को किसी भी प्रकार सर्विस नहीं मिल पाती है । इस लिये मेरा निवेदन है कि एड्केशन के ज्यादा विकास के साथ साथ एडकेशन सिस्टम में मूल रूप से परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है । आज विद्यार्थियों को एम० ए० या बी० ए० की डिग्री प्राप्त कर के भी सर्विस के लिये दर दर भटकना पड़ता है । इसलिये शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर के विद्यार्थिनों को टेक्निकल शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिये, ताकि वे एम० ए० या बी० ए० पास कर के अपने प्रोफ़ेशन में लग जायें और उन को अपनी जीविका चलाने के लिये साधन मिल सकें ।

अन्त में मैं आप का ध्यान गोल्ड कंट्रोल की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इस के परिणामस्वरूप बहुत बेरोज़गारी या एनएम्पलायमेंट फैलेंगी । जो लोग होशियार थे, वे तो पहले से ही सम्भल गए, लेकिन जो गरीब थे और जो इस बात को नहीं समझते थे, उन पर इस का असर पड़ेगा और वही बेकार हो जायेंगे । इस लिये इस में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया ।

Mr. Speaker: Dr. Colaco.

An Hon. Member: He has already spoken.

Mr. Speaker: Shri S. S. Deshmukh—absent. Shri Govindasamy Naidu—absent.

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : हम लोग हाजिर हैं ।

Mr. Speaker: I am calling the names of those hon. Members who are absent; they will lose their right. Shri Sumat Prasad, Shri Jialal Mandal Shri Shiv Charan Gupta—none of them is present.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ा और पाया कि वह अभिभाषण उत्साहवर्धक नहीं है । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में समाजवादी व्यवस्था का हवाला दिया है । परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि "समाजवादी व्यवस्था" शब्द का प्रयोग एक फ़ैशन सा बन गया है और वह जनता में एक तरह से बुद्धि विभ्रम पैदा करने और उस को बहलाने का एक हथियार बन गया है । जहां तक समाजवादी व्यवस्था के इस अर्थ का सम्बन्ध है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर किया जाये, उस दिशा में प्रगति नहीं के बराबर है । ज्यादा न कह कर मैं फ़ौज में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में जो बड़ा भारी फ़र्क़ है, उस को आप के सामने रखना चाहता हूं ।

आज सिपाही को ६० रुपये, जमादार को १४५ रुपये, लेफ्टिनेंट को ५४० रुपये, कैप्टन को ६६० रुपये, मेजर को १३०० रुपये, लेफ्टिनेंटकर्नल को १५०० रुपये, कर्नल को १७३० रुपये और ब्रिगेडियर को १६५० रुपये वेतन मिलता है । मैं केवल यहीं तक जाता हूं । एक सिपाही को ६० रुपये और ब्रिगेडियर को १६५० रुपये, अगर सरकारी कर्मचारियों में और खास तौर से सिपाही और अफ़सरों के वेतन में इतना जबर्दस्त फ़र्क हो, तो हम इस को कौन सा समाजवाद कहें ? यह समाजवाद नहीं है ।

जहां तक पंच-वर्षीय योजनाओं का प्रश्न है, राष्ट्रपति जी ने पंचवर्षीय योजनाओं का हवाला दिया और कहा कि वे सफल हुई हैं । मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी पंच-वर्षीय योजनायें सफल नहीं हुईं, क्योंकि अगर वे सफल हुई होतीं, तो हम चीनियों से न पिटते । किसी भी देश में औद्योगिक तरक्की, कलकारखाने और खेती का दुरुस्त होना लम्बी बांह के बराबर है और फ़ौजी ताकत मुट्ठी के । अगर लम्बी बांह मजबूत और ताकतवर है, तो मुट्ठी बांधने में देर नहीं लगेगी, बड़ी ही जल्दी मुट्ठी बंध जायगी और देश किसी भी संकट का सामना कर सकेगा । अगर हम उस दिशा में देखते हैं, तो सरकार स्वयं कहती है कि तैयारी कर के लड़ने में ज्यादा समय लगेगा । उस से पता चलता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कोई तरक्की नहीं हुई है और उन में भी हम को असफलता ही मिली है । अगर चीन और हिन्दुस्तान की औद्योगिक तरक्की के आंकड़ों को पेश किया जाये, तो पता चलता है कि जैसा कि माननीय सदस्य, श्री शिव नारायण, ने कहा है—हम कछुए की चाल से चल रहे हैं ।

इस सदन में कहा गया कि हमारी तटस्थता की नीति बहुत बढ़िया है । हम ने बार बार कहा है और आज फिर कहना चाहते हैं कि अगर तटस्थता की नीति हो, तो अच्छा है, लेकिन वह है नहीं । हमारी आजादी के बाद दो चीन बने, एक तो कम्यूनिस्ट चीन और दूसरा फ़ारमोसा का चीन । यद्यपि फ़ारमोसा के वर्तमान शासक, च्यांग काई शेक, ने हमारी आजादी की लड़ाई में हमारी मदद की थी, लेकिन हम उस एहसान को भूल गए और

बड़ी निर्लज्जता के साथ यह कोशिश करते रहे कि कम्यूनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्र-संघ में प्रवेश दिया जाये और हम ने फ़ारमोसा वाले चीन को मान्यता नहीं दी। लेकिन हम ने एक बार भी नहीं कहा है कि कम्यूनिस्ट चीन और फार्मूसा चीन जो हैं, इन दोनों को स्थान मिलना चाहिये। सदस्यता मिलनी चाहिये। अगर सरकार ने नहीं कहा है तो मैं चाहता हूं कि वह इस चीज़ को कहे।

17 hrs.

कम्यूनिस्टों ने तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम फलां देश से सहायता न लें क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जो तटस्थता की नीति है वह समाप्त हो जायगी। सरकारी पक्ष की ओर से भी यही दुहाई दी जाती है। मैं निवेदन करता हूं कि जो देश कोलम्बो में एकत्र हुये थे, उनमें से जो दो प्रमुख देश हैं, इंडोनेशिया और मिश्र उनकी ताकत कैसे बढ़ी चढ़ी है? दो हजार लड़ाकू वायुयान मिश्र के पास हैं, वे किसके दिये हुये हैं? रूस के ही तो वे दिये हुये हैं। छः अरब से अधिक की सैनिक सहायता इंडोनेशिया को रूस ही ने तो दी है। अगर ये देश रूसी सैनिक सहायता ले करके तटस्थ रह सकते हैं, बिन लगाव वाले रह सकते हैं, बिन लगाव वाले देश माने जा सकते हैं तो चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये, अपनी जमीन से उनको हटाने के लिये तथा अपनी भूमि को वापिस लेने के लिये और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये अगर हम किन्हीं देशों से सहायता लेते हैं तो इससे कैसे तटस्थता की हमारी नीति पर आघात पहुंचता है, कैसे तटस्थता हमारी टूट जायेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया है। वैसे तो श्रीमन्, हमारी तटस्थता है भी नहीं।

जब हम चीनी आक्रमण की ओर तथा अपनी असफलताओं की ओर देखते हैं तो उसके बहुत से कारण हैं और यह भाषा वाला कारण भी कम बड़ा कारण नहीं है। चीन के अफसर, चीन की जनता, चीन के जवान सब चीनी भाषा बोलते हैं और हमारे अफसर, हमारे जवान और हमारे देश की सरकार की भाषा जो है, वह अंग्रेजी है जिसका जनता से कोई संबंध नहीं है। हमारी फौज के अन्दर तरक्की किस आधार पर मिलती है? अफसर किस आधार पर बनाये जाते हैं? जो गिट-पिट बोलें, छुरी कांटे से खाना खाना जानते हों, मेज के तर्ज तरीके जानते हों, यह जानते हों की मेजों पर कैसे बैठा जाता है और क्लबों की जिन्दगी कैसे बिताई जाती है, उनको अफसर बनाया जाता है। यह है वह आधार जिस पर अफसरों की भरती की जाती है, जिस पर पलटनों में अफसर नियुक्त किये जाते हैं। कौन कितना बहादुर है, कौन कितनी कठिन जिन्दगी बिता सकता है, यह आधार आज नहीं है। जो आधार आपने बना रखे हैं, उनको आपको बदलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारी पलटनों में, हमारी मिलिटरी में अफसरों और सिपाहियों में कोई रिश्ता नहीं है। जब तक वह रिश्ता आप कायम नहीं करते हैं, जब तक पलटनों को और अपनी फौज को नये ढंग से आप संगठित नहीं करते हैं, तब तक चीन जैसे राक्षसी देश का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। हमने संकटकालीन स्थिति की घोषणा की और कहा कि हम चीन का मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कैसा मुकाबला कर रहे हैं? फूलों की प्रदर्शनियों का हम उद्घाटन कर रहे हैं। हमने संकटकालीन स्थिति के नाम पर उपचुनाव इत्यादि बन्द कर दिये थे, उनको दुबारा करा रहे हैं। सरकारी नौकरों की छुट्टियां इत्यादि बन्द कर दी थीं, वे फिर से जारी कर दी गई हैं। इन सब से यही पता चलता है कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। यह सब देख कर तो उस जानवर की कहानी की याद हो आती है जो रात में जब ठंडक पड़ी तो कहने लगा कि जैसे ही सुबह होगा, मकान तैयार करूंगा लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकला, धूप लगी, अपनी बात को भूल गया और फिर उसी तरह से

[श्री रामसेवक यादव]

रहने लग गया। इसी तरह से चीन ने दो डंडे मारे तो जरा हम में तेजी आई, उसके बाद जब हमको तैयारी का मौका मिला तो लड़ाई बन्द हो गई और हम चुपचाप बैठ गये। यह स्थिति हमारी है। मैं नहीं समझता हूं कि तैयारी की दिशा में हम कुछ कर रहे हैं। आज भी वही भ्रष्टाचार है, वही फिजूलखर्ची है, वही दावतनामे हैं। सभी चीजें एक एक करके पहले की ही तरह चल रही हैं। हां एक चीज है, कि एमरजेंसी में विरोधियों को कैसे दबाया जाये। हमारे किशन पटनायक जी की बात आप जानते ही हैं। जरा कुछ कहा नहीं कि अन्दर कर दिया गया। राष्ट्र प्रेम का सवाल उठाया जाता है। हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम में हम किसी से कम नहीं हैं। हां एक बात है। अगर जबर्दस्ती धन इकट्ठा किया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जायेगी। अगर यह कानून नहीं होता तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश से आवाज गूंजती इसके बारे में और अखबारों में भी यह चीज आती कि रक्षा कोष के लिये धन एकत्र करने में जबर्दस्ती हो रही है। आज लोग डरते हैं। अगर वे कुछ कहें तो वे जानते हैं कि उनको जेल का दरवाजा दिखा दिया जायेगा। लोगों को मारा पीटा जा रहा है। हमारे बाराबंकी जिले से एक रिट पेटीशन पहुंच गई है अदालत में। जबर्दस्ती जो हो रही है उसके खिलाफ दरख्वास्ते दी गई हैं और उनकी जांच हो रही है। गोंडा जिले में भी यह हो रहा है। चूंकि भारत सुरक्षा अधिनियम है, इस वास्ते ये सारी चीजें सामने नहीं आ रही हैं।

भाषा का सवाल भी उठाया जाता है। इस प्रश्न से मेरी पार्टी का बहुत गहरा संबंध है। १९ तारीख के बाद से और शायद १८ तारीख ही से सोशलिस्ट पार्टी के लोग इस सदन के और इस देश के दो सैकड़ा अंग्रेजी अभिमुख बड़े लोगों के जो ९८ सैकड़ा की छाती पर लदे हुये हैं, कोप का भाजन बने हैं। हमारी निन्दा की जा रही है, हमें अशिष्ट बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें कहा जाता है कि ये लोग हिन्दी लादना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा असत्य और गलतबयानी दूसरी नहीं हो सकती है। सोशलिस्ट पार्टी हिन्दी लादना नहीं चाहती है। वह तो जनभाषाओं को प्रतिष्ठित करना चाहती है। इन जनभाषाओं में तमिल, तेलेगू, मराठी, बंगला, उड़िया इत्यादि सभी भाषायें आ जाती हैं और साथ ही साथ हिन्दी भी आ जाती है। कहीं हमने नहीं कहा कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं। हम तो इस हद तक जाते हैं कि अंग्रेजी न रहे और इसके बजाय कोई भी भाषा हो जाये। संविधान में कहा गया है, ३४३ से लेकर ३५१ संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें साफ साफ यह कहा गया है कि सन् १९५० से लेकर १९६५ तक अंग्रेजी निरन्तर घटती जायेगी, उसकी जगह राष्ट्र भाषा हिन्दी लेती जायेगी और सन् १९६५ वह दिन होगा जब अंग्रेजी बिल्कुल मिट चुकी होगी। हम तो यह भी कहते हैं कि दक्षिण भारतीय या दूसरे जो हिन्दी नहीं समझते हैं, वे चाहें तो केन्द्र से अपना व्यवहार अंग्रेजी में कर सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि अपनी जनभाषाओं को वे अपने यहां प्रतिष्ठित करें। अगर उनको कोई भय है तो उनके लिये दस पन्द्रह बरस के लिये केन्द्र में नौकरियां, गजेटिड नौकरियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं या हमेशा के लिये सीटें सुरक्षित रखी जा सकती है या कोई अन्य सुझाव वे अगर पेश करना चाहते हैं तो सोशिलिस्ट पार्टी उसको भी मानने के लिये तैयार है लेकिन शर्त इतनी ही है कि अंग्रेजी जाये। अंग्रेजी क्यों जाये, इसका कारण यह है कि अंग्रेजी के रहते हमारे देश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता है, अच्छे टैक्नीशियंज पैदा नहीं हो सकते हैं, ज्यादा संख्या में डाक्टर्स पैदा नहीं हो सकते हैं। जब तक ये गिटपिट वाले दो सैकड़ा लोग हैं, देश की जनता को जनतंत्र में अपना हाथ बटाने के लिये तैयार

नहीं किया जा सकता है और न ही हम चीनियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमें कहा जाता है कि हम हिन्दी फैनेटिक हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम सेठ गोविन्द दास जी की तरह से हिन्दी लादने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी जाये, उसका स्थान कोई भी दूसरी भाषा ले। हम केवल हिन्दी के ही प्रेमी नहीं हैं, हम तो जितनी भी जन भाषायें हैं, उन सभी के प्रेमी हैं। हम अंग्रेजी के दुश्मन सिर्फ इसलिये हैं कि इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिये। अगर कोई अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। अंग्रेजी का प्रयोग अगर कोई अपने निजी काम के लिये करना चाहे तो वह वैसा कर सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग नहीं होना चाहिये। अंग्रेजी में राज काज नहीं चलना चाहिये। हम यहां अंग्रजों के ऊपर हुकूमत नहीं कर रहे हैं और न ही यहां की जन भाषा अंग्रेजी है। हमारे देश में दो फी सैकड़ा लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, बाकी ९८ फीसदी अंग्रजी नहीं जानते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं ने अपने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया था कि वह अंग्रेजी के सिवा किसी भी भाषा में अपना भाषण करें। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि १९५० में राष्ट्रपति जी ने यह परम्परा डाली थी कि राष्ट्र भाषा में वह अपना अभिभाषण पढ़ें। हमारे राष्ट्रपति जी दस बारह साल उप-राष्ट्रपति रहे और संविधान की धारा ३५१ के अनुसार शपथ लेते रहे जिसमें यह कहा गया है कि बराबर इस बात का प्रयास किया जायेगा कि राष्ट्र-भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक हो। लेकिन दुख है कि हमारे राष्ट्रपति जी ने शपथ लेने के बावजूद भी अभिभाषण को राष्ट्रभाषा में नहीं पढ़ा। मैंने तो उनसे यहां तक निवेदन किया था कि अगर वह राष्ट्रभाषा में नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी भी प्रादेशिक भाषा में पढ़ें और प्रादेशिक भाषा उनकी मातृभाषा ही हो सकती है। यहां तक भी जो मैंने उनसे कहा था, इसको भी उन्होंने अनसुना कर दिया। मैंने उनको हवाला दिया था कि प्रथम राष्ट्रपति ऐसा ही करते थे। मुझे उनका उत्तर मिला है, जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। यह इस प्रकार है :—

"Dear Shri Yadav,

Thank you for your letter of the 16th instant...."

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): Sir, on a point of order. Can we discuss letters that have been passed by the President to hon. Members?

Mr. Speaker: If the hon. Member has got it from the Rashtrapati, then probably he must have got permission from the Rashtrapati first. If he has not got that first, what can I do?

Shri B. S. Murthy: I would like to know whether permission has been obtained by him.

Mr. Speaker: I would not allow a discussion about it.

Shri Ram Sewak Yadav: I am simply reading.

Mr. Speaker: But it is only fair and ordinary courtesy that if one Member writes to the Rashtrapati or any other friend of his, unless permission is sought and is given from the other side also, the letters are not to be read. That is ordinary courtesy.

श्री रामसेवक यादव : मैं सिर्फ पढ़ ही दूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने लिखा है :—

"Thank you for you letter of the 16th. It is not correct to say that it has been the used practice to read the speech first in Hindi and then in English. The previous President in the early years used to read it in English first

[श्री रामसेवक यादव]

and in Hindi later. I remember that he sometimes read the speech in Hindi and then asked me to read it in English. It is entirely a matter of convenience.

I propose to read the speech first in English and then the Vice President will read it in Hindi.

With kind regards...."

अब फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा जिस में मैंने निवेदन किया कि आप मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ें । मुझे उसका यह उत्तर मिला :

"Thank you for you letter.

I find that you are right in saying that the previous President read his address first in Hindi and then in English. That the address should be read both in Hindi and English is a question of principle; the order in which it is done is a matter of convenience.

Courtesy and tolerance are essential for the satisfactory working of democratic institutions on which the unity of the country and our capacity to resist aggression depends.

With kind regards...."

यह बात सही है । उस दिन जिस बात के लिये हम लोगों की भर्त्सना की गई और कहा गया कि हम लोग बड़े डिसकर्टियस हैं और व्यवहार के अच्छे नहीं हैं, शिष्ट व्यवहार नहीं करते हैं, उन सभी लोगों के सामने, उन सभी सदस्यों के सामने हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे इस नाते "गुलों से खार अच्छे हैं, जो दामन थाम लेते हैं"। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने राष्ट्रपति जी का कोई अपमान या मानहानि नहीं की । मैंने संविधान की ओर उनका ध्यान खींचा उनसे निवेदन किया कि संविधान की [illegible] राओं के यह विपरीत है । उन्होंने मेरा निवेदन नहीं सुना । मेरे पास इसके सिवा चारा ही क्या था कि या तो मैं सदन त्याग देता या उन की बात सुनता । अगर हमारे मन की बात नहीं थी तो हमें अधिकार था कि हम सदन का त्याग कर दें । इसके इलावा मैंने कोई काम नहीं किया । लेकिन उसको लेकर इतनी बातें हुईं । मुझ दुःख है इस बात का । यह गांधी जी का देश है, हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्रीय हमारी लोक सभा है । लोक सभा में मातृ भाषा होनी चाहिय, लेकिन लोक सभा में हम विदेशी भाषा में कार्य चलाते हैं । गांधी जी कहा करते थे कि वह भारत का बाप जो अपने लड़कों को अंग्रेजी में तालीम देता है, मातृ भाषा में नहीं देता, वह उन बच्चों का दुश्मन है, अपना दुश्मन है और देश का दुश्मन है । आज उन भावनाओं से प्रेरित होकर ही मुझे कहना पड़ता है कि अभी हमारी आजादी के पन्द्रह ही साल हुये हैं, उससे भी कम महामना राष्ट्रपिता के हमारे बीच में रहते हुये हुये । उसके थोड़े ही समय बाद हर कोई आदमी इस देश में हल्ला मचाता है कि जनतंत्र जनभाषा के बिना निष्प्राण है । जब तक जन भाषा नहीं होगी तुम्हारी पंच साला योजनायें बेकार हैं, बिना उसके देश का निर्माण नहीं हो सकता है । लेकिन जब हम उन्हीं भावनाओं को अपने भारतवर्ष में लागू करते हैं तो उसके लिये हमें कोसा जाता है, हमें दंडित करने की व्यवस्था की जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब रूस और अमरीका बैठ रहे थे तो ख्रुश्चेव ने मेज पर जूता पटका था । जूता पटकने का मैं हामी नहीं हूं, मैं उसकी बुराई करता हूं लेकिन किसी माई के लाल के मुंह में जबान नहीं थी, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के मुंह में जबान नहीं थी कि इस कार्य को बयान द्वारा ही बुरा कहा जाता । लेकिन यदि यहां हम कहें कि भारत में जन भाषा को प्रतिष्ठित होना चाहिये, और अंग्रेजी, जो कि २ फी सदी लोगों को बोली है, उसको मिटना चाहिये, तो मुझे उसके लिये

सजा दी जाती है । किसी माननीय सदस्य को इस सदन की मर्यादा का, मान सम्मान का, ध्यान नहीं रहा । मैं राष्ट्रपति जी की बड़ी इज्जत करता हूं, राष्ट्रपति जी हैं, लोक सभा है, सारा देश है, मैं हूं, आप हैं, इस सारे हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको संविधान के अन्तर्गत अधिकार मिले हुये हैं न ? हमारे यहां संविधान सबसे बड़ा है । राष्ट्रपति को कहीं से यह अधिकार नहीं मिलता कि इस सदन में, जो कि स्वयं अपना मालिक है, अपने काम को चलाने के लिये इस सदन के किसी सदस्य को दंडित करने के लिये किसी को इशारा करें । अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन की कार्रवाई को जब पढ़ा तो उसमें पाया कि राष्ट्रपति जी ने आपको आदेश दिया कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाय, या कुछ कार्य किया जाय । यहां के किसी भी माननीय सदस्य.....

अध्यक्ष महोदय : यह बात गलत है । कार्रवाई का यह मतलब था कि वहां उनको बोलने दिया जाता ताकि जो कार्रवाई हो वह वहां ठीक से चल सके । कार्रवाई जो है उसके आप गलत माने न लगायें ।

श्री रामसेवक यादव : "टेक ऐक्शन" के मैं यही अर्थ लगाता हूं, **आर डू समथिंग** ।

अध्यक्ष महोदय : "टेक ऐक्शन" का मतलब था आप उनको बोलने देते । इसलिये मैं खड़ा हुआ कि आप से कहूं कि आप उनको बोलने दीजिये । अगर उस वक्त आप इजाजत न देते, तो मालूम नहीं उस वक्त मेरे मन में क्या खयाल आता ताकि वह स्पीच कर सकें ।

श्री रामसेवक यादव : खैर उस वक्त मैंने यह निवेदन किया कि जो वर्तमान स्थिति है, मेरे उस कर्म पर, जिसे मैं उचित समझता हूं क्योंकि मैंने संविधान की रक्षा की है, संविधान को तोड़ा नहीं है, संविधान की उन लोगों ने रक्षा नहीं की जिन्होंने बराबर १२ या १५ सालों से कस्में खाई हैं कि वे राष्ट्र भाषा का प्रचार करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे, लेकिन दस साल के बाद, पन्द्रह साल के बाद भी वह चीज नहीं हो सकी है,.....

Shri B. S. Murthy: It is a reflection on the President, because he says the President has violated the tradition.

अध्यक्ष महोदय : वह मेम्बर्स को कह रहे हैं, प्रेजिडेंट को नहीं ।

श्री राम सेवक यादव : मैं प्रेजिडेंट के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं आप से निवेदन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रेजिडेंट साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, इसलिये प्रेजिडेंट साहब का नाम न लिया जाय ।

श्री रामसेवक यादव : मैं तो सरकार से, सरकारी दलों से, अपने मित्र मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि उन्होंने पिछले पन्द्रह सालों से बराबर संविधान की शपथ लेने के बावजूद उसकी रक्षा नहीं की । मुझे तो यहां वह कहावत याद आती है कि "उल्टे चोर कोतवाल डांटे" । आज जिसने उसको उठाया आप उसे सजा दें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा के लिये जो वर्तमान सजा हमें दी जायगी उस में स्वीकार करूंगा, इस आशा के साथ कि शायद भविष्य में हमें इसका कुछ इनाम भी मिले ।

श्री ब० सू० मूर्ति : हम संविधान की रक्षा करने के लिये तैयार हैं, मगर आप प्रेजिडेंट साहब को बोलने देने के लिये तैयार नहीं हैं ।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Sir, the President's address reflects the people's opinion and, scholar and philosopher as he is, he has touched the vital points affecting the nation which is striving to grow in freedom. And, today the main question, as has been pointedly remarked in his speech, that over-rides all other issues which confront us, is the Chinese aggression. We have to be very careful in measuring the depth of the agony and the tragedy that has faced India

[Shri P. R. Chakraverti]

because of the unprovoked aggression from a nation in our neighbourhood which had been professing friendship so long.

Naturally, we have to consider when the question comes before us that India was unprepared, what does it indicate? It is the growth of the nation which has started rather from the scratch, trying to go up by steady processes to a higher level of standard of living, to take the 450 million people to a better form of life and to ensure them the minimum requisites of life which had been denied to them for years together. Our whole attempt was oriented in favour of a planned growth of the country and it was never defence oriented. It never accepted the principle of military aggression. If today China comes forth in blatant disregard of the principles of good faith of a nation, that has grown in the closest friendship with it for generations and generations, nay for centuries, united by the bonds of cultural affinity, the way of thinking, the attitude of life, developmental processes of mental outlook, and the entire history and tradition entwining the two nations, we have got to think and act in a different way. The country which is striving to improve the lot of its 450 million people was intent on keeping pace also with another country which has also 650 million people determined to grow. It is a form of appreciation of the joint efforts in developing the largest number of humanity in this part of the world. Therefore, today, if the challenge comes demanding a change in our attitude we have to accept it.

The President has touched very vitally the question that India will always endeavour to solve disputes peacefully. At the same time, he pointed out strongly, "whatever may happen, we cannot and will not submit to dictation backed by military force. Freedom and honour must be given the first place". There were some comments from the other side that these words used in his Address that, "we shall endeavour to solve disputes peacefully" will undermine the morale of the people. These are rather under-estimating the pointed remarks made. If you leave out the context and put a misconstrued meaning to it, it will not be doing justice to the Address.

When the question of people's responsibility comes, I am reminded of my own constituency, Dhanbad. There I was heartened to find that the wage-earner in the mining industry, whose daily earning is, but a meagre sum of Rs. 3·6 nP, voluntarily gave five days' salary in the month of November, two days' salary in December and two days' salary in January. It was I who told them that they need no longer give contributors to the National Defence Fund. Rather, they should endeavour to make some savings. I addressed some 125 meetings in my constituency telling them that their efforts in helping the country's defence by monetary contributions were undoubtedly praiseworthy, but there was more effective effort which they could do, and that was to accelerate the production apparatus which was set in motion. They could make themselves active in that sense and if anything was saved, that could be utilised in the purchase of Defence Deposit Certificates. This response is entirely voluntary. It is practically non-official organisation which is running the show and the officials are there only to give technical assistance. The response has its own intensity, and the tempo can be kept in its positive form only by active participation in the efforts undertaken. It is obvious that India is facing the challenge and continues to fight on her frontiers as well as in the farms, factories and the mines. That is my conception of the war efforts and there people have not been found lacking.

Maybe, there are sections of people, the privileged people, who have got better wealth and other forms of

prosperity, who might not be so active. That is the history of a nation's growth. Everywhere, the social uprising is marked by the tempo that is created, bringing out the best of the people at large and not of the select privileged few. If today, some persons drawing the highest privy purses or similar income per year, find themselves not in a position to offer their share, that does not undermine the morale of the people, who have voluntarily come forward to give their best in the productive efforts and also in the preparation for the war. There is no question of undermining the morale, as has been tried to be pointed out here.

Now, my hon. friends on the other side, specially my friend and my ex-colleague, Shri Chatterjee, have raised the question of the Defence of India Rules. Shri Gopalan, who is not here now, also raised the same question. I would analyse the statement which has been supplied to us by the Ministry on the question of detention consequent on the Chinese aggression. I come from a town where 2,500 to 3,500 people were always in detention from the year 1907 to 1947. So, I am very happy to see from the list supplied to us that the number of detenues is only 758. For Delhi one will find that nine were arrested and nine were released. Similarly, there have been releases in other States also. And I shall be happy to share the feelings of Shri Gopalan from another point of view in case the number is reduced to nil. I can tell the country, tell the people at large, that here is a country which has stood together, 450 million people have stood together, for a definite purpose, integrated in their mental outlook and that not a single man is kept in detention for his unfortunate way of behaviour. I would be very happy to say so when that situation comes. Even today the reviews and releases are bringing down the figure, and 758 for the whole of India is not a very high figure.

We are surprised to hear that the Defence of India Rules will be applied to eliminate the opposition. There is no question of eliminating the opposition. It is a question of bringing forth the national strength and potentialities to the fore to face this terrible and grim task before us, the dismal crisis that is confronting us. We cannot overlook it; we have to face this aggression. Naturally, it is up to everybody to say that he is going to contribute positively to face this aggression with all his potential resources. So, there is no question of the Defence of India Rules eliminating the opposition.

The question of non-alignment has sometimes been commented upon. This is a very crucial point. When people find themselves faced today with an aggression from a neighbouring country with whom we have been united by bonds of culture and amity for thousands of years, the question of non-alignment does not stand in the way of self-assertion for upkeeping the dignity and honour of our own country. To say that non-alignment is standing in the way of aggression on us by another country being vacated is not quite correct. Here it is a question of aligning with the forces of progress, forces of development. Anybody, who is in agreement with me in my democratic process of life, in my attempts to bring about a socialistic pattern of society, is aligned with me.

It is not a question of power blocs, military alliances or thinking in terms of aggression as against others. India has always tried to uphold its own philosophy so much so, that the Communists are coming and saying in unreserved terms that they condemn the aggressive activities of China, a great Communist country, with 650 million of people. What does it indicate? He thereby attunes himself to the music of India's culture and ceases to be a man prejudiced by the aggressive international Communistic outlook. He is an Indian. So, India's philosophy first of all conditions his outlook and he comes forward and rightly challenges this naked aggression on the part of China.

[Shri P. R. Chakraverti]

The question of non-alignment has somehow been tried to be misinterpreted. There is no question of aligning with other powers of this Bloc or that Bloc. It is a question of endeavouring as to how far we can produce that much of energy, we can bring about the best in the people and then try to face all forms of aggression that stand in the way of our progress towards the socialistic pattern of society which we have been trying to build up. These factors should now be made very clear.

Only today I was reading a nice comment by the *Economist* of London. It says:—

> "Democratic India has been made vulnerable in defence because India put economic growth before defence. It is impossible to say as yet whether the very violence of the crisis will create a new momentum by breaking through some form of the bottlenecks."

This is the question which is posed by a foreign critical observer, who tries to understand the difficulties which India had to experience, in the attempt to grow India will have to remove all the bottlenecks that stood in the way of her progress and, in that attempt for our growth, nobody will minimise the difficulties that face us. But at the same time, it evokes a determined will on the part of the people that takes us to the sure path of our progress and development. The people have not been found lacking. If anybody is found lacking, it is a very minor microscopic section of the people, who have been enjoying themselves at the cost of others and who have been basking in the sunshine of any regime, whether it is the British or Muslim League or any other regime. We have to be cautious on that score and see whether we try to understand deeply the problems that confront us and thereby find out the solution with a determined will. It is upto us to see whether, in this present crisis, we shall be in a position to remove all the bottlenecks—the impediments, as has been aptly pointed out by the London *Economist*. It brings the question of real integration, that is, integration in our outlook, in our determination, and in our will to overcome all attempts at subversion and for nullifying the progress which we have been working for the last 15 years. We have not reached the consummation. We have as yet to go a long way. So, today, if we are attempting to accelerate the progress, it is only possible with the people's concerted action that has been evident from the response which had been forthcoming in abundance from them.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, कई दिन से मैं बहस सुन रहा हूं और १०० फीसदी कांग्रेसियों के मुंह से जो बातें मैं ने सुनी हैं, उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सब लोगों ने यह कहा है कि अपोजीशन की तरफ से, जो काम और अच्छे काम कांग्रेसी सरकार ने किये हैं, उनकी तारीफ नहीं की गई। हर एक ने यह कहा है कि जो काम ऐडमाइरेबुल है, प्रशंसनीय है उन के लिए हमारा गुणगान नहीं किया गया है। इस के लिए मेरी अर्ज यह है कि अपोजीशन का काम क्रिटिसाइज करना है, गुणगान करना नहीं है। अगर सरकार ने १० मील लम्बी सड़क बनाई है तो उस की तारीफ करना हमारा काम नहीं है। अलबत्ता जो बीच में एक मील सड़क टूटी हुई है उसको क्रिटिसाइज करना हमारा काम है। डाक्टर का काम औपरेशन करने का है। जहां जख्म पक गया है वहां नश्तर लगा कर चीरने का है। जहां से जिस्म तंदरुस्त हैं, वहां पर मालिश करने का काम किसी खिदमतगार का काम है, डाक्टर का काम नहीं है। हम लोग यहां पर क्रिटिसाइज करने के लिये आए हैं। बार-बार यह कहा जाता है कि हमारी

तरफ से कोई आल्टरनेटिव, कोई आल्टरनेट सजेस्टियन या कोई कन्क्रीट सजेस्टियन नहीं दिया गया है। इस के लिए एक ही सजेस्टियन है। जिस तरह से रुहानियत के बिना खुदा नहीं मिलता है, आध्यात्मिकता के बगैर परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, जिस तरह से भजन के बगैर बन्दगी नहीं होती है, ठीक उसी तरह युद्ध के बिना देश की रक्षा नहीं हो सकती है। इस समय कोई आल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। इस समय केवल एक ही रास्ता है—युद्ध का। अगर हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो देश की इज्जत की रक्षा नहीं हो सकती है। आज देश को युद्ध के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज कोलम्बो-प्रस्तावों और आरबिट्रेशन वगैरह की जो बातें बनाई जाती हैं, वे सिर्फ इसलिए कही जाती हैं कि हमारे हलवे-मांडे और रंगीनियों में कमी न आए। उस में देश की रक्षा का कोई सवाल नहीं है। आज हमारा देश उस परिस्थिति में से गुजर रहा है, आज हमारे देश के सामने वह नजारा है, आज हम उस काल में से गुजर रहे ह, जिस के बारे में हिटलर ने अपनी आटो-बाइग्राफी में लिखा है :

"Then the sword will be the plough and the tears of war will produce the daily bread for generations to come."

आज वह वक्त आ गया है कि हिन्दुस्तान के बच्चे बच्चे को फौज के लिए तैयार किया जाये। काग्रेस सरकार नाकाबिल साबित हुई है। वह सिर्फ बातों से इस मसले को हल करना चाहती है। देश में कोई ऐसा एटमास्फीयर तैयार नहीं किया गया है, जिस से देश युद्ध के लिए तैयार हो सके, लड़ाई के लिए तैयार हो सके।

आज ऐसी बाते कही जाती हैं कि लड़ाई लम्बी चलेगी। लम्बी लड़ाई क्यों चलेगी ? क्या हिन्दुस्तान में ४४ करोड़ गधे रहते हैं, क्या हिन्दुस्तान में ४४ करोड़ नपुंसक रहते हैं, क्या हिन्दुस्तान में ४४ करोड़ कुत्ते रहते हैं कि लम्बी लड़ाई चलेगी ? यह महाराणा प्रताप और गुरु गोविन्दसिंह की औलाद है। यह भगवान् कृष्ण और अकबर की औलाद है। यह भगवान् राम की औलाद है। लम्बी लड़ाई का कुछ मतलब नहीं है। लड़ाई की साइकालोजी और स्ट्रैटेजी यह है : "आई केम, आई सा, आई कांक्रड"।

जब सरकारी बैंचिज की तरफ से कहा जाता है कि लड़ाई लम्बी चलेगी, तो ब्लैकमार्केटियर यह सोच लेता है कि बहती गंगा है, हाथ धो लो, जितना ब्लैक-मार्केटिंग कर सकते हो, उतना कर लो, मोटर का जो पुर्जा एक रुपए में बिकता था, उस को १५० रुपये में बेच लो। ऐसी बात कह कर ब्लैक-मार्केटियर्ज को बढ़ावा दिया जाता है।

इन पंद्रह सालों में देश को यह तालीम और ट्रेनिंग दी गई है कि अगर एक हाइड्रोजन बम गिर गया, तो करोड़ों आदमी नष्ट हो जायंगे और अगर एक एटामिक बम गिर गया, तो पचास लाख आदमी नष्ट हो जायेंगे। यह ट्रेनिंग और यह शिक्षा गलत थी। हमें तो इस ट्रेनिंग की जरूरत थी कि "सम्भावितस्यचाकीर्ति : मरणा-वतिरिच्यते"। हमें उस शिक्षा की जरूरत थी, जिस में यह पढ़ाया जाता कि जिल्लत की जिन्दगी से मौत अच्छी होती है, अपमान के जीवन से मृत्यु बेहतर होती है। वह ट्रेनिंग हमें नहीं दी गई। हमें डर दिखाया गया और जो आज भी डर दिखाते हैं, जो आज भी इन्फीरियारिटी कम्पलेक्स की बात कहते हैं, जो आज भी हीनता की बात कहते हैं, वे देश की सेवा नहीं कर रहे हैं।

इस माननीय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने २२ जनवरी को हमारे प्रधान

[श्री यशपाल सिंह]

मंत्री ने क्वेसचन हवर में यह ऐलान किया कि वाकई हमारे पास इतनी राइफलें नहीं हैं, जिन से हम एन० सी० सी० की ट्रेनिंग कालेजों को दे सकें । जिस देश के पास स्कूलों और कालेजों में ट्रेनिंग दे ने के लिए राइफलें नहीं हैं, क्या वह देश लद्दाख के मोर्चे पर राइफलें भेज सकता है ? अगर सरकार की कोई कमज़ोरी, वीकनेस या कमी है, अगर वह कहीं लूज़ करती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस का ढंढोरा पीटा जाए, क्योंकि ढंढोरा पीटने से दुश्मन और ज्यादा हम पर हावी होता है ।

सरकार की ओर से यह कहा गया है कि हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे । बिल्कुल ठीक है । जो लड़ाई के लिए तैयार होता है, उस पर कोई हमला नहीं होता है । जो लड़ाई के लिए तैयार हो, क्या उस पर हमला कर के कोई अपना सिर तुड़वायेगा या अपनी मौत बुलवायेगा ? यह सरकार तो दुश्मन को आह्वान देती है, दावत देती है और उसको यह कहती है कि "वाकई हम लोग लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, आओ, तुम्हारे लिए मैदान खाली है ।"

आज दो ही रास्ते हैं । चाहे कोलम्बो प्रस्ताव हों, चाहे नेगोशिएशंज हों, चाहे ८ सितम्बर की स्थिति की बात हो, यह ज़िल्लत, शिकस्त और पराजय का रास्ता है । देश की इज्जत की रक्षा केवल दूसरे ही रास्ते से हो सकती है और वह रास्ता है युद्ध का । कांग्रेस सरकार को इस देश ने वह सम्मान, इज्जत और आनर और एज़ाज दिया, जो किसी शहन्शाह को भी नहीं मिल सका । और कांग्रेस सरकार ने उस सम्मान के एवज इस देश के ४४ करोड़ इंसानों को पराजय का कलंक दिया, शिकस्त का दाग़ दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि चाइना ने तो सीज-फ़ायर किया है, हम ने क्या किया है? अगर हम में मिलिटरी स्ट्रेंथ और शक्ति होती, अगर हम में बल-वीर्य होता, तो क्या हम कासा-ए-गदाई ले कर, भिक्षा-पात्र ले कर, चाइना के सामने खड़े होते कि हमारे कैदी, हमारे ज़ख्मी और बीमार और हमारी लाशें वापस दे दो ? अगर हम में क्षात्र-तेज होता, अगर हमारी बांहों में बल होता, अगर हम में मिलिटरी स्ट्रेंथ होती, अगर हम में बल-वीर्य होता, तो हम एक कैदी के एवज एक लाख कैदी बनाते, एक ज़ख्मी के एवज एक लाख को ज़ख्मी करते, एक लाश के एवज एक लाख लाशें बिछा देते । यह हमारी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी को यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है । आज ४४ करोड़ इंसानों की आंखें खुशली हुई हैं । आज ४४ करोड़ इंसान इस ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ।

अगर यह सरकार इस देश की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती है, तो उस की तारीफ़ इसी में है कि वह पद छोड़ दे । बार-बार कहा जाता है और अभी माननीय सदस्य, श्री शिव नारायण, ने कहा कि अगर मेरे हाथ में डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज का संचालन होता, तो मैं एक-एक स्वतंत्र पार्टी के सदस्य और जनसंघी को जेल में डाल कर छोड़ता । ये हम को जेल से डराते हैं ? हम जेल में पैदा हुए । मैं तेरह साल की उम्र में काल-कोठरी में रहा हूं । हम ने आठ सौ साल तक दरख्तों की छालें चबा कर इस देश की रक्षा की है । हम ने आठ सौ साल तक खून के दरयाओं में नहा कर इस देश की रक्षा की है । हम ने कंकड़ों और पत्थरों के ढेर पर सो कर इस देश की रक्षा की है । इस के बावजूद आज हम को डराया जाता है कि हम को जेल में डाल दिया जायेगा । ये खिलौने हैं, जो हमें जेलों से डराते हैं । हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं । हम कहते हैं कि हम ने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, खून दिया है, मुसीबतें उठाई हैं । मैं पंडित चन्द्रशेखर शर्मा "आज़ाद" के साथ जंगलों में मारा-मारा फिरा । मैं भाई भगतसिंह के साथ फांसी की कोठरी में रहा । हम ने इस देश के लिए

मुसीबतें उठाई हैं। हमें इस देश का दर्द है

"जिसे है फ़िक्र मरहम की, उसे दुश्मन समझते हैं,

इलाही ख़ैर हो, यह जख्म अच्छा हो
नहीं सकता"।

हम इस सरकार के ख़ैर-ख्वाह हैं और हम उस को नेक रास्ता दिखाना चाहते हैं। भारतमाता गवर्नमेंट से बड़ी है और हमारे देश की इज्जत सरकार से बड़ी है। अगर यह सरकार देश की रक्षा नहीं कर सकती है, तो वह हट जाए। यह तो एक थोथी दलील है कि मैजारिटी बना लो और हमें हटा दो। मैं साफ कहना चाहता हूं कि उस की महिमा इस में है कि वह अपने पद छोड़ दे। वह ना-एहल है। इस सरकार की कैबिनेट के एक मेम्बर ने ही संसार के सामने एक आदर्श पेश किया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री की कोई खता नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे जमाने में ज्यादा एक्सिडेंट्स हुए हैं, इसलिए मैं मुस्ताफी होता हूं। यह सरकार उस आदर्श के अनुसार चले और चूंकि वह अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकी है, इसलिए ईमानदारी और देशभक्ति का तकाजा यह है कि वह अपने पद छोड़ दे। यह दलील ठीक नहीं है कि मैजोरिटी बना कर हम को हटा दो। जिस दिन हमारी मैजारिटी बनेगी, उस दिन बाकायदा जवाब-तलब किया जायगा कि किस से पूछ कर देश के नौजवानों को भट्टी में झोंक दिया गया था, जब कोई शक्ति नहीं थी। उस दिन पूछा जायगा कि किस से पूछ कर आठ साल तक हमारी फौजों को यह हक्म दिया गया था कि जब चीनी गोली चलायें, तो उस के बाद ही गोली चलाओ। दुश्मन हमारे घर में घुसा बैठा है, दुश्मन हमारे इस पालियामेंट हाउस में घुसा बैठा है, लेकिन में अपने पहरेदारों को यह हुक्म दे दूं कि जब दुश्मन गोली चलाए, उसके बाद गोली चलाओ!

जिन के मरे नहीं हैं, वे कहते हैं कि बातों से मसला हल करो। जिन का खून नहीं बहा है, वे कहते हैं कि कोलम्बो-प्रस्तावों से मसला हल करो। हमारे मरे हैं। मेरा सगा भतीजा मारा गया। मेरे बेटे, विक्रमसिंह, के चीनियों ने कुल्हाड़ियों से तीन टुकड़े कर के उस का खून पीया। मैंने वहां जा कर देखा। मैंने वहां का मुआयना किया। खून पीते वक्त उन्होंने यह कहा कि वैसे तो हर एक हिन्दुस्तानी बदमाश है, लेकिन तीन का खून हमें मीठा लगता है—सिख, जाट और राजपूत, इन तीनों का खून हम को मीठा लगता है। हमारे खून को चीनी की तरह से मीठा समझ कर पीया गया है। क्या हम उनको माफ़ कर देंगे? आज देश की आत्मा और देश की खुददारी जाग चुकी है। आज देश में आत्म-सम्मान है। जिन देशों में आत्म-सम्मान है, वे कभी कोलम्बो-प्रस्तावों की बात नहीं कर सकते।

आज चाइना ने कह दिया है कि कोलम्बो प्रस्तावों का यह टोकरा सड़ा हुआ है, इस में कीड़े पड़ चुके हैं, यह बेकार हो चुका है और अगर इस को चीन की सरज़मीन पर रखा जायगा, तो चीन में एक बीमारी, एक कानटेजियस डिज़ीज़, एक एपिडेमिक फैल जायगा। चीन ने उस टोकरे को लात मार दी है। हमारा भी यह फर्ज है, हमारी देशभक्ति और सिन्सेरिटी का भी यह तकाजा है कि हम लोग भी उसे छोड़ दें और अपने देश को, अपनी फौज को लड़ाई के लिये तैयार करें।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैंने सुना और फिर कई दफ़ा उस को पढ़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि देश में क्या निर्माण हुआ है। तीन मुख्य निर्माण-कार्य ये हैं, चरित्र का निर्माण, अपनी आवश्यकता की खुराक का देश में ही पैदा होना और फ़ौजी ताकत पैदा करना।

[श्री यशपाल सिंह]

इन तीनों के मामले में हम निहत्थे और बेकार खड़े हैं । हम दूसरे मुल्कों से २६ अरब रुपये का गेहूं ले कर खा चुके हैं । हम आज भी दूसरे मुल्कों के सामने हाथ पसारते हैं । आज भी हम दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं ।

जहां तक चरित्र का प्रश्न है, आज हालत यह है कि इस कैपिटल में एक एक दिन में सैंतीस सैंतीस अग़वा होते हैं । माननीय मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, सच बोलने वाला हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में यह माना है कि वाकई जरायम में इज़ाफ़ा हुआ है, वाकई अपराध दिन रात बढ़ते जा रहे हैं । आज दिल्ली की सड़कों और चौराहों पर वे नग्न चित्र लगे हुए हैं, जिन के खिलाफ महात्मा गांधी ने ज़िन्दगी भर जद्दो-जहद की थी । आज दिल्ली की सड़कों और चौराहों पर यह लिखा हुआ है, "४४ करोड़ लोगों के दिलों पर शासन करने वाली सुरैया," "४४ करोड़ लोगों के दिलों पर शासन करने वाली मधुबाला ।"

इसका मतलब यह है कि ४४ करोड़जानी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं । कहां हैं हमारी हाई कोर्टस, कहां है हमारी सुप्रीम कोर्ट, कहां है हमारा मौरल, कहां है हमारा डिसिप्लिन, कहां है हमारी सरकार ? जिन लोगों ने यह लिखा कि ४४ करोड़ लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाली सुरैया, उनके हाथ कटवा दिये जाने..

अध्यक्ष महोदय : ४४ करोड़ के अलावा भी कुछ आदमी हैं ।

श्री यशपाल सिंह : वाकई में और भी ज्यादा हैं । अगर देश का चरित्र होता तो इस बात की इजाजत न दी जाती कि कोई कहीं भी किसी तरह से भी लाउड स्पीकर लगा करके, माइक के ऊपर खड़ा हो करके..

श्री रा० श० पाण्डेय (गुना) : प्वाइंट आफ आर्डर, सर.....

श्री यशपाल सिंह : मुझे बड़ी कोशिशों के बाद थोड़ा सा समय मिला है और मुझे अपनी स्पीच जारी रखने दीजिये । जब आप बोलें तो अपनी बात कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं, वह प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह निवेदन...

अध्यक्ष महोदय : उनका प्वाइंट आफ आर्डर तो सुन लीजिये ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मधुबाला और सुरैया, कलाकार हैं और चित्रों में अभिनय करती हैं । उनके नाम के साथ व्यभिचार का सम्बन्ध जोड़ा जाए, यह प्रतिष्ठा के अनुकूल बात मालूम नहीं देती है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहने का मतलब यह है कि जो इश्तहार लगते हैं उनमें लिखा रहता है कि ४४ करोड़ पर वे राज करती हैं । उन पर वे राज नहीं करती हैं । वे कहते हैं कि हम कहां से शामिल हो गए ? लेकिन आबादी ४४ करोड़ से ज्यादा है और वे उस में आ जाते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : हम उनमें शामिल नहीं हैं .....

अध्यक्ष महोदय : आप उन में आ जायेंगे, जो बाकी लोग हैं ।

श्री यशपाल सिंह : देश का चरित्र सब से पहली चीज है। मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर देश का चरित्र होता तो देश में कानून बनाये जाते। कोई कहीं सिग्रेट का धुंआ फेंक दे, कोई कहीं बैठ कर शराब पीना शुरू कर दे, कोई कहीं बदबू फैलाता रहे, कोई कहीं माइक लगा कर कुलटाओं के गाने गाना शुरू कर दे, चाहे बच्चों के इम्तहान हो रहे हों, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा हो या पूजा पाठ कर रहा हो और चाहे डाक्टर आपरेशन कर रहा हो, कोई रोक-टोक नहीं है। बेवाओं के राज में भी थोड़ी बहुत रोक-टोक हो जाती है। विधवा रूल में भी कुछ मारेल रेस्ट्रिक्शंज होती हैं। विडो राज में भी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं मारल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कांग्रेसी राज में कोई मारल स्टैंडर्ड नहीं है। अगर देश को तैयार करना है, तो शराब को बन्द किया जाए, अगर देश को तैयार करना है तो सिनेमा घरों के अन्दर जो बुरे बुरे गाने गाये जाते हैं, इनको बन्द किया जाए और सिनेमा घरों को बन्द करके इन जगहों पर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल खोले जायें और लोगों को फौजी तालीम दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है, तो आप देश की रक्षा कर सकते हैं, वर्ना नहीं कर सकते हैं।

बार-बार यह कहा जाता है कि स्वतंत्र पार्टी जमींदारों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, राजा महाराजाओं की पार्टी है। मैं कहता हूं कि एक दो राजा महाराजा-राजाओं के आने से हमारी पार्टी अमीरों की हो गई, लेकिन कांग्रेस में पांच दर्जन राजे महाराजे हैं, क्या वह राजा महाराजाओं या अमीरों की पार्टी नहीं हुई ? हमारी पार्टी में तो दो राजे महाराजे हैं लेकिन कांग्रेस में पूरे पांच दर्जन हैं। किस तरह से हमारी पार्टी अमीरों की हो गई, समझ में नहीं आता है। कहा जाता है कि हम जमींदार हैं। हम जमींदार जब थे तब थे, आज नहीं हैं, आज तो हम काश्कार हैं। उधर से बार-बार मेरी पगड़ी का ज़िक्र किया जाता है। मैं साफ़ कहता हूं कि इस पगड़ी के साथ हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। यह जमींदारों की पगड़ी नहीं है, यह इंडिया कल्चर की पगड़ी है। मुझे इंडियन की वह बात याद आती है कि जब महाराणा प्रताप का भाट अकबर के दरबार में गया था और जब सलामी दी पगड़ी उतार कर सलामी दी तो इस पर राजा अकबर ने कहा कि यह दरबार की तौहीन है तो उसने जवाब दिया कि सिर मेरा आपके कदमों में झुक सकता है लेकिन पगड़ी महाराणा प्रताप की है, यह किसी के कदमों में नहीं झुकती है, सिर्फ भगवान के सामने ही झुकती है। हम लोगों को जमींदार कह कर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं आज भी डंके की चोट कहता हूं कि हम में ऐसे आदमी हैं जिन्होंने बीस-बीस हजार एकड़ जमीन हरिजनों और मजदूरों में तक्सीम की है। आज भी हम में ऐसे लोग हैं जो तन मन धन से हरिजनों और मजदूरों की सेवा में लगे हुए हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि हम देश को एक सूत्र में पिरोयें। पार्टीबाजी की बिना पर हमको बार-बार कहा जाता है कि कोई चर्चिल नहीं है तो चैम्बरलेन राज कर रहा है। यह सरकार की खता है। सरकार ने किसी पार्टी को पनपने नहीं दिया है, सरकार ने अपोजीशन को पनपने नहीं दिया है। दूसरे मुल्कों में अपोजीशन लीडर की वही इज्जत होती है जो प्राइममिनिस्टर की होती है। लेकिन हमारे देश की यह हालत है जो कि आज भी मुखालिफ़ पार्टी के लोगों के लैक्चरों को सी० आई० डी० वाले नोट करते हैं। हम डरते नहीं हैं सी० आई० डी० से। लेकिन नाक इनकी कटती है, शर्म हमको आती है। हजू होती है

[श्री यशपाल सिंह]

जनतंत्र की, लज्जा के मारे हम लोग मरते हैं। ४४ करोड़ इंसानों को एक सूत्र में पिरोकर हम हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा कर सकते हैं। न कोलम्बो प्रस्तावों की तरफ़ देख कर और नही मिलिटरी एंड की तरफ़ देख कर हम हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकते हैं। हम अमरीका के भिकारी नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। मैं नान-एलाइनमेंट को मानता हूं। लेकिन नान-एलाइनमेंट पहाड़ की होती है, चट्टान की होती है, तिनके की कोई नान-एलाइनमेंट नहीं होती है। आप फ़ौजी ताकत पैदा करें। इसके बग़ैर कुछ नहीं हो सकता है। ४४ करोड़ इंसानों को एक सूत्र में पिरो कर तथा फ़ौजी ताकत पैदा करके ही हम देश की रक्षा कर सकते हैं। हम सब को सिपाही बन कर देश की रक्षा करनी है और तभी देश की रक्षा हो सकती है।

मैं मजबूर हूं कि मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद नहीं दे सकता हूं।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तानपर): अध्यक्ष महोदय, आज कई रोज से राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर वाद-विवाद यहां पर चल रहा है। जो अभिभाषण माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उन्हें उसके लिये मैं धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विरोधी पार्टियों की ओर से कई आक्षेप सरकार की नीतियों पर, सरकार की कारगुजारियों पर किए गए हैं। यह आक्षेप भी किया गया है कि सरकार सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है, कम्प्लेसेंट है और उसकी नीतियां ठीक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि एमरजेंसी में जो बातें होनी चाहियें वे कहीं पर दिखाई नहीं पड़तीं हैं और सभी लोग ढीले ढाले हैं, सोये हुए हैं और कोई कार्य इस सम्बन्ध में नहीं हो रहा है। माननीय सदन की यहां पर बैठक बुलाई गयी है और माननीय राष्ट्रपति जी ने कई बातों की ओर संकेत किया है जिस में युद्ध के बारे में भी काफी जिक्र है। उन्होंने यह भी कहा है कि समारे राष्ट्र में जो कुछ भी सत्कार्य होने हैं वे इसी दृष्टिकोण से होने हैं कि युद्ध की तैयारी हम करें और हमें अपने शत्रुओं को अपनी भूमि से हटाना है। ये सभी चीजें होते हुए भी मैं नहीं समझता हूं कि अगर एमरजेंसी पीरियड है, अगर यहां पर संकट कालीन परिस्थिति है तो जो विषय कि इस मानयीय सदन में कई बार हो चुके हैं, जिन पर कई बार डिस्कशन हो चुका है प्रस्ताव पास हो चुके हैं चाहे बहुमत से और चाहे सर्वसम्मति से, तो फिर उन्हें ही, उन्हीं बातों को छेड़ना, उन्हीं बातों पर वाद-विवाद करना यह क्या एमरजेंसी दिखलाता है। क्या यह चीज नहीं जाहिर करती है कि इस माननीय सदन का और सार्वजनिक समय का नाश किया जा रहा है उस प्रस्ताव पर बार बार वाद-विवाद करके जिस पर कि यह माननीय सदन बहस कर चुका है?

जो लोग कम्यूनिस्ट पार्टी के विरुद्ध हैं, चाहे समय हो या न हो, वे कोई न कोई आक्षेप जरूर करना चाहते हैं,, कई न कोई चुटकी जरूर लेना चाहते हैं,। लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक चीज का समय होता है। अगर उनकी पार्टी ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया हैजिस में उन्होंने चीनी आक्रमण का विरोध किया है, चीन की निन्दा की है और अपील की है कि हमारा देश और सभी लोग मिल करके इस आक्रमण का मुकाबला करें और जो दूसरे कम्यूनिस्ट देश हैं वे भी भारतवर्ष का साथ दें, तो फिर उस सिलसिले में यह कहना कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाये, इस पार्टी को अवैधानिक घोषित कर दिया जाए, मैं नहीं समझता कि इस का कौन सा मौका है। अगर कोई प्रस्ताव नेकनियती से पास नहीं करता है, अगर उसके विरुद्ध कुछ व्यक्ति या सदस्य काम करते हैं तो उनके ख़िलाफ़

जो इस वक्त डिफ़ेंस आफ़ इंडिया रूल्ज़ हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। हमने देखा है कि कुछ को जेल भेजा गया है।

हम इस समय चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि हमारे देश का उत्पादन बढ़े। हम सुरक्षा के लिए जितना भी प्रयत्न कर सकें उतने करें। इस सिलसिले में यहां कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के मंत्रालय ने एक स्कीम तैयार की, जिस में हर पार्टी के सदस्यगण, जो इस कमेटी के सदस्य थे, बुलाये गए, और सब की सहमति से वह चीज़ तैयार हुई। उस में श्रम बैंक की व्यवस्था की गई कि हर गांव सभा में जितने लोग काम कर सकते हैं वह एक दिन का श्रम हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिए दें। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि हमारे रंगा साहब ने उस का भी विरोध किया, जब कि उनकी पार्टी के सदस्य भी उस में थे और उससे सहमत थे। म नहीं समझता कि इस में कौन सी खराबी की चीज़ है कि लोग श्रम कर के उत्पादन को बढ़ावें। लेकिन चूंकि सरकार ने उसको अपना लिया है, वह स्कीम चाल है, उस की व्यवस्था हो रही है, इसलिये उसका विरोध करना चाहिए, मैं नहीं समझता कि किस तरह से कहा जायेगा कि उन्होंने एमरजेंसी के अनुकूल यह बात कही।

दूसरी बात यह कि नानअलाइनमेंट की पालिसी हमारी बहुत अर्से से है और उसका माननीय सदन ने कितनी ही बार समर्थन किया है। इस माननीय सदन में यह चीज पास हुई है। हम ने कितनी बार इस चीज को समझाया कि अगर हम किसी गुट में जा कर शामिल हो जाते है, उस में विलीन हो जाते है, तो दूसरे जो ब्लाक हैं हम खामख्वाह उन से शत्रुता मोल लेते हैं, और यह कोई बद्धिमानी की चीज नहीं है। यह चीज बुद्धि से परे है। उस का समर्थन काफी हुआ। बहुत से राष्ट्र जो कि एक गुट बनाये हुए हैं स्वयंम् अब हमारी इस नानअलाइनमेंट की निती की प्रशंसा करते हैं। वे इस से सहमत है। वह साफ इस बात को कहते हैं कि हम यह नहीं चाहते कि भारतवर्ष अपनी इस नीति को बदले। लेकिन स्वतन्त्र पार्टी चाहती है कि नहीं, इस नीति का त्याग कर दिया जाय, यह नीति बदल दी जाय और हम पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में शामिल हो जायें। मैं समझता हूं कि यह तो वही बात हुई जैसी कि मसल कहीं जाती है कि "मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त"। एक तरफ तो दुनिया के जितने राष्ट्र हैं उन में से सभी लोग इस की प्रशंसा करते हैं और इससे सहमत हैं, दूसरी तरफ हमारे यहां स्वतंत्र पार्टी के लोग चाहते है कि हम एक गुट में विलीन हो जायें। इस के माने क्या हैं? इस के माने साफ यह होते हैं हम एक गुट में विलीन हो कर अपना अस्तित्व खो बैठें। हम किसी के हाथ की कठपुतली बन जायें। क्या इसके माने यह नहीं होते हैं? उनकी नीति जो है उस का अर्थ यही होता है, उसका नतीजा यही होता है कि हमारी स्वतंत्रता में फर्क आ जाये। इस से उस पर बट्टा लगता है और हम उसे खो बैठें। मैं समझता हूं कि जितने हमारे उत्पादन के साधन हैं, जितनी हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है, जो पार्टी उसका भी विरोध करती है, वह एक तरह से हमारी जनता की गुमराह करना चाहती है जिससे कि हम अपनी स्वतंत्रता को खो बैठें और हमारी स्वतन्त्रता चली जाय। हम किसी के हाथ की कठपुतली बन जायें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के लोग देशद्रोही नहीं कहे जा सकते? क्या वह पार्टी यह कह सकती है कि उसको अपने राष्ट्र में पूरी निष्ठा है और वह स्वतन्त्रता की वाकई हामी और मददगार है? हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वह स्वतन्त्र रहे। मेरी समझ में इस समय इन प्रश्नों को उठाना और यह कहना कि इस पार्टी को बैन कर दो या उस पार्टी की बैन कन दो, यह ठीक नहीं है। अगर यह नीति अख्तयार करनी है तो पहले स्वतन्त्र पार्टी को बैन कर देना चाहिये जो कि हमारे राष्ट्र को इस तरह से गुमराह करना चाहती है और गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है।

[श्री कु० कृ० वर्मा]

हमने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उस सिलसिले में हमारी सरकार के ऊपर आक्षेप लगाये जाते हैं। गोया राउंड टेबल कान्फ्रेंस के लिये हम बहुत ही आतुर हैं, हम चाहते हैं कि किसी तरह से राउंड टेबल कान्फ्रेंस जरूर हो और हम उस में जाकर बैठें। लेकिन विरोधी पार्टियां इस बात को भूल जाती हैं कि जो शर्तें हमने रखी थी, वह, हमारे ऊपर नेफा और लद्दाख में मेसिव अटैक होना के पहले ही रखी गई थीं, उसके पहले ही उनका ऐलान हो गया था और उसकी घोषणा कर दी गई थी कि ८ सितम्बर की लाइन जो है अगर चाइना उस को मंजूर करता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, वरना तैयार नहीं है। अब अगर कोलम्बो प्रस्ताव हुए, और वे बहुत कुछ उनसे मिलते जुलते हैं जो कि हम ने पहले घोषित कर रक्खे थे, तो उनको अस्वीकार करने के माने क्या होते हैं? क्या उसको स्वीकार न करने के माने यह नहीं होते है कि हम एक बात कहते हैं और जब मौका आता है तो उससे पीछे हट जाते हैं। यह आक्षेप क्या हमारे उपर नहीं हो सकता है? कोलम्बो प्रस्ताव, जिस पर इस सदन में काफी बहस मुबाहसा हुआ और जिसमें यह बात साफ की गई कि इस से हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, उससे कुछ मदद मिलती हैं, उस को स्वीकार करने में क्या हानि हैं? ऐसा नहीं है कि हम किसी डर की वजह से उन को स्वीकार कर रहे है। यह चीज पैदा यहां नहीं होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कहना कि हम इस के लिये आतुर हैं, सही नहीं है। बल्कि चाइना इसके लिये आतुर था, बराबर निमंत्रण हमें देता था कि आओ बात-चीत करें। हमने उसको हिकारत से ठुकराया और हम कभी इस बात के लिये राजी नहीं होंगे कि हम उसके साथ बिना उसके ८ सितम्बर वाली बात माने हुए, बिना शर्त के बात करें। कोलम्बो पावर्स में भी शायद दो-एक राष्ट्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ठीक है, बिना शर्त बात-चीत की जाय। लेकिन हम के उससे भी इन्कार कर दिया। यह चीज कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम इसके लिये आतुर हैं कि राउंड टेबल कांफ्रेंस बुलाई जाये।

हम अपनी तैयारी कर रहे है। यह कहना भी कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, गलत बात हैं। हम अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे है, अस्त्र बना रहे हैं। और अब तो यह व्यवस्था हो गई है कि हर गांव सभा में जो १८ से लेकर ४५ वर्ष तक के व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग दी जाय। दलपति वगैरह चुन लिये गये हैं, और विकास क्षेत्र के स्तर पर जो दलपति हैं, उन की ट्रेनिंग हो रही है ताकि वह जाकर दूसरों को ट्रेनिंग दें। सब लोग जानते हैं कि एन० सी० सी० के इन्स्ट्रक्टर्स के लिये भी व्यवस्था हुई है कि उनको जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग दी जाये। वे जल्दी से जल्दी भर्ती किये जायें ट्रेनिंग लेने के लिये। तो कहां पर ढीलापन है, कहां कम्प्लेसेन्सी है? कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हम सुरक्षा के लिये कोई बात नहीं कर रहे है। अगर धन की बात हो तो हम धन भी एकत्र कर रहे हैं, और भी कुछ भी हम अपने देश में कर सकते हैं वह कर रहे हैं। यह भी हम को मालूम है कि जो बाहर के विशेषज्ञ हैं बाहर के जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके भी डेलिगेशन और मिशन हम ने बुलाये हैं। ऐसी दशा में यह कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी समझ में जनता को गुमराह करना है। मैं विरोधी पार्टियों पर यह चार्ज लगाता हूं कि वह गलत बयानात को इस तरह से कह कर देश में इस किस्म का वातावरण बनाना चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार निकम्मी है। इस तरह से जनता के नैतिक स्तर को कमजोर किया जा रहा है। यह देशद्रोह है, न कि उन की देश भक्ति है और देश के प्रति निष्ठा है। मैं उनसे अपील करूंगा कि जो रचनात्मक सुझाव उनको देने हों वे उन्हें दें, और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक युद्ध काल है, आपात्काल है, तब तक उन्हें

चाहिये कि हमारी जनता के नैतिक स्तर को कमजोर न करें । इस समय देश में ऐसा वातावरण न बनायें कि सुरक्षा के लिये कोई चीज नहीं की जा रही है, या हम चीन से लड़ने के लिये तैयार नहीं है । हम चीन से लड़ने के लिये तैयार हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं । हमारी जनता को इससे संतोष है ।

इतना कहकर राष्ट्रपति जी ने जो कुछ भी अपने अभिभाषण में कहा है उस का मैं स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं ।

Shri Muthiah (Tirunelveli): Mr. Speaker, Sir, I wholeheartedly support the motion of thanks on the President's Address.

Mr. Speaker: Would the House sit longer or should we adjourn?

Shri Yashpal Singh: We should sit up to midnight; this is emergency time.

Mr. Speaker: I wanted to know the sense of the House.

Some Hon. Members: Let us adjourn.

Mr. Speaker: All right. The hon. Member may continue day-after-to-morrow. The House stands adjourned to meet again at eleven o' clock on the 27th.

18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 27, 1963|Phalguna 8, 1884 (Saka).